RNI No. : CHHHIN/2011/40280

पाक्षिक पत्रिका

छत्तीसगढ़ आजतक

वर्ष : 12 • अंक : 20 • जून - द्वितीय 2023 • मूल्य : 40/-

नक्सली क्षेत्रों में

माफिया मालामाल

बस्तर के विकास में जुटने वाली अरबों का बजट सरकारी अधिकारियों, ठेकेदारों, नक्सलियों, राजनेताओं और वन माफियाओं की जेब में जा रही विकास कार्य सिर्फ कागजों और फाइलों में मजबूत है, धरातल की कहानी कुछ और ही कहती है. घटिया निर्माण और सतही विकास तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद प्रशासनिक उदासीनता व भ्रष्टाचार की पोल खोलती है.

दुर्ग जिले की पावन धरा पर

मान. अमित शाह जी

के आगमन पर

स्वागत... वंदन... अभिनंदन

मान. अमित शाह जी

केंद्रीय गृहमंत्री

राजनीतिक परिचय

छात्र संघ

महिला महाविद्यालय भिलाई में छात्राओं ने लगातार दो बार छात्रसंघ अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी और यही से सरोज पाण्डेय ने अपनी राजनैतिक कैरियर की शुरुआत की। ये वर्ष 1989 से 1991 तक इस पद की जिम्मेदारी एक प्रखर छात्र संघ नेता के रूप में निभायी।

नगर पालिका निगम में 10 साल तक महापौर

सुश्री सरोज पाण्डेय ने दुर्ग शहर से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत नव निर्वाचित होकर लगातार दो बार महापौर पद पर दुर्ग निगम के छत्तीसगढ़ मॉडल निगम को बेहतर बनाया। उस समय की दुर्ग निगम की योजनाओं को प्रदेश के सभी निगमों ने अपनाया। सुश्री सरोज पाण्डेय देश की एकलौती महापौर रही, जो सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीतकर महापौर बनी थी।

पुनः महापौर

सर्वश्रेष्ठ महापौर का पुरुस्कार 10 वर्षों का रिकार्ड

विधायक

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-66, वैशाली नगर
(दिनांक 08.12.2008 से 31.05.2009 तक)

लोकसभा

लोकसभा क्रमांक-07 दुर्ग छत्तीसगढ़, 2009-2014
राज्यसभा सांसद - 2017 से अब तक

वर्ल्ड रिकार्ड बनाया...

सुश्री सरोज पाण्डेय ने एक ही अवधि (समय) में महापौर, विधायक व सांसद के निर्वाचित प्रतिनिधि के दायित्वों का निर्वहन हेतु लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड 2010 में अपना नाम रजिस्टर्ड कराया। सुवा नृत्य में 12 हजार प्रतिभागियों ने एक साथ नृत्य का वर्ल्ड रिकार्ड भी दर्ज करवाया।

संगठन दायित्व

- प्रवक्ता भा.ज.पा. छत्तीसगढ़ (2004 से 2008)
- राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य युवा मोर्चा
- महामंत्री भा.ज.पा. छत्तीसगढ़
- राष्ट्रीय मंत्री भा.ज.पा. (प्रथम 2008 से 2009)
- पुनः राष्ट्रीय मंत्री भा.ज.पा. (2009 से 2012)
- राष्ट्रीय अध्यक्ष भा.ज.पा. महिला मोर्चा (2012 से 2014)
- राष्ट्रीय महामंत्री भा.ज.पा. (2014 से 2019)

निरंतर कर्म, यही मेरा धर्म

डॉ. सुश्री सरोज पांडेय जी

राज्यसभा सांसद

डॉ. सुश्री सरोज पांडेय जी को

जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं...

विनीत : समस्त भाजपा कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ प्रदेश

Website : www.chhattisgarhaajtak.com
E-Mail : cg.aajtak@gmail.com

पाक्षिक पत्रिका

छत्तीसगढ़ आजतक

वर्ष : 12 ● अंक : 20 ● जून - द्वितीय 2023

संपादक	:	लखन लाल
सलाहकार संपादक	:	सादात अनवर
कार्यकारी संपादक	:	दीपक रंजन दास
विशेष प्रतिनिधि	:	मंजुला कौशिक, आर.के. वर्मा
	:	विक्रम जनबंधु
कानूनी सलाहकार	:	गिरीशचंद्र शर्मा
प्रबंध संपादक	:	डॉ. डी.पी. देशमुख
सरगुजा प्रभारी	:	अमरेश्वर दुबे
फोटो जर्नलिस्ट	:	पी. मोहन

प्रतिनिधि :-

रायपुर	:	भूपेन्द्र वर्मा
दुर्ग	:	रामशरण कौशिक
भिलाई	:	सतीशदास वैष्णव
भिलाई - 3	:	श्यामलाल साहू
राजनांदगांव	:	राहुल गौतम
कबीरधाम	:	सुरेश प्रसाद गुप्ता
कोरबा	:	अजय कुमार
जांजगीर-चांपा	:	समयदास अविनाशी
कटघोरा	:	विकास जायसवाल
कोण्डागांव	:	सुरेश पाटले
नारायणपुर	:	नरेन्द्र देवांगन
जगदलपुर	:	हेमंत कश्यप
धमतरी	:	जियाऊल हुसैनी
बालोद	:	सलीम चौहान
बलौदाबाजार	:	संतोष यादव
महासमुंद	:	मनोज गोयल
बोड़ला	:	नवलकिशोर श्रीवास्तव
अंबिकापुर	:	धनंजय दुबे
मनेन्द्रगढ़	:	मनप्रीत सिंह साहनी
रामानुजगंज	:	विकास केसरी
वाड्रफनगर	:	प्रदीप जायसवाल
दल्लीराजहरा	:	झुनमुन गुप्ता
गुंडरदेही	:	रमेश चांडक
पाटन	:	उमाशंकर वर्मा
उतई	:	सतीश पारख
बलरामपुर	:	नितेश श्रीवास्तव
दंतेवाड़ा	:	देवकरण बुरड
बिलासपुर	:	सत्येन्द्र प्रकाश सूर्यवंशी

संपादकीय, विज्ञापन, प्रसार कार्यालय

ब्लॉक बी-1, प्रथम तल, बॉम्बे मार्केट, रायपुर (छ.ग.)
भिलाई कार्यालय : जी.ई. रोड, कोसानगर, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
संपर्क : 99261 80287, 88895 70726

प्रसार व विज्ञापन विभाग

पत्रिका की सदस्यता व विज्ञापन के लिए संपर्क करें
भूपेन्द्र वर्मा-8889570726, गजेन्द्र-7999139990,
दिनेश यादव-6264374105

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- लखन लाल के लिए सागर प्रिंटर्स, पुरानी बस्ती, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं ब्लॉक बी-1 प्रथम तल, बॉम्बे मार्केट, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित, **संपादक - लखन लाल**

सर्वाधिक सुरक्षित : किसी भी रूप से सामग्री की नकल प्रतिबंधित है. सभी विवादों का निपटारा रायपुर न्यायालय में होगा.

08

आवरण - कथा

माफिया मालामाल

बस्तर के विकास में जुटने वाली अरबों का बजट सरकारी अधिकारियों, ठेकेदारों, नक्सलियों, राजनेताओं और वन माफियाओं की जेब में जा रही है. विकास कार्य सिर्फ कागजों और फाइलों में मजबूत है. धरातल की कहानी कुछ और ही कहती है. घटिया निर्माण और सतही विकास तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद प्रशासनिक उदासीनता व भ्रष्टाचार की पोल खोलती है, पढ़िये एक रिपोर्ट...

04

महासंग्राम...

छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा की चुनावी सक्रियता से राजनीतिक माहौल गरमा गया है. यद्यपि विधानसभा चुनाव अभी लगभग 6 माह दूर है, लेकिन दोनों दलों में जिस प्रकार...

30

महंगाई : पूछे नौ सवाल...

छत्तीसगढ़ में भाजपा लगातार चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है. इसमें सबसे बड़ा मुद्दा शराबबंदी का है. पर इधर देश के कई राज्यों में केन्द्र सरकार के खिलाफ...

06	हिंसा	:	मणिपुर को कश्मीर में बदलने की साजिश...
14	समस्या	:	बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन ?...
20	तकरार	:	द केरला स्टोरी में दिखाया आधा सच...
26	भ्रष्टाचार	:	गौण खनिज में शासन को लग रहा...
48	श्रद्धांजलि	:	सार्वजनिक जीवन का अर्धशतक : विद्यारतन...

लखन लाल

कौन होगा छत्तीसगढ़ का खेवनहार ?

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी शंखनाद हो चुका है. चुनाव नवंबर महीने में होना है. इसके लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जोरों पर है. इस दौरान जनमानस में यह सवाल उभर रहा है, कि आखिर छत्तीसगढ़ का खेवनहार कौन होगा? कांग्रेस का चेहरा तो फिलहाल भूपेश बघेल ही है लेकिन भाजपा का चेहरा कौन होगा, यह अभी तक पार्टी ने घोषित नहीं किया है. जनापेक्षा है कि खुशहाली, उन्नति और नक्सली आतंक से मुक्त कराकर छत्तीसगढ़ को वास्तव में शांति के टापू की ओर ले जाए. इस उम्मीद पर खरा उतरने कांग्रेस और भाजपा दोनों की राजनीति उफान पर है. भाजपा का दावा है कि कांग्रेस राज में पार्टी शराबबंदी तो नहीं करवा सकी लेकिन भाजपा भी अपने 15 साल के शासन में शराब बंदी के मामले में विफल रही. इस मुद्दे को लेकर भाजपा चुनावी वैतरणी कदापि पार नहीं कर सकती. इसके अलावा भाजपा के पास धर्मांतरण और सांप्रदायिकता जैसे मुद्दे ही रह गए हैं जो कर्नाटक में औंधे मुँह गिर पड़े. कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में पिछले पाँच साल में जो काम किए हैं, उसी आधार पर वोट मांगने की रणनीति पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चल रहे हैं. लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर वोट मांगने जनता के बीच जाएगी? यह अहम मुद्दा है.

जैसे-जैसे छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक आ रहा है भाजपा तरस रही है कि किस चेहरे को सामने लाकर वह कमल खिला सके. निश्चित ही भाजपा के पास कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैसा कोई तेज-तर्रार, आक्रामक व ताकतवर नेता नहीं है. पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह पर पुन: भाजपा अपना दॉव लगाए यह भी यक्ष प्रश्न है. उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की छवि निखर सके. इसके साथ-साथ भाजपा को मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर भी जनता के बीच जाना है. इन सबके बरअक्स भाजपा की हालत देशभर में लगातार खराब होती जा रही है. सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब मोदी का चेहरा दिखाकर चुनाव नहीं जीते जा सकते. अब तो आरएसएस ने भी ऐसा ऐलान कर दिया है. ऐसे में निश्चित तौर पर भाजपा को सत्ता में वापसी के लिए किसी स्थानीय चेहरे की तलाश होगी. डॉ. रमन सिंह के लगातार 3 बार सीएम रहने के बावजूद उनकी फेस वैल्यू पहले जैसे नहीं रही. ऐसी स्थिति में संभव है कि भाजपा ऐन चुनाव के पूर्व किसी ऐसा कद्दावर चेहरा ला सकती है, जो स्थानीय होने के साथ लंबा राजनीतिक अनुभव रखता हो, साथ ही प्रदेश के लिए जाना-पहचाना चेहरा भी हो. यदि भाजपा की इस तरह की रणनीतिक समझ बनती है तो वह कांग्रेस के आक्रामक और चिरपरिचित भूपेश बघेल का मुकाबला संभवत: कर सके.

विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों और समस्याओं को लेकर जीते-जाते हैं, जैसा कि कनार्टक में हुआ. अब छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में भी यही दोहराया जाएगा. कांग्रेस और भाजपा इस चुनावों में अभी से एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप गढ़ने में लग गए हैं. यह तल्ख स्वर चुनाव में आगे चलकर और आक्रामक ढंग से मुखर होंगे, यह भी अभी से दिखाई पड़ने लगा है. एक पुरानी कहावत है कि पैरा देखकर पता चल जाता है कि गांव में कितना धान हुआ है, यह कहावत भाजपा पर हू-ब-हू लागू होती है. भाजपा के हर बड़े नेता कार्यकर्ताओं को हर बूथ में माहौल बनाने की समझाइश दे रहे हैं. भाजपा पूरी ताकत और रणनीति के तहत चुनावी समर में उतरती है और उसकी संगठनात्मक शक्ति भी दिखाई देती हैं.

कांग्रेस हो या भाजपा हर विधानसभा में विधायकों की पर्सनल छवि भी महत्वपूर्ण होती है. इसी आधार पर विधानसभा और लोकसभा की सीटें मुकर्रर होती हैं. भूपेश बघेल ने यद्यपि अब तक किसी विधायक पर अंगुली नहीं उठाई है, पर जहां कुछ विधायकों की स्थिति कमजोर है वहां उनसे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए अवश्य कहा गया है.

दरअसल, पर्दे के पीछे की कूटनीति हमेशा बहुत ही भयावह होती है. आम आदमी यह समझ ही नहीं पाता कि क्या हो गया है, उसे तभी समझ में आता है जब राजनीति में छलने की कवायद पूरी हो जाती है. वास्तव में अच्छे काम करती हुई सरकार भी जब अपने मतदाता के पास जाती है तो वह भी भौंचक रह जाती है कि जिसने जनमानस के दुख-दर्द में झाँका तक नहीं, वह विधायक प्रत्याशी जीत जाता है. हालांकि कांग्रेस के सामने ऐसी कोई नौबत नहीं है अलबत्ता भाजपा के सामने ऐसे बुर्कानोश लोगों की लाइन लगी है. संगठन और सत्ता सुंदरी का मोह लिए कई ऐसे लोग भी हैं, जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आने को लालायित है. क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों का इन दिनों बोलबाला है, जो देशभर में भाजपा की हालत पतली बता रहें हैं. यदि मोदी का चेहरा तक सामने नहीं लाना चाहते तो फिर भाजपा आखिर करेगी क्या? केंद्र और कुछ राज्यों से भाजपा की सरकार जाने के बाद भाजपा और उसके नेताओं को स्थानीय मुद्दे तलाशने होंगे. जिससे वे मतदाताओं को रिझा सकें. दरअसल भाजपा राजनीति के कारखाने में ऐसे मुद्दे बना रही है, जिससे वह विधानसभा और लोकसभा में ऐसे महापुरूष पा सके जो उसे केंद्र में सरकार बनाने में मददगार हो. बहरहाल कांग्रेस और विपक्षी एकता कैसी आकृति लेती है, वह कितनी भरोसेमंद है, यह तो भविष्य ही बताएगा.

सिंहदेव बने डिप्टी सीएम

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सरगुजा राज परिवार के राजा टी.एस. सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उपमुख्यमंत्री बना दिया गया. यह घोषणा कांग्रेस के राष्ट्रीय आलाकमान ने की है. यह पद राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ में पहली बार निर्मित किया गया है. कांग्रेस के सत्ता-संगठन को यह उम्मीद है कि चुनाव से चार माह पूर्व संगठन में फूट की जो आशंका थी उसे रोकने में मदद मिलेगी. इससे असंतुष्टों के स्वर कम होंगे. ज्ञात हो कि वर्ष 2021 से ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री का जो विवाद चल रहा था उस विवाद का पटाक्षेप हो गया है. आलाकमान की इस घोषणा से प्रदेश कांग्रेस को नई ताकत मिलेगी. नई नियुक्ति के बाद टी.एस. बाबा ने कहा है कि सत्ता में उन्हें नई जिम्मेदारी और सम्मान मिली है इसके लिए उन्होंने आलाकमान को धन्यवाद दिया है. साथ ही उन्होंने अपनी नई जिम्मेदारियों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे. वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टी.एस. बाबा को ट्विट कर बधाई और शुभाकामनाएं दी है.

नंदकुमार साय बने CSIDC के अध्यक्ष

भाजपा से कांग्रेस में शमिल हुए आदिवासी नेता नंदकुमार साय को छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया है. श्री साय को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है. नियुक्ति पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री साय को ट्वीट कर बधाई और शुभकामनाएं दी. नंद कुमार साय को सरगुजा क्षेत्र के कद्दावर आदिवासी नेता के रूप में जाना जाता है. श्री साय अविभाजित मध्यप्रदेश में पहली बार 1977 में तपकरा सीट से जनता पार्टी के विधायक चुने गये. 1980 में उन्हें बीजेपी का रायगढ़ जिला इकाई प्रमुख बनाया गया. 1985 में तपकरा से दोबारा बीजेपी विधायक

केबिनेट मंत्री का दर्जा

चुने गए. इसके बाद 1989-1996 और 2004 में रायगढ़ से लोकसभा सदस्य और 2009-2010 में राज्यसभा सदस्य चुने गए. श्री साय 2003 से 2005 तक छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष और इससे पहले 1997 से 2000 तक मध्यप्रदेश बीजेपी प्रमुख रहे.

नवंबर 2000 में मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद वे छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता बने. श्री साय को 2017 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन सी एस टी) का अध्यक्ष बनाया गया. कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद नंदकुमार साय को महज ढाई माह के अंतराल में भूपेश मंत्री मंडल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया.

आरोप और उपलब्धियों का महासंग्राम

संगठन स्तर पर भाजपा ने ली लीड

सत्ता को उपलब्धियों पर भरोसा

छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा की चुनावी सक्रियता से राजनीतिक माहौल गरमा गया है. यद्यपि विधानसभा चुनाव अभी लगभग 6 माह दूर है, लेकिन दोनों दलों में जिस प्रकार ताबड़तोड़ कार्यक्रम हो रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि चुनावी दंगल शुरू हो गया है. दोनों पार्टियां ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तरीय सम्मेलन, कार्यकर्ताओं की बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम और छोटी-बड़ी रैलियां और प्रदर्शन कर रही हैं. इसे देखकर ऐसा लगता है 'बूथ मजबूत तो जीत पक्की' की भावना और संकल्प के साथ दोनों पार्टियों के नेता और संगठन प्रतिनिधि पूरी शिद्दत से जुट गए हैं.

हर वर्ग को मिला विकास का लाभ- भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ में दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनेगी. इसकी वजह जनाकांक्षा के अनुरूप चौतरफा विकासा हुआ है. सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से किसानों, महिलाओं, मजदूर और युवाओं आदि हर वर्ग को लाभ हुआ है. छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति को भी बढ़ाने का काम किया है. शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण इलाकों में हुए सर्वांगीण विकास का भरपूर लाभ हर तबके को मिला है. हमारे इन कार्यों से जनता खुश है, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनेगी.

● **भूपेश बघेल**, मुख्यमंत्री

» सुरेश प्रसाद गुप्ता

प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल लगातार प्रदेश के कोने-कोने में दौरा कर जनता की भावनाओं का आकलन कर रहे हैं. इन बैठकों में वे किसान, मजदूर और जनहित में किए जा रहे तमाम कार्यों और उपलब्धियों के साथ ही चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा कर रहे हैं. लेकिन कांग्रेस का संगठन भाजपा की तुलना में सक्रियता और क्षमता के मुकाबले कमजोर दिखाई दे रहा है. छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए भाजपा का संगठन ऊपर से नीचे तक सक्रिय हो गया है.

राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि पिछले वर्षों में भाजपा ने वो संघर्ष और सक्रियता नहीं दिखायी जो एक सशक्त विपक्ष को दिखाना चाहिए था. जनता के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता भी ऐसी सक्रियता की अपेक्षा करते हैं. देर से ही सही पर छत्तीसगढ़ भाजपा में ताबड़तोड़ नेतृत्व परिवर्तन हुआ और इसके बाद काफी सक्रियता आई है. पार्टी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है. जातीय और धार्मिक आधार पर भी भाजपा नेता सभी क्षेत्रों में गोलबंदी का प्रयास कर रहे हैं. इस मामले

छत्तीसगढ़ की सरकार में घोटाले ही घोटाले- बृजमोहन

छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी. छत्तीसगढ़ में जो भी विकास हुआ है मोदी सरकार और भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में हुआ है. कांग्रेस के साढ़े चार साल के शासनकाल में तो घोटाले ही घोटाले हुये हैं. इस दौरान पीएससी घोटाला के साथ रेत, धान, व्यापम जैसे कई बड़े घोटाले हुए. यदि केंद्र सरकार चावल लेना बंद कर दे तो छत्तीसगढ़ सरकार क्या किसानों की धान खरीद पाएगी.

● **बृजमोहन अग्रवाल,** पूर्व मंत्री

में कांग्रेस संगठन की उदासीनता एवं प्रशासनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण कई मामलों में भाजपा को घुसपैठ बनाने का अवसर भी मिला है. इसी कड़ी में रतनपुर और नारायणपुर की घटनाएं उल्लेखनीय है.

छत्तीसगढ़ में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में भी नई चेतना और प्रगति लाने के लिए मुख्यमंत्री की छवि एक बेजोड़ छत्तीसगढ़िया नेता के रूप में स्थापित हुई है. इन प्रयासों में किसानों और असंगठित मजदूरों तक सीधे आर्थिक लाभ पहुंचाना, आदि शामिल है. मुख्यमंत्री यदि कांग्रेस संगठन को एकजुट और सक्रिय कर राज्य सरकार के जनहित कार्यों को लेकर जनता के बीच पहुंचे तो वह भाजपा के दुष्प्रचार का मुँहतोड़ जवाब दे सकते हैं. इससे भाजपा को आसन्न चुनावों में पीछे छोड़ने का कार्य आसान हो सकता है. वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि अन्य किसी भी नेता की तुलना में प्रदेश में अधिक प्रभावशाली है. पर राज्य के मंत्रियों, विधायकों और संगठन के प्रभारियों को भी यह ध्यान रखना होगा कि अकेले मुख्यमंत्री का नाम लेकर चुनाव की वैतरणी पार नहीं की जा सकती. अभी हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की छवि को लेकर मैदान में उतरी भाजपा का क्या हश्र हुआ यह सबके सामने है. कांग्रेस नेताओं को भी कर्नाटक से सीख लेनी चाहिए.

फिलहाल राज्य के तमाम मंत्रियों से पार्टी कार्यकर्ता खुश नहीं है. कार्यकर्ताओं को सत्ता और संगठन से अपेक्षित सहयोग न मिलने की शिकायतें भी जगह-जगह देखने को मिली है. संभाग स्तर पर बात करें तो बस्तर संभाग में सांसद दीपक बैज और मंत्री कवासी लखमा की सक्रियता और लोकप्रियता बरकरार दिखती है. लेकिन अन्य विधायकों और संगठन पदाधिकारियों को अपनी छवि सुधारनी होगी. इसी प्रकार दुर्ग संभाग में भी जहां मुख्यमंत्री का अपना गृह क्षेत्र भी है, संगठन के स्तर पर और मजबूती तथा सक्रियता की जरूरत है. क्षेत्रीय मंत्रियों को भी सिर्फ अपनी विधानसभा तक ही सीमित और सक्रिय रहने की बजाय प्रदेश स्तर पर सक्रिय होने की जरूरत है. इस संभाग से मुख्यमंत्री के अतिरिक्त 5 मंत्री प्रदेश मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं. इनसे कार्यकर्ताओं और आमजनता को काफी अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन स्थिति इसके विपरीत ही दिखाई दे रही है. इस संदर्भ में रायपुर संभाग की स्थिति कुछ बेहतर है. यद्यपि बिलासपुर और सरगुजा के संभागीय सम्मेलनों में कांग्रेस ने अपनी एकजुटता दिखाकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा है और इसका सकारात्मक संदेश आम जनता के बीच भी गया है. इस दौरान रायगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय रामायण मेला के सफल आयोजन ने न केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार को भी नई चमक प्रदान की है. इस आयोजन से इस क्षेत्र की जनता में कांग्रेस सरकार के प्रति आकर्षण और विश्वास का भाव देखने को मिल रहा है. वैसे फौरी तौर पर देखा जाए तो अकेले मुख्यमंत्री ही संगठित और आक्रामक भाजपा के सामने पूरे दम-खम के साथ खड़े दिखाई देते हैं. यदि मंत्रिमंडल के सहयोगी और संगठन के पदाधिकारी भी अपनी पूरी क्षमता के साथ मैदान में उतरें तो निश्चित ही कांग्रेस को सफलता मिलेगी.

छत्तीसगढ़ की राजनीति में आम आदमी पार्टी (आप) सर्व आदिवासी समाज और जोगी कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं. पिछले चुनाव में जोगी कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति दर्ज करायी थी लेकिन इसके मुखिया अजीत जोगी के देहावसान के बाद पार्टी अस्तित्वहीन हो गई. आज जोगी कांग्रेस के विधायक कांग्रेस व भाजपा में जगह तलाश रहे हैं. आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की राजनीति में नया-नया प्रवेश किया है लेकिन जमीनी स्तर पर उसका प्रभाव न के बराबर है. यही स्थिति सर्वआदिवासी समाज की है. अरविंद नेताम जैसे कालातीत हुए नेताओं के सहारे यह संगठन आदिवासी समाज को आकर्षित करने में शायद ही सफल हो. वैसे नक्सली वारदातों पर नियंत्रण, तेंदूपत्ता संग्राहकों को अच्छा पारिश्रमिक और लगभग समस्त वनोपज की खरीदी के साथ ही मिलेट्स उत्पादन को प्रोत्साहन देकर भूपेश सरकार ने आदिवासी-वनवासी समुदाय के बीच अपनी गहरी पैठ बना ली है. इसका लाभ कांग्रेस को मिलने की प्रबल संभावना है. प्रदेश में कोई भी तीसरी राजनैतिक शक्ति नहीं दिखाई देती जो विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सके. असल जोर आजमाइश कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होनी है.

मणिपुर को कश्मीर में बदलने की साजिश

मणिपुर और केंद्र में डबल इंजन की भाजपा सरकार है. बावजूद मणिपुर की हालात अभी नियंत्रण से बाहर है. यहां पर जो हिंसा हुई है वह देशभर में चर्चा का विषय है. मणिपुर की घटना में मैतई हिंदू बहुसंख्यक वर्ग और आदिवासी ईसाई अल्पसंख्यक वर्ग के बीच टकराव और वर्ग संघर्ष चिंताजनक है. बीते दो माह में मणिपुर हिंसा में 120 से ज्यादा लोगों की जानें जा चूकी है और हजारों को बेघरबार होना पड़ा है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के लिए बड़ी चुनौती भी है. चालीस से पचास लाख की जनसंख्या वाला छोटा सा प्रदेश है मणिपुर. जो इन दिनों राजनीतिक हथकंडों का शिकार है. स्थिति इतनी गंभीर है कि तनाव को यदि तत्काल नहीं सम्हाला गया तो तस्वीर और गंभीर हो सकती है. इसका असर पूरे देश में पड़ेगा. यहां पर यह बताना भी जरूरी है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और बजरंग दल के ऑपरेशन मणिपुर में लंबे समय से चल रहे हैं. इस राज्य में बहुसंख्यकों को तवज्जों और आदिवासियों के खिलाफ नफरत बोने की राजनीति के तहत साजिश की जा रही है. मणिपुर की हिंसा प्रायोजित है. जो हत्याएं हुई हैं वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है. लगातार एक गुट को भड़काना और तनाव पैदा करना नफरत की राजनीति नहीं तो और क्या है? सैकड़ों चर्च और मंदिर तोड़ दिए गए. कई घरों में आग लगा दी गई. कितनी जानें चली गई. दरअसल, हिंसक ताकतों का इस्तेमाल भाजपा अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत कर रही है. ऐसा विपक्षी पार्टियां कह रही हैं. आरोप यह भी है कि राजनीतिक एजेंडे के तहत दो धर्मों को आपस में लड़ाने की हो रही है. ऐसा तब हो रहा जब देश में पाँच महीने बाद पाँच विधानसभा और दस महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने है.

» **विक्रम जनबंधु**

मणिपुर जल रहा है. यह बड़ी हैरत की बात है कि वहां सत्तारूढ़ भाजपा के मंत्रियों के ही घर जलाए जा रहे हैं. यह लोगों का गुस्सा ही है अथवा कोई और बात यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है. यद्यपि जातीय हिंसा कुकी और क्षेत्रिय जाति के बीच भड़की हैं. कोर्ट द्वारा आदिवासी समुदाय को आरक्षण दिए जाने के बाद हिंसा 3 मई को भड़क उठी थी जो आज 50 दिन बाद भी शांत नहीं हो पाई है. स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थान और इंटरनेट सुविधाएं बंद पड़ी है. कुछ लोगों का मानना है कि जनता की अंतरविरोधी धार्मिक सम्प्रदायिकता को उन्माद में बदलने की साजिश हो रही है. आरोप है कि यह सब कोई और नहीं बल्कि खुद केंद्र सरकार कर रही है. मणिपुर के सेवानिवृत्त अफसर खुलेआम यह आरोप केंद्र पर लगा रहे हैं कि यदि हिंसा 24 घंटे से ज्यादा जारी रहती है तो वह सरकार की सहमति के बिना नहीं हो सकती.

चुप क्यों हैं प्रधानमंत्री?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में आग से खेल रहे हैं, जो उनके लिए आगे चलकर नुकसान देह साबित हो सकता है. यह बात दिल्ली के जंतर-मंतर पर 25 जून को न्याय और शांति की मांग कर रहे एक मणिपुरी नागरिक ने कही. क्या यह राज्य प्रायोजित है? मणिपुर की सीमाएं उत्तर में नगालैंड से, दक्षिण में मिजोरम से, पश्चिम में असम से तथा पूर्व में म्यांमार से लगी हैं. म्यांमार वही देश है जहां से भगाए गए रोहिंग्या भारत में घुसपैठ कर रहे हैं. आज अमेरिका के लोग, वहां के पत्रकार, यहां तक कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पूछ रहे हैं कि भारत में जाति हिंसा क्यों बढ़ी है? मोदी गोलमोल जवाब देते हैं. कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की मांग है कि कि वहां शांति बहाल होनी चाहिए. वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह से मणिपुर नहीं संभल रहा है. कांग्रेस और कुछ अन्य दलों ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है. राज्य में 3 मई से छुटपुट हिंसा शुरू हो गई थी, लेकिन बीरेन सिंह इसे रोकने में नाकाम रहे. प्रदेश में हिंसा भड़कने से 120 लोगों की जान चली गई और 3000 से अधिक लोग घायल हो गए.

मणिपुर को लेकर सियासत अब गरमा गई है. हिंसा के पीड़ितों का दर्द बाँटने सड़क मार्ग से राज्य के विष्णुपर जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पुलिस ने रोक दिया. शासन द्वारा इसकी वजह उनकी सुरक्षा और हिंसा भड़क जाना बताया गया. वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस कदम को अलोकतांत्रिक बताया है. सड़क मार्ग से रोके जाने पर राहुल हेलिकॉप्टर से चुराचाँदपुर पहुंचें और राहत शिवरों में विस्थापितो से मिलकर मदद का भरोसा दिलाया.

कार्पोरेट को घुसाने का षड्यंत्र

मणिपुर जैसे छोटे और शांत प्रदेश को अंबानी, अडानी और दूसरे बड़े कार्पोरेट सेक्टर को देने की साजिश की जा रही है ताकि वहां के संसाधनों का भरपूर दोहन हो सके. मणिपुर के लोगों की लड़ाई यहां से शुरू होती है. उन्हें तो यह पता भी नहीं है कि कार्पोरेट किस अंधगति से जल, जंगल और जमीन और पर्वतों का दोहन करने वाले हैं. यह आजतक नहीं कह रहा बल्कि मणिपुर का बुद्धिजीवी समुदाय, उनके शिक्षक, लेखक, कवि और वकील कह रहे हैं. केन्द्र के लिए यह अवसर मणिपुर में दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, अमीर-गरीब एवं जातियों के बीच वैमनस्यता फैलाने का अमृत काल सिद्ध हो रहा है

शांति के लिए गुहार

मणिपुर में लोकतांत्रिक मूल्य खत्म हो रहे हैं. वहां की जनता सीधा-साधा, सरल जीवन चाहती हैं. आदिवासी कुकी जाति के लोग जल, जंगल, और जमीन सहित पर्वत पर अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार की सोच कुछ और ही साजिश कर रही हैं.

धर्म के साथ खिलवाड़

धर्म के साथ खिलवाड़ का भयावह तांडव मणिपुर में खेला जा रहा है. देश के अन्य हिस्सों में हिंदू- मुस्लिम के बीच वैमनस्यता फैलाकर खून की नदियां बहाई गईं. मणिपुर एक अकेला ऐसा राज्य है जहां ईसाई-हिंदू के बीच ना बुझने वाली भयानक भड़काई जा रही है. एक ताजा समाचार के अनुसार मणिपुर में अब तक 400 चर्चों को फूंका जा चुका है. यहां केंद्र का अपना निजी स्वार्थ धधक रहा है. पहला स्वार्थ तो यह है कि धर्म को साम्प्रदायिकता में तब्दील किया जा रहा है. दूसरा स्वार्थ लोकतांत्रिक मूल्य जाएं भाड़ में उन्हें तो किसी तरह सत्ता में बने रहना है.

जहर की खेती कर रहे मोदी

मणिपुर में कुकी और मेतेई जातियों के बीच झगड़ा है. लेकिन इस हिंसा को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति स्थापना का एक शब्द भी नहीं बोला. गृहमंत्री अमित शाह वहां बैठकें जरूर कर रहे हैं. उन्होंने 15 दिनों में शांति बहाल करने का दावा भी किया था लेकिन दूसरे दिन भी फिर हिंसा भड़क उठी. वे कौन से विपक्षी दलों के साथ बैठकें करते हैं यह तो वही जानें.

इंडिया ईसाइयों के रहने लायक नहीं

एक पीड़ित ईसाई ने बताया कि हम यूएन में जाना चाहते हैं. हम उन्हें बताएंगे कि हम मणिपुर में रहते हैं. मणिपुर इंडिया में हैं. इंडिया ईसाइयों के रहने लायक नहीं हैं. मणिपुर में 400 चर्चों को जला दिया गया. सरकार चाहती तो इस हिंसा को रोक सकती थी. लेकिन मोदी ने शांति के लिए एक शब्द नहीं बोला. इससे लगता है कि यह सब प्रायोजित था. लोग डरे हुए हैं. हम सब शांति चाहते हैं आज की हालत यह है कि पीड़ित राहत कैंपों में रहने को मजबूर हैं. सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है. पानी की बोतलें काटकर लोग दाल पी रहे हैं. डबल इंजन सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे सकी.

मुख्य बिन्दु

मणिपुर को जलता हुआ छोड़कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका और मिस्र की यात्रा पर निकल गए. इससे कई सवाल खड़े हो जाते हैं. ताज्जुब की बात तो यह है कि मोदी भले ही भारत में चुप रहते हैं पर विदेश जाकर खूब बोलते हैं, भले ही जवाब गोलमोल देते हों.

भारत अमेरीकी हथियारों का बड़ा खरीददार है. बाइडन की नजर अमेरिका में रह रहे 30 से 40 लाख भारतीय वोटरों पर भी है. अमेरिका का लक्ष्य चीन से मुकाबले के लिए भारत को मोहरे के रूप में खड़ा करना भी हो सकता है. 35 करोड़ आबादी वाले अमेरिका में 40 लाख वोटों का लालच कोई कैसे छोड़ सकता है?

भारत के भीतर और देश के बाहर मोदी के इमेज में बहुत अंतर है. बेरोजगारी, साम्प्रदायिकता और पूर्वोत्तर में जातीय हिंसा जैसे मुद्दे अपने विकराल रूप में खड़े हैं. बावजूद इसके अगर अमेरिका भारत को यह सम्मान दे रहा है तो इसके पीछे उसका अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि है.

बस्तर-सरगुजा में

नक्सली क्षेत्रों में

माफिया मालामाल

बस्तर के विकास में जुटने वाली अरबों का बजट सरकारी अधिकारियों, ठेकेदारों, नक्सलियों, राजनेताओं और वन माफियाओं की जेब में जा रही है. विकास कार्य सिर्फ कागजों और फाइलों में मजबूत है. धरातल की कहानी कुछ और ही कहती है. घटिया निर्माण और सतही विकास तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद प्रशासनिक उदासीनता व भ्रष्टाचार की पोल खोलती है, पढ़िये एक रिपोर्ट...

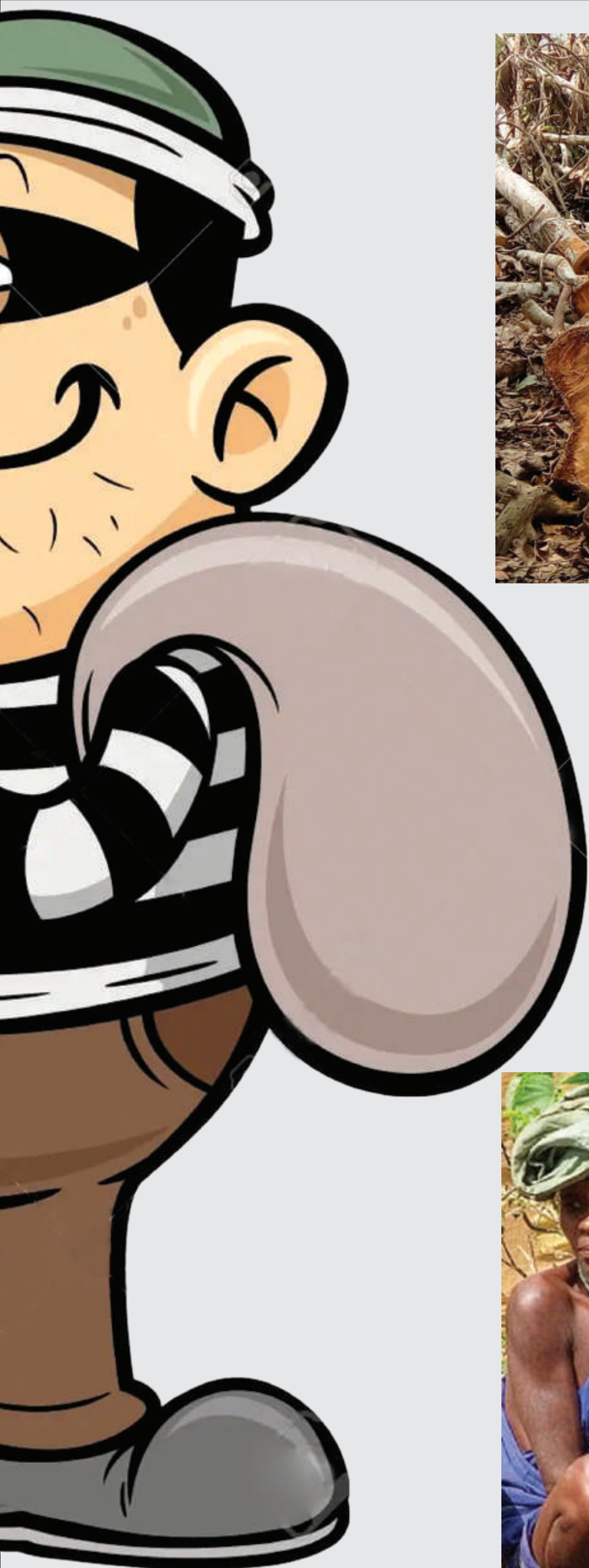

खदान हो या इस्पात संयंत्र किसी का नहीं मिला लाभ

बाहरी ठेकेदार भी कर रहे शोषण, कोई सुनवाई नहीं

» लखन वर्मा

छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में हो रहे विकास कार्यों से बाहरी लोग तो खूब मालामाल हुए पर बस्तरिहा और सरगुजिहा के हाथ खाली के खाली रह गए. बस्तरिहा को न तो खदानों या इस्पात संयंत्रों में काम मिल पाया और न ही विकास का कोई सीधा लाभ. सरगुजा के किसान तो अपने ही खेतों में मजदूर बन गए. कभी लाल गलियारे में शामिल इन दोनों आदिवासी बहुल अंचलों पर अब बाहरी ठेकेदारों और एजेंसियों का कब्जा है. स्थानीय युवाओं को नौकरी दिलाने की सरकार की छोटी कोशिश पर उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया. उधर ठेकेदार न केवल करोड़ों में खेल रहे हैं बल्कि नेताओं के साथ ही इन इलाकों की नक्सली गतिविधियों को भी फायनेंस कर रहे हैं.

सुरक्षा बलों ने हथियारबंद माओवादियों को पहाड़ियों तक सीमित तो कर दिया है किन्तु नक्सलवाद की आड़ में नए माफियाओं का खेल शुरू हो गया है. यह माफिया है निर्माण एजेंसियों के ठेकेदार और लकड़ी तस्करों का. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए एसडब्ल्यूई योजनांतर्गत कई प्रोजेक्ट लांच किये जाते हैं. निर्माण एजेंसियां भी तय होती हैं. इन एजेंसियों की आड़ में बाहरी संदिग्ध लोग बस्तर में घुस आते हैं. ये न केवल गुणवत्ताविहीन काम कर रहे हैं बल्कि सरकारी खजाने पर डाका डाल भी रहे हैं.

स्थापना खर्च बचाने के लिए 50-60 हजार वेतन वाले इंजीनियरों की जगह पड़ोसी राज्यों के दसवीं-बारहवीं पास युवाओं को 10-12 हजार मासिक वेतन पर रखा जाता है. इनके पास डिग्री-डिप्लोमा तो नहीं है पर ये लोग जोखिम वाले क्षेत्र में 10-12 हजार रुपए की तनख्वाह पर काम करने को तैयार हो जाते हैं.

निगरानी एजेंसियां (पीडब्ल्यूडी, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ए.डी.बी. प्रोजेक्ट, एन.एच.) कार्य की गुणवत्ता की तरफ से आंखें बंद किए हुए हैं. वैसे भी सरकारी एजेंसियों में ज्यादातर इंजीनियर मैदानी एवं शहरी क्षेत्रों में पदस्थ हैं, यहां अमले की भारी कमी है. ऐसे में गुणवत्तापूर्ण निर्माण की मानीटरिंग कैसे हो? जंगलों में गुणवत्ताविहीन सड़कों, पुल-पुलियों का निर्माण कर ठेकेदार चाँदी काट रहे हैं. जब जंगल में कदम पड़ ही गए तो ये एजेंसियां साल-सागौन की तस्करी का नया व्यापार भी शुरू कर लेते हैं.

बताते हैं कि यहां अन्य राज्यों के ब्लैक लिस्टेड और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने पैर जमा लिए हैं. सवाल उठता है कि ये नक्सलगढ़ में कोई खतरा क्यों नहीं महसूस करते? जवाब है नेताओं, अफसरों एवं ठेकेदारों का त्रिकोणीय गठजोड़. इक्कीसवीं सदी में बढ़ते चुनावी खर्चों की मजबूरी के साथ ही अकूत धन कूटने की प्रवृत्ति भी बढ़ी. उगाही के तरीके बदल गये. सरकारी ठेके हासिल कर बेहिसाब मुनाफा कमाया जा रहा है. इसमें नेता-अफसर और ठेकेदार सबका हिस्सा होता है. अब अगर नक्सलियों से भी सांठगांठ कर ली जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है. इसलिए ऐसी एजेंसियां अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गईं जो नेताओं की तिजोरी भरने के साथ ही सेटिंग में उस्ताद हों.

बाहरियों के पैर हुए मजबूत

केन्द्र सरकार के लिए बस्तर केवल लोहे के पहाड़ हैं. राज्य सरकार के लिए यह वनोपजों और गौण अनाजों का स्वर्ग. यहां लोहे की बेशकीमती खदानें खुलीं तो आदिवासियों को कुछ नहीं मिला. उलटे परिवहन में लगे ठेकेदारों के कारण यहां नक्सलियों की चाँदी हो गई. आम बस्तरिहा सुरक्षा बलों और नक्सलियों के दो पाटों की बीच घुन की तरह पिस गया. उन्हें रोजगार के सपने तो दिखाए गए पर हाथ में आया कुछ नहीं. बस्तर का ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले नगरनार स्टील प्लांट में भी स्थानीय बेरोजगारों के साथ छलावा किया गया. एनएमडीसी स्टील प्लांट में 80% बाहरी युवाओं की नियुक्ति की गई है जबकि शेष 20% में भी केवल 5% ही स्थानीय युवा हैं.

नहीं मिला विकास का लाभ

बस्तर में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC) की खदानें हैं. इन खदानों में लगभग पूरा काम मशीनों के द्वारा होता है. पिछले 60 सालों से यहां उत्खनन हो रहा है. जिन डिपाजिटों में खनन चल रहा है वहां अब भी आधे से ज्यादा खनिज भरा पड़ा है.

सिंडिकेट का खेल

सूत्र बताते हैं कि ज्यादातर टेंडर मैनेज किये जाते हैं. तीन-चार एजेंसियां मिलकर सिंडिकेट बना लेती हैं. कोई इस गठजोड़ को तोड़ना चाहे, तो विभागीय नियमों का इस्तेमाल कर उन्हें हतोत्साहित कर दिया जाता है. किसी तरह काम ले भी लिया तो ऐसे एजेंसियों को या तो काम छोड़ना पड़ता है या फिर भारी नुकसान उठाना पड़ता है. सिंडिकेट की एजेंसियां स्वयं काम नहीं करतीं बल्कि पीस वर्क एवं पेटी कांट्रेक्टरों को काम सौंप देती है. इनका भुगतान रोकने की भी शिकायतें आम हैं पर कोई कान नहीं धरता.

एनएमडीसी ने चूना लगाया निजी से क्या उम्मीद ?

डिपॉजिट-13 में लौह अयस्क खनन के लिए आदिवासियों और स्थानीय जन प्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लिया गया. एनएमडीसी पहले से संचालित भंडार का आधा अयस्क भी 6 दशकों में नहीं निकाल सकी है, फिर नए डिपॉजिट खोलने और उन्हें निजी हाथों में सौंपने का क्या औचित्य है? इतने सालों में एनएमडीसी से स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ. न रोजगार मिला और न ही सुविधाएं. लाल पानी की समस्या भी हल नहीं हुई. एनएमडीसी से क्षेत्र को पेयजल, बिजली, सड़क की जो सुविधा मिलनी थी, वह नहीं मिली. फिर निजी कंपनियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं?

■ लखेश्वर बघेल
अध्यक्ष, बस्तर विकास प्राधिकरण

बस्तर का ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले नगरनार स्टील प्लांट में स्थानीय बेरोजगारों के साथ छलावा किया जा रहा है. एनएमडीसी स्टील प्लांट के मेकॉन कंपनी ने लगभग 80% बाहरी युवाओं की भर्ती की है जबकि अन्य 20% में भी केवल 5% स्थानीय युवा काम कर रहे हैं.

■ नवनीत चांद
जिला अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस

इधर एक नए डिपाजिट को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है जिसका आदिवासी विरोध कर रहे हैं. इस विरोध की ठोस वजह है. आदिवासियों का मानना है कि जब सरकारी कंपनी एनएमडीसी ने ही उनका ध्यान नहीं रखा तो निजी क्षेत्र से क्या उम्मीद की जाए. खदानों का मतलब उनके लिए केवल उजड़ते जंगल, लाल पानी, भारी वाहनों का आवागमन मात्र है. सभी सरकारें नक्सलियों को भगाने और खदानें खोलने का ही रास्ता साफ करती रही. सड़क बनाने की जिद में बस्तर खून से लाल हुआ. 2018 में भूपेश बघेल सरकार के आने के बाद छत्तीसगढ़ के लिए बस्तर में सुरक्षा, विश्वास और विकास का नया दौर शुरू हुआ.

राज्य सरकार की कोशिशों पर विराम

नगरनार स्टील प्लांट में यह स्थिति तब है जबकि प्लांट प्रबंधन ने प्लांट में 50% नौकरियां बस्तर के बेरोजगारों को क्वालिफिकेशन के आधार पर देने का वादा किया था. राज्य सरकार ने कनिष्ठ चयन बोर्ड का गठन किया था और इस बोर्ड के माध्यम से सरकारी विभागों में खाली पड़े विभिन्न पदों पर स्थानीय युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन इस कनिष्ठ चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती पर हाईकोर्ट का स्टे लग गया है.

निर्माण एजेंसियां और ठेकेदारों के वारे-न्यारे

वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर भारत सरकार से 271 करोड़ रूपए की वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई थी. छत्तीसगढ़ में वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 16,297 किमी सड़कों का निर्माण हो चुका है. वर्ष 2015-16 से वर्ष 2022-23 के बीच बजट में प्रावधान की गई 3309 करोड़ रूपए की राशि के विरुद्ध 2493 करोड़ रूपए का व्यय किया गया. बस्तर की 231 किलोमीटर की 75 सड़कों का 37 करोड़ रूपए की लागत से संधारण किया गया. सरगुजा संभाग की 146 सड़कों का संधारण 90 करोड़ रूपए की लागत से किया गया. इसमें से अधिकांश पैसा इन ठेकेदारों को चला गया.

बस्तर में खर्च की जा रही करोड़ों की राशि बाहरी ठेकेदारों के हाथों तक पहुंच रही है. इनमें से अधिकांश के मुख्यालय राजधानी रायपुर में हैं जहां उनके करोड़ों रुपए के आलीशान बंगले हैं. इन कंपनियों के सुपरवाइजरों को ही बस्तर की सड़कों पर देखा जाता है. फौरी पूछताछ में ये लोग खुद को इंजीनियर सब-इंजीनियर बताते हैं. पर जब गहराई से पूछताछ की जाती है तो ये कन्नी काट लेते हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनमें ऐसे युवा भी शामिल हो सकते हैं जिनका यूपी-बिहार में आपराधिक रिकार्ड हो. वहां पुलिस का दबाव बढ़ने के बाद इन्होंने छत्तीसगढ़ में पनाह ली हो.

पुलिस नहीं नक्सलियों का प्रोटेक्शन

हाल ही में जब सड़क निर्माण में जुटी एक एजेंसी के वाहनों को नक्सलियों ने फूंक दिया तो पुलिस का कहना था कि एजेंसी ने पुलिस को न तो सूचित किया था और न ही सुरक्षा की मांग की थी. बस्तर के घने जंगलों वाले क्षेत्र में ये ठेकेदार अपने रिस्क पर ही काम करना पसंद करते हैं. उनका काम आसान बनाता है नक्सलियों को जाने वाला इनका भारी भरकम नगद चंदा जो अब तक 2000 रुपए के नोटों की शक्ल में होता आया है.

बीजापुर इलाके में पुलिस ने नक्सली कमांडर मल्लेश का 6 लाख रुपया संघम सदस्यों से जब्त किया था. यह पूरी रकम 2 हजार के 300 नोटों की शक्ल में थी. बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि बस्तर में नक्सली संगठन पैसों की बदौलत ही बाहरी मदद लेते हैं. लेवी के रूप में नक्सली अधिकांश बड़े नोटों को अपने पास जमा करके रखते हैं और इन्हीं पैसों की मदद से अपने संगठन को मजबूत करते हैं. नक्सल मामलों के जानकारों का मानना है कि नक्सली बड़े स्तर पर व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य लोगों से लेवी वसूलते हैं. इस रकम को बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर के घने जंगल में छुपा कर रखते हैं.

सुरक्षा बलों ने हथियारबंद माओवादियों को पहाड़ियों तक सीमित तो कर दिया है किन्तु नक्सलवाद की आड़ में नए माफियाओं का खेल शुरू हो गया है. यह माफिया है निर्माण एजेंसियों के ठेकेदार और लकड़ी तस्करों का.

वन अधिकार पट्टे का खुला दुरुपयोग

वनांचलों में बढ़ती जनसंख्या और ग्रामीणों की जरूरत को देखते हुए भूमिहीन निवासियों को खेती-किसानी के लिए वन भूमि अधिकार पत्र दिए गए हैं. अब तक अकेले जगदलपुर वनवृत्त के अंतर्गत लगभग 32,000 हेक्टेयर वन भूमि का पट्टा दिया जा चुका है. ग्रामीण आदिवासियों को लालच देकर उन्हें प्राप्त भूमि पर स्थित पेड़ों को काटने हेतु उकसाया जाता है. जाहिर है कि पैसे और खेती के लिए वन भूमि अधिकार पट्टा पाने वाला व्यक्ति तत्काल राजी हो जाता है. इस प्रकार वन भूमि अधिकार पट्टे के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं. इन क्षेत्रों में लगातार बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से हरियाली गायब हो रही है और सैकड़ों साल पुराने साल वृक्षों के साथ ही सागौन, बीजा जैसे अन्य कीमती वनोपज देने वाले वृक्ष भी गायब हो रहे हैं. वास्तव में वन भूमि अधिकार पट्टा इस शर्त के साथ दिया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित बड़े पेड़ों को ना काटा जाए, लेकिन निगरानी के अभाव में इस शर्त का पालन नहीं हो रहा है. निगरानी करें भी तो कौन जब सरकारी अधिकारी भी अवैध कार्यों में भागीदार बन जाए तो नियम शर्तों का पालन कैसे संभव है.

बताया जाता है कि मुख्यमंत्री निवास में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में बस्तर से बोर्ड के सदस्य हेमंत कश्यप द्वारा यह मामला उठाया गया और उन्होंने जानकारी दी कि वन भूमि अधिकार पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि वृक्षों को काटे बगैर वन भूमि पर खेती की जाएगी. उसका पालन ना कर पेड़ों को गडलिंग कर सुखाने और उनमें आग लगाने की प्रवृत्ति आम हो गई है, जिसके कारण पेड़ों की बहुत क्षति हो रही है. यह सुझाव भी दिया गया कि वन भूमि अधिकार पट्टा देने के पूर्व भूमि का निरीक्षण कर उस भूमि में किस-किस प्रजाति के कितने वृक्ष है उसका उल्लेख पट्टा प्रपत्र में किया जाना चाहिए, जिससे समय-समय पर निरीक्षण करने से यदि वृक्ष काटे गए हैं तो उसकी जानकारी मिल जाएगी और ऐसे मामलों में दंड के कड़े प्रावधान हों तथा क्षति पूर्ति हेतु अर्थदंड लगाया जाए जिससे वन भूमि पट्टे के दुरुपयोग पर रोक लगेगी.

छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक 10 दिसंबर 2022 को संपन्न हुई थी. यह मामला जानकारी में आने के बाद मुख्यमंत्री ने श्री कश्यप की सूचनाओं को गंभीरता से लिया और 19 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री कार्यालय से पीसीसीएफ (वन्य जीवन एवं जैव विविधता संरक्षण) को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया गया कि इस संबंध में तत्काल सकारात्मक कार्यवाही की जाए. जानकारी मिली है कि इसके तारतम्य में मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव छत्तीसगढ़ में लगभग 5 माह बाद 23 मई 2023 को मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर वनवृत्त, मुख्य वन संरक्षक वन्य जीवन और क्षेत्रीय निदेशक इंद्रावती टाइगर रिजर्व जगदलपुर, निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर तथा उपनिदेशक इंद्रावती टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट को पत्र प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही करने एवं की गई कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत कराने का निर्देश दिया है. अब देखना यह है कि जमीनी स्तर पर क्या कार्रवाई होती है.

MATS UNIVERSITY

A NAAC Accredited

with highest ranking in Chhattisgarh State amongst all private Universities.

APPROVALS & RECOGNITIONS : U.G.C., A.I.C.T.E., B.C.I., P.C.I., N.C.T.E., A.I.U., N.A.A.C. & C.G.P.U.R.C

NATIONAL & INTERNATIONAL ACADEMIC ASSOCIATIONS

Join MATS

STAY AHEAD WITH CUTTING EDGE SPECIALIZATIONS

- Data Science
- A.I. and I.O.T.
- Robotics
- Drone Technology
- Mineral Processing
- Green Technology
- Applied Psychology
- Logistics

ADMISSION OPEN FOR THE SESSION 2023-24

FOR ONLINE ADMISSION VISIT : www.matsuniversity.ac.in

PLACEMENT ORIENTED NEW PROGRAMS INTRODUCED FROM THIS SESSION

B.Sc. (Hons.) (Applied Psychology) | **M.Sc.** (Psychology) | **B.Sc.** (Forensic Science) | **B.Pharm.** (Bachelor of Pharmacy) | **D.Pharm.** (Diploma in Pharmacy) | **B.S.W.** (Bachelor of Social Work)

School of Engineering

M.Tech.
Computer Science Engineering
Turbo Machinery
Power Electronics
Computer Aided Structural Engineering

B.Tech. Hons.
Computer Science Engg.(IOT, AI & ML)
Aeronautical Engg. (UAV)
Mechanical Engg. (ROBOTICS & ENERGY)
Mining Engg. (MINERAL PROCESSING)
Civil Engg. (CONS. MGMT. & GREEN TECH.)

B.Tech.
Computer Science Engineering
Aeronautical Engineering
Mechanical Engineering
Mining Engineering
Civil Engineering

Diploma
Mechanical Engineering
Mining Engineering
Civil Engineering
Admission Help Line : 7389356989, 9109951182

School of Business Studies

M.Com.
B.Com. (Hons.)
B.Com. (Land Transportation)
Admission Help Line : 7389376989

School of Management

M.B.A. Marketing/HR/Fin. (Dual Spe.)
B.B.A. (Hons.) Marketing/HR/Fin.
B.B.A. (Logistics)
Admission Help Line : 9109913111

School of Information Technology

M.C.A.
Specialization in AI/Data Science
M.Sc. (CS)
P.G.D.C.A.
B.Sc.
Animation & Graphic Designing
B.C.A.
Specialization in AI/Data Science
D.C.A.
Admission Help Line : 9109951181

School of Fashion Designing & Technology

M.Design
B.Sc. (Hons.)
Fashion Designing & Technology
Interior Design & Decoration
Admission Help Line : 9109951183

School of Education

M.A. (Education)
B.Ed.
Admission Help Line : 9109951184

School of Research Studies

Ph.D.
in various streams
Admission Help Line : 9109994500

Law School

LL.M.
B.A. LL.B.
LL.B.
Admission Help Line : 9109997900

School of Sciences

M.Sc.
Microbiology/Chemistry
Botany/Zoology
B.Sc.
Biotechnology/Microbiology
Forensic Science/ CBZ/ PCM
Admission Help Line : 9109991032

School of Pharmacy

B.Pharmacy
D.Pharmacy
Admission Help Line : 9755199381

School of Physical Education

M.A. (Yoga)
B.P.Ed.
P.G.D.Y.Ed.
Admission Help Line : 9755199381

School of Library & Information Science

M.Lib.I.Sc.
B.Lib.I.Sc.
Admission Help Line : 9109991031

School of Arts & Humanities
Department of Social Work

M.S.W.
Specialization :
1. Community Development
2. Medical & Psychiatry
B.S.W.
Admission Help Line : 9109994500

Department of Psychology

M.A. (Psychology)
M.Sc. (Psychology)
P.G.D.G.C.
PG Dip. in Guidance & Counseling
B.A. (Hons.) Applied Psychology
B.Sc. (Hons.) Applied Psychology
Admission Help Line : 7471180268

Department of Hindi

M.A. (Hindi)
B.A.
History/Political Science/Social Science
B.A. (Hons.)
Hindi with Journalism & Tourism
Diploma
Journalism & Mass Communication
Admission Help Line : 7880001773

Department of English

M.A. (English)
B.A. (Hons.)
English with Mass Communication
Admission Help Line : 9752942949

STUDENTS CAN PURSUE TWO ACADEMIC PROGRAMS SIMULTANEOUSLY

FROM ACADEMIC YEAR 2023-24. PLEASE CONTACT OUR COUNSELORS TO KNOW MORE ABOUT THE PROGRAMS & ITS FINANCIAL BENEFIT.

FOR DETAILS CALL : 1800 123 819999

ADMISSION OFFICE : RAIPUR CAMPUS, MATS TOWER, PANDRI, RAIPUR, CG, 492 004
UNIVERSITY CAMPUS : AARANG KHARORA HIGHWAY, AARANG, RAIPUR, CG, 493 441
Tel : 0771 4078995, 96, 98 **Mob:** 9109951184, 9755199381, 9109994500 **Email :** admissions@matsuniversity.ac.in

SCAN FOR VIRTUAL TOUR OF MATS UNIVERSITY

भिलाई-राजहरा की जिम्मेदार

कैसे होगा समाधान!

सेल भिलाई इस्पात संयंत्र की बिगड़ती शिक्षा, चिकित्सा, टाउनशिप तथा श्रमिक अधिकारों की कटौती से उपजता जनाक्रोश अब धीरे-धीरे मुखर हो रहा है. छत्तीसगढ़ आजतक के पिछले अंक में भिलाई सहित नंदिनी एवं दल्ली राजहरा की उजड़ती टाउनशिप, घटता रोजगार के अवसर तथा निरंतर हो रहे यहां के रहवासियों और व्यापारियों के पलायन से संबंधित समाचार प्रकाशित होने के बाद विभिन्न क्षेत्रों से तीखी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई है.

» पी. मोहन

विशेषकर श्रमिक संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने न केवल वर्तमान स्थिति पर चिंता जाहिर की है बल्कि उन्होंने सेल एवं सरकार के केंद्रीय नेतृत्व और क्षेत्रीय सांसदों की उदासीनता को भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है.

इस संबंध में हाउस लीज संघर्ष समिति एवं लोकतांत्रिक इस्पात इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन भिलाई के अध्यक्ष राजेंद्र परगनिहा ने हमारे प्रतिनिधि से चर्चा करते हुए कहा कि जब उन्होंने नवंबर 1986 में एसओटी के रुप में बीएसपी की नौकरी ज्वाइन की तब भी भिलाई, राजहरा, नंदिनी एवं हिर्री में कार्यरत मजदूरों की कुल संख्या 60 हजार से अधिक थी. उनका कहना था कि साल 1960 से लेकर 1985 तक भिलाई इस्पात संयंत्र का स्वर्णिम कार्यकाल था. पं. जवाहरलाल नेहरू एवं श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन काल में सार्वजनिक उपक्रमों के प्रति काफी उदारवादी दृष्टिकोण था और इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में न केवल उत्पादन के क्षेत्र में बल्कि कर्मचारियों की समस्त मूलभूत सुविधाओं, बेहतर वेतन, आवास, शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई. इसी वजह

बदहाली के लिए कौन ?

से भिलाई की टाउनशिप देखने और शिक्षा, चिकित्सा का लाभ लेने के लिए ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्य के लोग भी आकर्षित हुए. इसी दौरान भिलाई का निजी औद्योगिक क्षेत्र भी तेजी से विकास की ओर अग्रसर हुआ. उन्होंने कहा कि समय के साथ परिवर्तन स्वभाविक है. राजीव गांधी के शासन काल में आधुनिक तकनीक के साथ ही आर्थिक नीतियों में कुछ परिवर्तन तो आया, लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र और उसके खदानों के श्रमिकों के अधिकार एवं रोजगार सुरक्षित रहे. बाद में परिस्थितियां बदलती गई और केंद्र में चाहे जिनका भी नेतृत्व रहा हो उनका दृष्टिकोण बदला और ऐसा कहा जाने लगा कि हमारा काम सिर्फ प्रोडक्शन और प्राफिट का है. इस नए दृष्टिकोण ने न केवल सार्वजनिक हित और मजदूरों के अधिकार व सुविधाओं पर कुठाराघात किया बल्कि प्रोडक्शन और प्राफिट भी अपेक्षा अनुरूप निरंतर घटता गया. इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान की दयनीय स्थिति सामने है. वर्तमान में प्रबंधन एवं सरकार द्वारा सुधार की बजाय यूनियनों के संघर्ष को दबाने और उपेक्षा करने का कुचक्र चल रहा है.

छत्तीसगढ़ सीटू के कार्यकारी अध्यक्ष एस.पी.डे जो भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी हैं और जिन्होंने लंबे समय तक भिलाई सीटू यूनियन का प्रतिनिधित्व किया है बीएसपी एवं खदान क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति और निरंतर बढ़ती ठेका प्रणाली एवं कम होती नियमित संयंत्र कर्मियों

एस. पी. डे

की संख्या को लेकर काफी बेचैन और मुखर हैं. उन्होंने छत्तीसगढ़ आजतक को इस गंभीर समस्या पर ध्यान देने और सच्चाई को प्रकाशित करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उसकी यूनियन की ओर से एक दशक पहले ही संयंत्र कर्मियों की आवासीय कालोनी को संरक्षित रखने, स्कूलों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित भिलाई इस्पात संयंत्र के सेक्टर 9 स्थित मुख्य अस्पताल को उन्नत करने और माइंस क्षेत्रों में भी अच्छे अस्पताल तथा स्कूल स्थापित किए जाने हेतु मांग पत्र दिया था. दुर्भाग्यवश प्रबंधन ने हमारे सुझाव और मांगों को उपेक्षित किया. इस दौरान हमारी यूनियन को भिलाई इस्पात संयंत्र में मान्यता प्राप्त यूनियन के रूप में भी संघर्ष करने का अवसर मिला और हमने ना केवल स्थायी संयंत्र कर्मियों बल्कि ठेका मजदूरों के हक में भी आवाज उठायी और संघर्ष किया. सबसे दुखद पहलू यह है कि केवल राजनीतिक विचारधारा के विरोध स्वरूप क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों जिनमें विधायक एवं सांसद प्रमुख हैं, की ओर से राज्य एवं केंद्र स्तर पर भिलाई स्टील प्लांट उसके खदान क्षेत्र और यहां कार्यरत स्थाई व ठेका मजदूरों के हित में कभी भी ठोस प्रयास नहीं किया गया. आज की दयनीय स्थिति के लिए न केवल संयंत्र प्रबंधन बल्कि राज्य एवं केंद्र में प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी बराबर के जिम्मेदार व दोषी हैं. श्री डे का कहना है कि पहले भिलाई इस्पात संयंत्र एवं राजहरा, हिर्री माइंस टाउनशिप में शिक्षा के लिए अच्छे भवन एवं पर्याप्त शिक्षकों सहित 62 से अधिक स्कूल थे और हायर सेकेंडरी तक इन स्कूलों के माध्यम से संयंत्र कर्मियों के बच्चों के अलावा अन्य रहवासियों के बच्चों को भी न्यूनतम खर्च पर अच्छी शिक्षा, सुविधा प्राप्त होती थी लेकिन वर्तमान में सब कुछ तहस-नहस हो गया है, और नाममात्र के लिए 10-12 स्कूल ही रह गए हैं. निजी स्कूलों एवं अस्पतालों से ज्यादा निजी लाभ उठाने वाले जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी वर्ग शिक्षा, चिकित्सा को उद्योग बनाने वाले तबकों के सामने नतमस्तक है और उन्हें सार्वजनिक हित की कोई चिंता नहीं है. वर्तमान केंद्र सरकार पूरी तरह पूंजीपतियों के पक्ष में है, इसलिए सार्वजनिक उपक्रमों एवं मजदूर हितों पर लगातार कुठाराघात हो रहा है. उन्होंने मजदूर आंदोलन को संयुक्त रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करने पर जोर दिया और यह आशा व्यक्त की कि शीघ्र ही भविष्य में विपक्षी दलों की तरह यूनियनों की आपसी एकता मजबूत होगी तभी हम वर्तमान स्थिति से उबर सकते हैं.

चन्ना केशवलू

इस संदर्भ में हमारे प्रतिनिधि ने बीएसपी की मान्यता प्राप्त यूनियन बीएमएस के कार्यकारी अध्यक्ष चन्ना

» **पी. मोहन**

विशेषकर श्रमिक संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने न केवल वर्तमान स्थिति पर चिंता जाहिर की है बल्कि उन्होंने सेल एवं सरकार के केंद्रीय नेतृत्व और क्षेत्रीय सांसदों की उदासीनता को भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है.

इस संबंध में हाउस लीज संघर्ष समिति एवं लोकतांत्रिक इस्पात इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन भिलाई के अध्यक्ष राजेंद्र परगनिहा ने हमारे प्रतिनिधि से चर्चा करते हुए कहा कि जब उन्होंने नवंबर 1986 में एसओटी के रुप में बीएसपी की नौकरी ज्वाइन की तब भी भिलाई, राजहरा, नंदिनी एवं हिर्री में कार्यरत मजदूरों की कुल संख्या 60 हजार से अधिक थी. उनका कहना था कि साल 1960 से लेकर 1985 तक भिलाई इस्पात संयंत्र का स्वर्णिम कार्यकाल था. पं. जवाहरलाल नेहरू एवं श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन काल में सार्वजनिक उपक्रमों के प्रति काफी उदारवादी दृष्टिकोण था और इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में न केवल उत्पादन के क्षेत्र में बल्कि कर्मचारियों की समस्त मूलभूत सुविधाओं, बेहतर वेतन, आवास, शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई. इसी वजह से भिलाई की टाउनशिप देखने और शिक्षा, चिकित्सा का लाभ लेने के लिए ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्य के लोग भी आकर्षित हुए. इसी दौरान भिलाई का निजी औद्योगिक क्षेत्र भी तेजी से विकास की ओर अग्रसर हुआ. उन्होंने कहा कि समय के साथ परिवर्तन स्वभाविक है. राजीव गांधी के शासन काल में आधुनिक तकनीक के साथ ही आर्थिक नीतियों में कुछ परिवर्तन तो आया, लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र और उसके खदानों के श्रमिकों के अधिकार एवं रोजगार सुरक्षित रहे. बाद में परिस्थितियां बदलती गई और केंद्र में चाहे जिनका भी नेतृत्व रहा हो उनका दृष्टिकोण बदला और ऐसा कहा जाने लगा कि हमारा काम सिर्फ प्रोडक्शन और प्राफिट का है. इस नए दृष्टिकोण ने न केवल सार्वजनिक हित और मजदूरों के अधिकार व सुविधाओं पर कुठाराघात किया बल्कि प्रोडक्शन और प्राफिट भी अपेक्षा अनुरूप निरंतर घटता गया. इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान की दयनीय स्थिति सामने है. वर्तमान में प्रबंधन एवं सरकार द्वारा सुधार की बजाय यूनियनों के संघर्ष को दबाने और उपेक्षा करने का कुचक्र चल रहा है.

गोविंद वाघवानी

छत्तीसगढ़ सीटू के कार्यकारी अध्यक्ष एस.पी.डे जो भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी हैं और जिन्होंने लंबे समय तक भिलाई सीटू यूनियन का प्रतिनिधित्व किया है बीएसपी एवं खदान क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति और निरंतर बढ़ती ठेका प्रणाली एवं कम होती नियमित संयंत्र कर्मियों की संख्या को लेकर काफी बेचैन और मुखर हैं. उन्होंने छत्तीसगढ़ आजतक को इस गंभीर समस्या पर ध्यान देने और सच्चाई को प्रकाशित करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उसकी यूनियन की ओर से एक दशक पहले ही संयंत्र कर्मियों की आवासीय कालोनी को संरक्षित रखने, स्कूलों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित भिलाई इस्पात संयंत्र के सेक्टर 9 स्थित मुख्य अस्पताल को उन्नत करने और माइंस क्षेत्रों में भी अच्छे अस्पताल तथा स्कूल स्थापित किए जाने हेतु मांग पत्र दिया था. दुर्भाग्यवश प्रबंधन ने हमारे सुझाव और मांगों को उपेक्षित किया. इस दौरान हमारी यूनियन को भिलाई इस्पात संयंत्र में मान्यता प्राप्त यूनियन के रूप में भी संघर्ष करने का अवसर मिला और हमने ना केवल स्थायी संयंत्र कर्मियों बल्कि ठेका मजदूरों के हक में भी आवाज उठायी और संघर्ष किया. सबसे दुखद पहलू यह है कि केवल राजनीतिक विचारधारा के विरोध स्वरूप क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों जिनमें विधायक एवं सांसद प्रमुख हैं, की ओर से

राज्य एवं केंद्र स्तर पर भिलाई स्टील प्लांट उसके खदान क्षेत्र और यहां कार्यरत स्थाई व ठेका मजदूरों के हित में कभी भी ठोस प्रयास नहीं किया गया. आज की दयनीय स्थिति के लिए न केवल संयंत्र प्रबंधन बल्कि राज्य एवं केंद्र में प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी बराबर के जिम्मेदार व दोषी हैं. श्री डे का कहना है कि पहले भिलाई इस्पात संयंत्र एवं राजहरा, हिर्री माइंस टाउनशिप में शिक्षा के लिए अच्छे भवन एवं पर्याप्त शिक्षकों सहित 62 से अधिक स्कूल थे और हायर सेकेंडरी तक इन स्कूलों के माध्यम से संयंत्र कर्मियों के बच्चों के अलावा अन्य रहवासियों के बच्चों को भी न्यूनतम खर्च पर अच्छी शिक्षा, सुविधा प्राप्त होती थी लेकिन वर्तमान में सब कुछ तहस-नहस हो गया है, और नाममात्र के लिए 10-12 स्कूल ही रह गए हैं. निजी स्कूलों एवं अस्पतालों से ज्यादा निजी लाभ उठाने वाले जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी वर्ग शिक्षा, चिकित्सा को उद्योग बनाने वाले तबकों के सामने नतमस्तक है और उन्हें सार्वजनिक हित की कोई चिंता नहीं है. वर्तमान केंद्र सरकार पूरी तरह पूंजीपतियों के पक्ष में है, इसलिए सार्वजनिक उपक्रमों एवं मजदूर हितों पर लगातार कुठाराघात हो रहा है. उन्होंने मजदूर आंदोलन को संयुक्त रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करने पर जोर दिया और यह आशा व्यक्त की कि शीघ्र ही भविष्य में विपक्षी दलों की तरह यूनियनों की आपसी एकता मजबूत होगी तभी हम वर्तमान स्थिति से उबर सकते हैं.

इस संदर्भ में हमारे प्रतिनिधि ने बीएसपी की मान्यता प्राप्त यूनियन बीएमएस के कार्यकारी अध्यक्ष चन्ना केशवलू से भी चर्चा की. उनका कहना था कि संयंत्र के इतिहास में पहली बार बीएमएस को बीएसपी में प्रतिनिधित्व का अवसर मिला है. एनजेसीएस जो सेल में प्रबंधन से चर्चा के लिए विभिन्न यूनियनों का अधिकृत संगठन है. उसमें भी लंबे अर्से के बाद बीएमएस को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है. हम विभिन्न स्तर पर कुछ नया बदलाव चाहते है. जिसके निए योजना बनाई जा रही है. हमें इस बात की चिंता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र ने लोककला, खेलकूद आदि के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय अन्तरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाएं दी. जिससे टाउनशिप शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था पूरे देश में अपनी उत्तम स्थिति और व्यवस्था के लिए चर्चित थी. वह आज बदहाली की स्थिति में है और उसका अस्तित्व ही खतरे में आ गया है. उन्होंने कहा कि क्रिकेट के क्षेत्र में राजेश चौहान, बॉक्सिंग के क्षेत्र सें राजेंद्र प्रसाद, बास्केटबाल के क्षेत्र में राजेश पटेल, वेटलिफ्टिंग में तंद्राराय चौधरी, लोककला के क्षेत्र में तीजन बाई, स्व. देवदास बंजारे, पद्मश्री डॉ. राधेश्याम बारले, पद्मश्री उषा बारले आदि ऐसे नाम है, जिन पर छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश गौरव करता है. ऐसे समाज रत्नों को सामने लाने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बीएसपी की प्रमुख भूमिका रही है. साहित्य के क्षेत्र में डॉ. परदेशी राम वर्मा, स्व. दानेश्वर शर्मा, स्व. डॉ. विमल कुमार पाठक, रवि श्रीवास्तव, दादूलाल जोशी, लोकबाबू, ललित वर्मा, स्व. प्रेम साइमन आदि के साथ ही मूर्तिकला और लोकवाद्य के क्षेत्र में पद्मश्री जे. एम. नेल्सन, अंकुश देवांगन, रिखी क्षत्रिय इत्यादि तमाम इस्पात कर्मचारी अपनी रचना और कला से भिलाई और छत्तीसगढ़ का नाम देश- दुनिया में रोशन कर रहे हैं. इसके बावजूद बीएसपी कर्मचारियों और यहां के रहवासियों की मूलभूत समस्याओं के प्रति संयंत्र प्रबंधन की उदासीनता चिंताजनक है. यह पूछे जाने पर कि इस विषम स्थिति से उबरने के लिए आपकी यूनियन क्या प्रयास कर रही है, जबकि लोकसभा एवं राज्यसभा में आपकी विचारधारा के सांसद हैं केवल दुर्ग ही नहीं राजनांदगांव, कांकेर और बिलासपुर में भी भाजपा के सांसद हैं. ऐसी स्थिति में भिलाई, राजहरा, नंदिनी और हिर्री माइंस की बर्बाद होती टाउनशिप खस्ताहाल शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था को लेकर आपकी यूनियन क्या कर रही है. श्री केशवलू ने सिर्फ इतना ही कहा कि हम प्रयासरत हैं. कुल मिलाकर यूनियन प्रतिनिधियों में आक्रोश तो दिखा लेकिन संघर्ष की कोई ठोस योजना सामने नहीं आई. इस मामले में दल्ली राजहरा का व्यापारी संगठन काफी सजग और सक्रिय भी है इसलिए हमारे प्रतिनिधि ने दल्ली राजहरा जाकर व्यापारी संघ के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की.

दल्ली राजहरा व्यापारी संघ के अध्यक्ष गोविंद वाघवानी ने कहा कि उनका संगठन

उपलब्धि

पाटन अब बन गया शिक्षा का नया हब

- ब्लाक में 15 आत्मानंद स्कूलों की स्थापना
- 19 हाई और 38 हायर सेकंडरी स्कूल स्थापित
- कृषि महाविद्यालय एवं वानिकी विवि की स्थापना
- गरीब मेधावियों को मिलेगा बराबर का मौका

» उमाशंकर

यह नया पाटन है, जो शिक्षा के क्षेत्र में नई इबारत लिख रहा है. नए आत्मानंद स्कूलों में जहां गरीब मेधावी छात्रों को अंग्रेजी में शिक्षा मिल रही है, वहीं ब्लाक की चारों दिशाओं में स्थापित कालेज उन्हें उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान कर रहे हैं. यह नए पाटन की तस्वीर है. यह उजली तस्वीर है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की परिकल्पना साकार होते दिखती है. ये शिक्षा के नए मंदिर है.

यह ब्लाक मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर नवस्थापित 11 आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालय, कृषि महाविद्यालय एवं वानिकी विश्वविद्यालय उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था की मिसाल कायम कर रही है. पांच वर्ष पूर्व अंचल के बच्चे अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा के लिए निजी स्कूलों पर निर्भर थे. निर्धन मेधावी छात्रों के पालक अपने बच्चों का इन स्कूलों में दाखिला नहीं दिला पाते थे, किन्तु अब पाटन ब्लाक में 15 आत्मानंद स्कूलों की स्थापना हो चुकी है. जिसमें 11 में अंग्रेजी माध्यम एवं 4 विद्यालयों में हिन्दी माध्यम से पढ़ाई होती है. कुल प्राथमिक विद्यालय 184, मिडिल स्कूल 100, हाईस्कूल 19 और 38 हायरसेकंडरी स्कूल स्थापित है, जहां 44 हजार 276 बच्चे अपना भविष्य गढ़ रहे हैं.

इन विद्यालयों में जहां बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा मिलती है वहीं स्वादिष्ट और पोषण से परिपूर्ण मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जाता है. इन विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित सुयोग्य शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं. विकासखंण्ड शिक्षा अधिकारी टी. आर. जगदल्ले बताते है कि कोरोना महामारी के बाद क्षेत्र के पालकों ने अपने बच्चों का दाखिला इन सरकारी स्कूलों में कराना शुरू कर दिया. कोरोना काल में कई निजी स्कूलों में ताले लग गए. ऐसे में सरकारी स्कूलों ने पुन: गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान कर उन स्कूलों की कमियों को दूर किया.

अब डिग्री के लिए भी ब्लाक में चारों दिशाओं में कालेजों की स्थापना हो चुकी है

डॉ. चन्दूलाल चंद्राकर महाविद्यालय पाटन ब्लाक की शिक्षा का प्रमुख केन्द्र है, जहां के छात्र नेता ब्लाक की राजनीति को कंट्रोल करते है. यहां बी.ए., बी. कॉम., बीएससी के साथ ही एमए., एमएससी की डिग्री मिलती है. शासकीय डॉक्टर खूबचंद बघेल महाविद्यालय भिलाई-3 शहरी क्षेत्र में स्थित है और पुराना शिक्षा केन्द्र है. जामगांव आर एवं रानीतराई स्थित नवीन कालेज नए शिक्षा केन्द्र के रूप में उभर रहे है, जहां कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों की पढ़ाई हो रही है. अब विशिष्टता की बात करें, तो पाटन में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं पाटन स्वामी आत्मानंद स्कूल की तकनीकी शिक्षा मिसाल है.

आईटीआई पाटन में इलेक्ट्रिशियन, फिटर, कोपा, स्टेनो और डीजल मैकेनिक ट्रेड है. जहां कुल 240 युवा अपना भविष्य संवार रहे है. पूर्व में यह संस्था ग्राम दरबार मोखली में संचलित थी. प्राचार्य हरीश शर्मा कहते है कि नया भवन सर्वसुविधायुक्त है. नए हॉस्टल का निर्माण जारी है. इसी कड़ी में एक उपलब्धि यह है कि आई.टी.आई. का उन्नयन करने का जिम्मा टाटा कंपनी ने लिया है.

पाटन में शिक्षा क्रांति दो विशिष्ट संस्थाओं की देन है. इसमें आधुनिक कृषि का विजन है. पहला मर्रा में स्थित कृषि महाविद्यालय और सांकरा में नवस्थापित वानिकी विश्वविद्यालय. वानिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रखी है. विश्वविद्यालय परिसर के लिए 150 करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान किया गया है.

पाटन विकासखण्ड कृषि के क्षेत्र में अग्रणी रहा है. इस पर कृषि महाविद्यालय ने चार चांद लगाए. यहां कृषि स्नातकों के लिए चार वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित है. यहां कृषि शिक्षा के साथ ही अनुसंधान कार्य जारी है. महाविद्यालय में टिश्यू कल्चर लैब के साथ हाईटेक नर्सरी स्थापित है. यहां से किसानों को गुणवत्ता युक्त पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं. कृषि महाविद्यालय के डीन वी. के सोनी बताते हैं कि महाविद्यालय में राज्यभर के विद्यार्थी अध्ययनरत है. कालेज के माध्यम से अंचल के कृषक सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इसलिए पाटन को जैविक ब्लाक के रूप में चिन्हांकित किया गया है. कालेज अंचल को कृषि उद्यानिकी एवं जैविक खेती में उन्नतशील बनाने प्रयासरत है. कालेज में 21 स्नातक छात्रों का पहला बैच 2022-23 में तैयार हुआ. मजबूत स्कूली शिक्षा से जहां अंचल के बच्चों की नींव सुदृढ़ हो रही है, वहीं उच्चशिक्षा के ये मंदिर बच्चों के करियर निर्माण में महती भूमिका निभा रहे हैं. ये नए पाटन के शिक्षा मंदिर है जो इसे शिक्षाधानी की नई पहचान दे रहे हैं.

DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY

Chhattisgarh, Bilaspur — AN AISECT GROUP UNIVERSITY

DR. C.V.RAMAN UNIVERSITY

Approved by : PCI | AICTE | NCTE | BCI | Member of : AIU | Recognized by : UGC | A NAAC Accredited University

ADMISSION OPEN [2023-24]

PROGRAMMES OFFERED

ENGINEERING & TECH.

B.Tech.
- Mechanical Engineering
- Civil Engineering
- Electrical Engineering
- Electronics & Comm. Engg
- Computer Science Engg.
- Electrical & Electronics Engg.

Polytechnic Diploma
- Civil Engineering
- Mechanical Engineering
- Computer Science Engg.
- Electrical Engineering

M. Tech.
- Digital Communication
- Power System
- Computer Science Engg.
- Production Engineering
- Software Engineering • VLSI

B.VOC
- Automobile Servicing
- IT Application Development
- Banking Financial Services and Insurance
- Construction
- Production Technology
- AC & Refrigeration

EDUCATION
- B.Ed. | M.Ed.

PHYSICAL EDUCATION
- B.P.E.S. | M.P.E.S.

MANAGEMENT
- B.B.A.| M.B.A. |PGDBM

COMMERCE
- B.Com. | M.Com.

INFORMATION TECH.
- M.Sc. (IT) • M.Sc. (CS)
- P. G.D.C.A.
- B.C.A. • D.C.A.

ARTS
- B.A.
- M.A.
  - Linguistics- (English, Hindi, Chhattisgarhi, Sanskrit)
  - Social Science - (History, Geography, Economics, Political Science, Education)
- B.Lib. | M.Lib.
- M.S.W. (Social Work)
- B.J. | M.J.
- PERFORMING & FINE ARTS (Indian Music (Vocal) Kathak, Tabla, Guitar)
  B.F.A. | M.F.A.

PHARMACEUTICAL SCIENCES
- B. Pharm-(4-Year Course) (Bachelor of Pharmacy)
- D. Pharm-(2-Year Course) (Diploma in Pharmacy)
- M. Pharm*-(2-Year Course) (Master of Pharmacy)

* Proposed

Research Programmes **Ph.D.**

FACULTY OF SCIENCE

B.Sc. — Mathematics | Biology | Microbiology | Biotech | Computer Science

M.Sc. — Physics | Chemistry | Mathematics | Botany | Biotech | Zoology | Electronics | Micro-biology | Rural Technology

PGDRD

FACULTY OF LAW

LL.B. | LL.M.

B.A. (LL.B.)

B.Com.(LL.B.)

Other Initiatives Taken Up By CVRU

Solar Power
We have a 10 KW solar power generation system and a 5 KW capacity solar cell

Herbal Medicinal Garden
Our campus garden has around 425 plants with medicinal value and a variety of herbs and shrubs, as part of our **Go Green Campus** campaign

Biogas
We use biogas in laboratories from our plant which produces with more than 1000 cm^3 of capacity

NSDC and NPTEL Partnership
To ensure an advantage in placements, we train in skills with the NSDC and virtual courses designed by IIT faculties with the NPTEL

Incubation Centre
Incubation Centre at CVRU campus 5 crore project fromdepartment of science & technology (DST), govt of India (ITBI) inclusive technology business Incubator NIDHI-DSTscheme

Village Adoption
We have adopted five villages near the university through the NSS and NCC & Uannat Bharat Abhiyan

TOP RECRUITERS OF AGU

Paytm | NIIT | Star | Collabera | genpact | LANCO | amazon | AMERICAN EXPRESS | Tech Mahindra | iON | vedanta | zomato | vivo | wipro | pinnacle | Infosys | SHRIRAM | IndusInd Bank | SAMSUNG | Vedisoft | COGENT | EXIDE | vedanta | Capgemini | CODING NINJAS | YAHOO! | WADHWANI | Prakash | HCLTech | Fullerton India | HCL

ADMISSION HELPLINE: 6261-900581, 6261-900582 www.cvru.ac.in

Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.), Phone: +91-7753-25801,Email: info@cvru.ac.in, admissions@cvru.ac.in

AdPrayas

द केरला स्टोरी में दिखाया आधा सच

अभी हाल में ही केरल राज्य की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म 'केरला स्टोरी' प्रदर्शित हुई. फ़िल्म प्रदर्शन के बाद इसकी कथानक एवम धार्मिक कट्टरता के फलस्वरूप पूरे देश में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी. हिन्दू-मुस्लिम समर्थकों को डिबेट करने का ज्वलंत मुद्दा मिल गया था, राजनीतिज्ञों ने भी इसके पक्ष एवं विपक्ष में जमकर बयानबाजी की. फ़िल्म इस्लामिक कट्टरता के कारण सुर्खियों में रहा. इसमें यह दिखाया गया था कि केरल में हिन्दू लड़कियों का धर्मांतरण कर किस तरह इस्लामिक कट्टरता की ओर उन्हें धकेला जाता है. मुस्लिम धर्म की आड़ में आतंकी संगठन उसका किस तरह आतंकी के रूप में इस्तेमाल करते हैं. फ़िल्म में विभिन्न आंकड़ों व तथ्यों को जोड़कर इसे रियल घटना बताने का प्रयास किया गया था. यह फ़िल्म आई-गई चली गई, लेकिन आम जनता के बीच एक प्रश्न छोड़ गया कि फ़िल्म में जो बातें बताई गई है उस स्टोरी को सच माने या गलत? अब इसी फिल्म के राईटर सूर्यपाल सिंह ने बस्तर में भी धर्मांतरण को लेकर लोकसभा चुनाव के पहले फिल्म प्रदर्शित करने की घोषणा की है.

» दीपक रंजन दास

देश की अल्पसंख्यक कौमों पर यह आरोप अकसर लगते हैं कि वे प्रलोभन और 'लव जिहाद' के जाल में फँसा कर हिन्दू लड़कियों को अपने धर्म में शामिल कर लेते हैं. पर यह केवल आधा सच है. ईसाई हों या मुसलमान दोनों का भारत में सैकड़ों साल का इतिहास है. अलग-अलग समय पर ये भारत आए और इस पुण्यभूमि को अपना घर बना लिया. कारण भी स्पष्ट था. भारत को अंग्रेजी में "लैण्ड ऑफ अबन्डेंस" (प्रचुरता की भूमि) कहा जाता है. अब राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए चुन-चुन कर मुद्दे उठाए जा रहे हैं. ऐसा संभव इसलिए हो रहा है कि भारतीय समाज ने इतिहास अध्ययन को कभी गंभीरता से नहीं लिया. यह थर्ड डिवीजन वालों का विषय ही बना रहा. इस आलेख में हम आपको बताने जा रहे हैं केरल के सीरिया कनेक्शन के साथ ही देश में हिन्दू, मुसलमान, ईसाइयों के सहअस्तित्व के बारे में.

भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों का आगमन प्रथम शताब्दी में ही हो चुका था. केरल में सेंट थॉमस का आगमन ईस्वी 52 में हुआ. वे ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक थे. इसलिए जब 1498 में वास्को डी गामा केरल पहुंचे तो यहां ईसाइयों को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ था. केरल के ईसाई समुदाय में कैथोलिक चर्च (सीरियन) को मानने वालों की संख्या सबसे अधिक है. इसके अलावा मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च, जैकोबाइट सीरियन चर्च, मार्थोमाइट सीरियन चर्च सभी की जड़ें सीरिया से जुड़ी हैं. इसके अलावा प्रोटेस्टेंट समूहों में चर्च ऑफ साउथ इंडिया, पेन्टेकोस्टल चर्च, चालडियन सीरियन, सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट्स, साल्वेशन आर्मी को मानने वाले भी यहां पाए जाते हैं. जाहिर है केरल के सीरिया कनेक्शन में ईसाइयों की भी भूमिका बड़ी है.

इस्लाम का भारत आगमन

इस्लाम का आगमन भी भारत मे 7वीं शताब्दी में हो चुका था. कुछ इतिहासकार इसे 17वीं शताब्दी भी मानते हैं. अरब सागर को पार कर मुस्लिम मूलतः मसालों का व्यापार करने के लिए मालाबार तट पर पहुंचे. उनमें से कुछ लोग यहीं बस गए और स्थानीय युवतियों से विवाह कर लिया. इन्हें मप्पिला या मोपला कहा गया. इनमें से अधिकांश खेतिहर मजदूर थे. भूमि का स्वामित्व जमींदारों और उच्च वर्ग के हिन्दुओं के पास था. देश के अन्य भागों की तरह ही यहां भी किसानों पर जमींदार अत्याचार करते थे. मालाबार पर टीपू सुलतान के आक्रमण से पहले तक यही स्थिति बनी रही.

18वीं शताब्दी में हैदर अली के आक्रमण के बाद उत्पीड़न और जबरिया धर्मपरिवर्तन के डर से हिन्दू जमींदार और सामंत यहां से भाग खड़े हुए. टीपू सुल्तान ने उन भूखण्डों का अधिकार मोपला कृषि मजदूरों को सौंप दिया. 1799 में चौथे एंग्लो-मैसूर युद्ध के बाद इस इलाके पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया. केरल सहित पूरा मालाबार मद्रास प्रेसीडेंसी के अधीन हो गया. अंग्रेजों ने सामंतों और जमींदारों को पुनः केरल में बसाने के प्रयास प्रारंभ किये. अंग्रेजों की बंदूकों का सहारा मिला तो सामंतों और जमींदारों ने किसानों और मजदूरों पर जमकर अत्याचार प्रारंभ कर दिये.

इसके बाद 1836 से 1896 के बीच कई छोटे बड़े विद्रोह हुए. इसमें अनेक ब्रिटिश

अधिकारी एवं शोषक जमींदारों की हत्या कर दी गई. 1921 का विद्रोह विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिसे सभी इतिहासकारों ने मोपला विद्रोह के रूप में संबोधित किया. अंग्रेजों के खिलाफ संभवतः यही देश का पहला सशस्त्र विद्रोह था.

सदियों बाद भी सलामत है हिन्दुत्व

कहने का आशय यही है कि छोटे से प्रदेश केरल में मुसलमान और हिन्दू सदियों से साथ रह रहे हैं. इसका असर भी साफ दिखता है. बड़ी संख्या में हिन्दू मलयाली भी मुस्लिम देशों में नौकरी करते हुए मिल जाते हैं. सदियों तक साथ रहने के बावजूद यहां की हिन्दू आबादी

आज तक बहुसंख्यक ही है. यहां की 3.48 करोड़ आबादी में से 97% लोग मलयाली बोलते हैं. 54.7 प्रतिशत आबादी हिन्दू है. 26.6 प्रतिशत आबादी मुस्लिम और 18.4 प्रतिशत ईसाई हैं. राज्य में 9.8 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति की है. 1.14 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है. इसके अलावा 22.8 लाख मलयाली देश के बाहर निवास करते हैं. आबादी के हिसाब से इन देशों का क्रम संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, इटली, जर्मनी, आदि शामिल हैं.

यही बात ईसाई धर्म के लिए भी कही जा सकती है. सेंट थॉमस पहली शताब्दी में भारत आ चुके थे. शिक्षा और स्वास्थ्य पर 1911 में कोचीन और ट्रावनकोर के राजाओं ने काम करना शुरू कर दिया था जिसमें ईसाई मिशनरियों की भी बड़ी भूमिका थी. यही वजह है कि न केवल यहां की 97 फीसदी से अधिक आबादी शिक्षित है बल्कि राज्य को चिकित्सा पर्यटन से भी अच्छी खासी आमदनी होती है. UNICEF और WHO ने केरल को विश्व के पहले "बेबी फ्रेंडली स्टेट" का भी दर्जा दिया है. यहां लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या अधिक है.

सवाल यही उठता है कि जब 17वीं शताब्दी को भी मान लें तो 400 साल में न तो केरल मुस्लिम बहुल हुआ और न ही 2100 साल में ईसाई हुआ. हम कौन सा खतरा दिखाकर हिन्दुओं को डरा रहे हैं. केरल सहित दक्षिण भारत और बंगाल में हिन्दुत्व का मुद्दा इसलिए भी नहीं चल पाता कि उनका इतिहास उत्तर भारत से अलग है.

बंगाल का इस्लामीकरण

बंगाल का इस्लामीकरण मुगल साम्राज्य के व्यापारियों द्वारा 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 16वीं शताब्दी तक बंगाल एशिया के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र में उभरा. यूरोप के व्यापारियों का आगमन इस क्षेत्र में 15वीं शताब्दी में हुआ और अंततः 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया. 18वीं शताब्दी के आते आते इस क्षेत्र का पूरा नियंत्रण उसके हाथ में आ गया जो धीरे-धीरे पूरे भारत में फैल गया.

पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश एक ही राज्य के दो टुकड़े हैं. बंगाल का विभाजन 19 जुलाई 1905 में तत्कालीन वाइसराय कर्जन ने किया था. 16 अक्टूबर 1905 में यह प्रभावी हो गया. हालांकि यह विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया. दोनों ही प्रदेश ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत थे इसलिए इस विभाजन का वैसा असर नहीं हुआ था जो पाकिस्तान के बनने पर 1947 में हुआ. 1947 में जब देश का विभाजन हुए तब एक बार फिर बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम पर अस्तित्व में आया. 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र हो गया जिसमें भारत की बड़ी भूमिका थी. इसलिए मुसलमानों के खिलाफ बंगाल में भी वैसा आक्रोश नहीं है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या गुजरात में देखने को मिलता है. बांग्लादेश का संविधान उसे इस्लामिक राज्य बनाने के साथ ही उसे पन्थनिरपेक्ष भी घोषित करता है. गंगा-ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर स्थित यह देश, प्रतिवर्ष मौसमी उत्पात का शिकार होता है. इसलिए भारत ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह बांग्लादेश को समर्थन दिया है. भूक्षेत्रफल की दृष्टि से बांग्लादेश जहां विश्व में 92वें स्थान पर है वहीं आबादी के लिहाज से उसका स्थान आठवां है.

लव जिहाद या और कुछ

प्रेमजाल में फंसाकर लड़कियों और युवतियों को शोषण और उत्पीड़न के दलदल में फेंकने की यह कोई पहली घटना नहीं है. देश भर के चकलाघरों में फँसी हुई लड़कियां किसी न किसी के द्वारा प्रेमजाल में फँसाकर ही यहां लाई गई हैं. इसमें प्रेमियों और पड़ोसियों के साथ-साथ सगे रिश्तेदारों का भी हाथ रहा है. हालांकि, आतंकवाद में इस्तेमाल के लिए लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाकर ले जाने की घटनाएं नई हैं. इसका एक अंदाजा राज्यों से गुम हो गई लड़कियों और महिलाओं की संख्या से लगाया जा सकता है. जहां तक केरल का प्रश्न है, केरल से कुल 6608 महिलाएं लापता हो गई थीं जिनमें से 6242 महिलाओं को 2021 तक ढूंढ लिया गया. 366 महिलाओं का अब भी कुछ पता नहीं चला. इसी तरह 951 नाबालिग कन्याएं भी लापता थीं जिनमें से 919 को ढूंढ लिया गया. 32 लड़कियां अब भी लापता हैं. देश की तुलना में ये आंकड़े तुच्छ हैं.

एनसीआरबी द्वारा 2019 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 2019 तक 30570 लड़कियां हमेशा के लिए गुम हो चुकी हैं जिनका कभी कोई सुराग नहीं मिला. 2019 में यह संख्या 52049 हो गई. वैसे वास्तव में घर से भागने वाली लड़कियों की संख्या इससे कहीं अधिक थी. पर इनमें से कईयों का उद्धार कर लिया गया. सबसे ज्यादा लड़कियां बिहार, मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल से गायब हो जाती हैं. इसका एक कारण वहां की आबादी में गरीबों का प्रतिशत भी है. बिहार की ही बात करें तो 2019 के पहले वहां 3904 लड़कियां गायब थीं जो 2019 में बढ़कर 5935 हो गई. मध्यप्रदेश में यह आंकड़ा 2019 से पूर्व 4743 था जो बढ़कर 8572 हो गया. 2019 तक पश्चिम बंगाल की 5883 लड़कियां गुम हो चुकी थीं जिनकी संख्या 2019 में बढ़कर 6499 हो गई. छत्तीसगढ़ में 2019 से पहले 951 लड़कियां मिसिंग थीं जो 2021 में बढ़कर 2606 हो गई. अधिकांश लड़कियों को प्रेम-विवाह या नौकरी का झांसा देकर ही भागने के लिए तैयार किया जाता है.

खूंखार फूलनदेवी की बीहड़ के वनग्रामों में ही नहीं बल्कि आसपास गांवों में भी दहशत

एक वक्त था, जब उसके आतंक से पूरा जंगल कांपता था. खूंखार फूलनदेवी की बीहड़ के वनग्रामों में ही नहीं बल्कि आसपास गांवों में भी दहशत थी. लेकिन जब वह अपने प्राकृतिक रहवास से निकलकर मैत्री का संदेश देने वाले खूबसूरत आधुनिक अरण्य में पहुंची तो उसका ऐसा कायाकल्प हुआ कि उसके शांत और सहिष्णु मिजाज पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ. लेकिन इसके पहले कि प्रकृति प्रेमियों को उसकी खुशमिजाजी का भरपूर दीदार हो पाता उसे अपने इस नए घर को भी अलविदा कहना पड़ा...

» विमल

जी नहीं आप नाम को लेकर कनफ्यूज मत होइए. हम यहां बात अपने जमाने की मशहूर दस्युसुंदरी से सांसद बनने वाली नेत्री फूलन देवी नहीं वरन उस आदमखोर शेरनी की कर रहे हैं, सालों पूर्व जिसकी भयानक दहाड़ें मैत्रीबाग की आबोहवा और वन्य प्राणियों के भाईचारे की सोहबत में गायब हो गई थीं. अस्सी के दशक में गरियाबंद जिला के घनघोर जंगल से मैत्रीबाग लाई गई फूलन देवी नामक जंगल की रानी की दास्तां जितनी दिलचस्प है उतनी ही प्रेरक भी है. फूलनदेवी से वाबस्ता क्षेत्र के प्रबुद्ध प्रकृतिप्रेमियों और मैत्रीबाग से जुड़े लोग इस बेजुबां हिंसक जानवर के हृदयपरिवर्तन को याद कर आज सालों बाद भी रोमांचित हो जाते हैं. छत्तीसगढ़ की जीवनरेखा कलकल बहती महानदी के उद्गम स्थल नगरी सिहावा और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित सोंढूर के निकट हरदीभाठा मैनपुर के भयंकर जंगल में भयानक शेरनी फूलनदेवी का आतंक था. बताते हैं कि वर्ष 1980 के दशक ठंड के मौसम में हरदीभाठा गांव की एक कमार आदिवासी महिला अपने तीन चार साल के बच्चे को लेकर आंवला तोड़ने जंगल गई थी. बच्चे को पेड़ के निकट बिठाकर बांस से आंवला तोड़ने में मशगूल थी,अचानक गुर्राहट

मैत्रीबाग में आने के बाद शेरनी के स्वभाव में आश्चर्यजनक बदलाव देखा गया. मैत्रीबाग से जुड़े लोगों के मुताबिक शेरनी के एनक्लोजर के ठीक सामने सैकड़ों हिरणों और सांभरों आदि चपल व सुंदर जानवरों का बाड़ा था. परिंदों की चहचहाहट भी थी. तत्कालीन मैत्रीबाग प्रभारी वायके सोढ़ी और स्टाफ का बर्ताव भी शेरनी के प्रति दोस्ताना व मनोवैज्ञानिक था. बताते हैं कि कुछ दिनों में ही शेरनी फूलनदेवी इस दोस्ताना और आर्टिफिशियल अरण्य यानी चिड़ियाघर के प्राकृतिक माहौल के चलते अपने हिंस्र मिजाज को भूलकर शांत होने के साथ खाना व दवाई देने वाले कर्मियों के साथ घुलमिल गई. लंगड़ाहट के बावजूद उसकी उछलकूद पर्यटकों को लुभाती थी. लेकिन पंजे का जख्म उसके लिए जानलेवा साबित हुआ और वह कुछ महीने बाद बीमार हो गई. शेरनी फूलन देवी को हवा बदलने पहले भोपाल जू फिर इंदौर भेजा गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह चल बसी.

की आवाज सुनकर जब पलटकर देखा तो एक शेरनी उसके बेटे को लंगड़ाते हुए मुंह में दबाकर ले जा रही थी. घबराई महिला साहसिक मुकाबला कर शेरनी पर बांस से कई वार किए तो वह बूढ़ी और लंगड़ी होने के कारण बच्चे को छोड़कर भाग गई.

हो गई थी आदमखोर

शेरनी फूलनदेवी के पंजों और नुकीले दांतों में दबकर आदिवासी महिला का बच्चा मर चुका था. बच्चे को लेकर वह अपने गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने मुआवजा के बाद ही दफनाने की सलाह दी. घायल शेरनी पहाड़ी पर अपनी मांद में छीने गए शिकार के लिए रातभर दहाड़ती रही. लंबे समय से सोंढूर में वनांचल और आदिवासियों से जुड़े प्रकृतिप्रेमी और बुजुर्ग साहित्यकार इंदुशंकर मनु बताते हैं कि इस बच्चे के साथ अब तक 5 लोगों का शिकार कर वह आदमखोर बन चुकी थी लेकिन गांव के शिकारी व्यक्ति के मुर्गा फंसाने के पिंजरे के तार से उसका पंजा जख्मी होने से लंगड़ाने के साथ वृद्ध भी हो चुकी थी. आतंक बढ़ने पर उसे पकड़ने वन विभाग के अधिकारी असम के प्रसिद्ध शिकारी रहमान खान के साथ गुफा के सामने पिंजरा डाला. पिंजरे के अंदर बकरे की जगह रहमान खुद बैठकर बकरे की आवाज निकालने लगे . जैसे ही शेरनी फूलनदेवी पिंजरे में घुसी पार्टिसन वाले डोर से वे तेजी से बाहर भागे, लेकिन तब तक उनकी एक अंगुली शेरनी के जबड़े का ग्रास बन चुकी थी. पूर्व व्याख्याता श्री मनु बताते हैं कि वर्ष 1991 में शेरनी फूलन देवी को पकड़कर मैत्रीबाग चिड़ियाघर भिलाई में छोड़ा गया था.

जैन संत विराग मुनि गढ़ रहे तपस्या का कीर्तिमान

» नवीन संचेती

इस भीषण गर्मी में जैन संत विराग मुनि 167 वाँ तपस्याओं की ओर बढ़ रहे हैं. वे दिन में दो या तीन बार केवल गर्म पानी पी कर तपस्या कर रहे हैं. प्रतिदिन प्रार्थना, बिना ध्वनिविस्तारक के दैनिक प्रवचन, धर्म, आराधना, सत्संग, धर्म चर्चा करना उनका नित्य प्रतिदिन का कार्य है. इसके साथ ही अपने गुरु भाइयों के लिए आहार लाना, हजारों भक्तों को मंगल पाठ सुनाना उनकी दिनचर्या में शामिल है. इतनी कठिन तपस्या केवल गुरु भगवंतो के आशीर्वाद एवं अरिहंत परमात्मा की दिव्य कृपा से ही संभव हो सकता है. धर्म सभा को संबोधित करते हुए तपस्वी संत श्री विराग मुनि ने कहा, आज मेरे जीवन के 46 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. मेरे हृदय में एक भी व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं है. संसार के सभी जीव मोक्ष की ओर अग्रसर हों बस मेरा इतना ही राग है. उन्होंने कहा, मुझे दो कर्तव्य पूरे करने हैं- पहला मेरे दीक्षा गुरु को शिखर जी की यात्रा करानी हे और मेरे शिष्य रत्न को गिरनार की यात्रा करनी है.

नागपुर के रास्ते पद विहार करते हुए राजनांदगांव-दुर्ग होते हुए श्री विराग मुनि अभी रायपुर मे विराजमान हैं. आगामी चातुर्मास बालाघाट मध्य प्रदेश में होने जा रहा है. किसी जैन संत ने इस भीषण गर्मी में उग्र तपस्या करने का साहस नहीं किया. इतनी बड़ी तपस्या छत्तीसगढ़ में जैन संत द्वारा पहली बार हो रही है.

1 मई 2014 का वह पावन दिन राजस्थान का पाली कभी नहीं भूलेगा. उस दिन परम पूज्य श्री कुशल मुनि जी महाराज की पावन निश्रा में मनोज डाकलिया पत्नी मोनिका, पुत्री खुशी और पुत्र भव्य के साथ एक ही साथ दीक्षा ली और संयम मार्ग की ओर अग्रसर होने का संकल्प पूर्ण किया. नया नाम मिला, विराग मुनि. विराग मुनि ने इसके बाद उज्जैन और नागपुर में चातुर्मास किया. इसके पश्चात तप साधना एवं पद विहार करते परम पूज्य श्री विराग मुनि जी महाराज ने गुप्त उपवास तपस्या प्रारंभ कर दी. दीक्षा के पूर्व जो कभी एक उपवास की साधना भी बड़ी मुश्किल से कर पाता था, गुरु कृपा और नाकोड़ा पार्श्व तीर्थ की ईश्वरी कृपा से आध्यात्म तप संयम साधना की ओर बढ़ता चला गया. वैरागी जीवन जीते हुए उपवास एकासना आयंबिल बेला तेरा अठाई मासश्रमण की तपस्या आपने दीक्षा के पूर्व भी प्रारंभ कर दी. अब वे 167 वाँ तपस्या की ओर अग्रसर हैं.

जिस तरह भगवान महावीर अभिग्रह लेकर तपस्या करते थे उसी तरह श्री विराग मुनि जी महाराज ने अभिग्रह लेकर तपस्या प्रारंभ की थी. श्री विराग मुनि जी के तीन अभिग्रह फलीभूत हो चुके हैं. वर्षीतप उपधान तप सिद्धि तप उपवास एकासना आयबिल तेला अठाई पन्द्रह की तपस्या दिन में दो बार सिर्फ गरम पानी पीकर यह कठिन तपस्या गुरु भगवन तो के आशीर्वाद से निर्विघ्न कर रहे हैं.

छत्तीसगढ़ के माटीपुत्र : कुंजराम

दुर्ग जिले के एक छोटे से गांव मासाभाट निकुम में एक छोटे से परिवार में 26 अगस्त 1942 को पैदा हुए कुंजराम साहू का संपूर्ण जीवन संघर्षमय रहा. प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा गांव में पूरी करने के बाद कुंजराम साहू ने राजनांदगांव के ठाकुर प्यारेलाल सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल में बीए तक की शिक्षा प्राप्त की. ग्रेजुएशन करने के बाद कुंजराम को नौकरी की तलाश थी जो 1965 में खत्म हुई. वे भिलाई इस्पात संयंत्र में नौकरी पाने में सफल हो गए. बीएसपी की सेवा में रहते हुए उन्होंने मजदूर हितों के लिए यूनियन से जुड़ने का मन बनाया. सबसे पहले उनका संपर्क उस समय के चर्चित मजदूर नेता संबल चक्रवर्ती से हुआ. इसी दौरान आनंद मार्ग के संपर्क में आकर वे पूरी तरह आनंद मार्ग के समर्पित कार्यकर्ता बन गए. वे एक कुशल संगठक और छत्तीसगढ़ माटी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे.

» भूपेंद्र वर्मा

उनकी सक्रियता के कारण कुछ ही वर्षों में एक आनंद मार्गी और यूनियन नेता के रूप में उनकी पहचान स्थापित हो गई. इसके बाद वे छत्तीसगढ़ मजदूर कल्याण सभा नामक एक स्थानीय संगठन के संपर्क में आए. इस संगठन का नेतृत्व सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉ विमल कुमार पाठक एवं आदिवासी नेता मेघनाथ ठाकुर कर रहे थे. श्री ठाकुर मूलत: कवर्धा क्षेत्र के रहने वाले थे.

इस संगठन ने उन स्थानीय विस्थापितों के लिए आवाज बुलंद की जिनकी जमीन बीएसपी के लिए अधिग्रहीत की गई थी, पर जिन्हें संयंत्र में नौकरी नहीं मिली थी. स्वभाविक है कि कुंजराम इस आंदोलन से दूर नहीं रह सके. छत्तीसगढ़ मजदूर कल्याण सभा ने पूरी शिद्दत से इस मांग को लेकर आंदोलन किया. इसके परिणाम स्वरूप विस्थापित परिवारों के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर बीएसपी की सेवा में लिया जाने लगा.

25 जून 1975 की रात देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई. आनंद मार्ग से जुड़े होने के कारण तमाम गैर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें भी मीसा में गिरफ्तार कर लिया गया. मीसाबंदी रहने के दौरान उनका परिचय छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नेता जॉर्ज कुरियन से हुआ. चूंकि कुरियन भी संयंत्र कर्मचारी थे. दोनों मजदूरों के हित में संघर्ष करते थे. इसलिए जल्द ही दोनों में गहरी मित्रता हो गई. 21 महीने बाद आपातकाल खत्म हुआ और जेल से छूटकर वे पुन: संयंत्र की सेवा में बहाल हो गए.

मीसा के बाद केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी. राजनांदगांव से प्रसिद्ध समाजवादी नेता मदन तिवारी सांसद निर्वाचित हुए. उन्होंने भिलाई इस्पात संयंत्र के संघर्षशील व समाजवादी विचारधारा के लोगों को जोड़ना शुरू किया. इस तरह जनता यूनियन का गठन हुआ. श्री साहू इस यूनियन में शामिल तो हो गए किंतु दो साल में ही जनता पार्टी टूट गई और 1980 में कांग्रेस पुनः सत्ता में आ गई. मदन तिवारी चुनाव हार गए और जनता यूनियन भी समाप्त हो गई. लेकिन तब तक विस्थापित परिवारों की मांग पूरी हो चुकी थी.

कुंजराम साहू का राजनीति में दोबारा प्रवेश तब हुआ जब छत्तीसगढ़ की अस्मिता को लेकर सांसद ताराचंद साहू ने 2009 में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच का गठन किया. तब कुंजराम साहू एवं पेशे से शिक्षक रहे राधेलाल साहू भी इससे परोक्ष रूप से जुड़ गए. उन्होंने इस पार्टी को मजबूत करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया. पर 11 नवम्बर, 2012 को ताराचंद साहू का निधन हो गया और इसके साथ ही यह आंदोलन भी फीका पड़ गया.

जॉर्ज कुरियन ने बताया कि मीसाबंदी रहने के दौरान कुंजराम के साथ ही उनकी मित्रता गौतम सिंह ठाकुर से भी हुई थी. तीनों ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया. पर कुछ ही वर्षों में छमुमो के नेता शंकर गुहा नियोगी से मतभेदों के कारण उनका इस आंदोलन से मोह भंग हो गया. इसके बाद तीनों ही नेता मजदूर आंदोलन से दूर हो गए और सामाजिक संगठनों में सक्रिय हो गए. 25 मई 2023 की रात कुंजराम का देहावसान हो गया.

स्व. कुंजराम साहू के दो पुत्र एवं एक पुत्री हैं. तीनों विवाहित हैं. उनका परिवार रिसाली के आशीष नगर में निवासरत है. ठेठ छत्तीसगढ़ी का संघर्षमय जीवन जीने वाले स्व. कुंजराम साहू को छत्तीसगढ़ आजतक की विनम्र श्रद्धांजलि.

॥ मंगल भवन,अमंगलहारी ॥

वी वाय हॉस्पिटल, रायपुर

छत्तीसगढ़ का विश्वसनीय सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल

VY HOSPITAL
We care for your Health

Pre Accredited by NABH

8 वर्षों का प्रयास
वर्षों का विश्वास
वर्षों का साथ

शुक्रिया आपके विश्वास का.

वी व्हाय हॉस्पिटल विगत 8 वर्षों से अपनी सर्विसेस के साथ आपकी सेवा में समर्पित है। हमारा आपके प्रति देखभाल का भाव अनंत है और हमारी सफलता का श्रेय आपके विश्वास और सहयोग को जाता है. हम आगे भी दृढ़ता के साथ, आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।

वी वाय मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पिटल विगत 8 वर्षों से उत्कृष्ट ईलाज किफ़ायती दरों पर "नर सेवा, नारायण सेवा" के भाव के साथ आपकी सेवा में समर्पित हैं।

आयुष्मान भारत,बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना (उड़ीसा) एवं सभी इंश्योरेंस द्वारा कैशलेस ईलाज सुविधा

वी वाय हॉस्पिटल, कमल विहार, रायपुर (छ.ग.)

0771-4622222, 7225024301, 7225024302 हेल्पडेस्क: 0771-4622200, टोल फ्री: 1800-123-4775

www.vyhospital.in info@vyhospital.in vyhraipur vyhospitalrpr @vyhraipur

गौण खनिज में शासन को लग रहा लाखों का चूना

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

छत्तीसगढ़ में गौण खनिज का राजस्व हमेशा विवादों में रहा है, रेत, गिट्टी और मुरम से जितनी रायल्टी मिलती थी, उससे ज्यादा की अवैध माइनिंग हो जाती थी. इसलिए 2018-19 में शासन से नीलामी का अधिकार छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम को सौंप दिया. रायल्टी का एक बड़ा मामला तब उजागर हुआ जब छ. ग. राज्य सहकारी विपणन संघ के लिए बनाए गये गोदामों का मामला सामने आया. रायपुर और दुर्ग जिले के 3 स्थानों पर बनाये गये 50-50 हजार मी. टन क्षमता के वेयरहाऊस गोदामों में इस्तेमाल हुए गौण खनिज की रॉयल्टी नहीं पटाई गई थी. विपणन संघ द्वारा एन.सी.डी.सी. के ग्रामीण भण्डार योजना के अतंर्गत लोन लेकर रायपुर एवं दुर्ग के औद्योगिक क्षेत्र के भूमि पर प्रत्येक स्थान पर 50 हजार मी.टन. क्षमता के गोदाम बनाये गये हैं. इन गोदमों के निर्माण में हुई अनियमिताओं के संबंध में विधायकों ने कई बार विधानसभा में मामला उठाया था. जिसे राज्य शासन ने पूरे प्रकरण की जांच कराने हेतु राज्य आर्थिक अपराध अन्वेशषण ब्यूरो को सौंप दिया था. किन्तु जांच आज भी जस की तस पड़ी है.

दरअसल छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ ने 2002-2003 में वित्त पोषित संस्था एन.सी.डी.सी से ऋण पर रायपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा दुर्ग जिले के औद्योगिक क्षेत्र हथखोज एवं बोरई (रसमड़ा) में 50-50 हजार मी. टन. क्षमता के गोदम निर्माण कराया था. इनमें प्रत्येक गोदाम की लागत 6.34 करोड़ रुपए थी. संघ द्वारा निविदा में 2 गोदामों का निर्माण एजेंसी व्ही.आर एण्ड कंपनी गाजियाबाद ने किया था. इस कंपनी ने बोरई तथा सिलतरा गोदाम के निर्माण में लगे रेत, गिट्टी, मुरम इत्यादि की रॉयल्टी की राशि नही पटाई गई थी. इस बात का खुलासा 2017 में इस प्रकार हुआ कि विपणन संघ के कार्यपालन अभियंता के रिटायर्ड हो जाने बाद फाइनल बिल को पारित करने के लिए शासन के माध्यम से लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री के पास

भेजा गया, जिसमें उनके द्वारा बिल की जाँच कर निर्मित गोदाम में लगे खनिज की रॉयल्टी फाइनल बिल से कटौती कर निर्माण एजेंसी (व्ही.आर.एंड कंपनी) भुगतान करवा दी गई थी.

दुर्ग जिले के बोरई गोदाम में निर्मित खनिज की रायल्टी की कटौती कर विभागीय इंजीनियरों ने इसे शासन में जमा ही नहीं कराई, रायल्टी की यह राशि लगभग 14 लाख की है. यह बात खुलकर सामने आती उसके पहले से ही विभागीय इंजीनियरों ने इसका फाइनल पेमेंट कर दिया था.

विभागीय इंजीनियरों पर निर्माण एजेंसी से मिली भगत का आरोप

50 हजार मी.टन. क्षमता निर्मित सभी गोदाम के रनिंग तथा फाइनल बिल भी शत प्रतिशत जांच एवं अनुशंसा सहायक यंत्री एन.एम. देवांगन द्वारा की गई थी बोराई गोदाम की फाइनल बिल की अनुशंसा कर देयक कार्यपालन अभियंता एवं वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से 2006 में पारित कर निर्माण एजेंसी को भुगतान किया गया तथा व्ही.आर.कंपनी की बोरई गोदाम की सुरक्षा निधि अमानत राशि का भुगतान बाकी था. इस जमा राशि से भी रायल्टी की राशि की कटौती की जा सकती थी, किन्तु निर्माण एजेंसी से मिली भगत कर इसकी सम्पूर्ण राशि का भुगतान वर्ष 2017 में सहायक यंत्री एवं प्रभारी यांत्रिकी की अनुशंसा अनुसार कर दी गई, इस प्रकार बोरई गोदाम से शासन को रायल्टी की राशि से लगभग 14 लाख का नुकसान हुआ है. जो बिल, विभागीय मापपुस्तिका इत्यादि दस्तावेजों से जांच कर इनसे वसूली योग्य है.

यहां उल्लेखनीय है, कि श्री देवांगन द्वारा की गई गंभीर अनियमिताएं को देखते हुए उन पर अनुशासिक कार्रवाई नहीं करते हुए उसे आगामी पदोन्नति देने की तैयारी की जा रही है जो कि शासन के नियमों के विपरीत है. उक्त गलतियों को दंड दिया जाना चाहिए न कि पदोन्नति.

भिलाई में आयुध कारखाना स्थापित हो- शांतिलाल जैन

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

संयंत्र की खदानों में लंबे समय तक ठेकेदारी करने वाले 76 वर्षीय शांतिलाल जैन ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर भिलाई में आयुध कारखाना स्थापित करने की मांग की है. अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र से देश के विभिन्न आयुध कारखानों में उपयोग किए जाने वाले सामानों की आपूर्ति की जाती है. यहां पर आयुध कारखाने के लिए पर्याप्त जमीन और पर्याप्त मात्रा में आवासीय भवन शैक्षणिक और चिकित्सकीय संसाधन उपलब्ध हैं. यदि यहां आयुध कारखाना खोला जाता है तो ना केवल भिलाई की रौनक लौटेगी, बल्कि यहां की रिक्त पड़ी हजारों एकड़ जमीन खाली पड़े आवासों और भवनों का उपयोग भी हो सकेगा.

भिलाई इस्पात संयंत्र आयुध कारखानों और भारतीय रेलवे के लिए प्रमुख आपूर्तिकर्ता है. भिलाई में आईआईटी जैसे उन्नत तकनीकी संस्थान भी है. यहां पर शैक्षणिक एवं तकनीकी दृष्टि से संपन्न एवं योग्य युवा कामगारों की कोई कमी नहीं है. इसलिए यहां आयुध कारखानों की स्थापना पर लागत भी कम आएगा. पत्र में उन्होंने लिखा है कि रक्षा मंत्री का भिलाई से गहरा रिश्ता रहा है, इसीलिए भिलाई के विकास में उनकी सहभागिता की विशेष उम्मीद है.

भिलाई इस्पात संयंत्र एवं उसके खदान क्षेत्रों में रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं. संयंत्र और खदानों में कर्मचारियों की संख्या न के बराबर रह गई है. इसके चलते नंदिनी एवं राजहरा टाउनशिप का अस्तित्व ही संकट में आ गया है. भिलाई नगर की टाउनशिप ही अपने अस्तित्व के लिए छटपटा रही है. भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा संचालित अधिकांश शिक्षा संस्थान और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद हो चुके हैं. कभी पूरे मध्य भारत में सर्वश्रेष्ठ अस्पताल माना जाने वाला संयंत्र का पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र सेक्टर- 9 भिलाई भी रिफर सेंटर बन कर रह गया है.

दल्लीराजहरा में लौह अयस्क से सिलिका सफाई के लिए सेल द्वारा लगभग 150 करोड़ की लागत से सिलिका प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा 24 जून 2023 को किया गया. डस्ट के रूप में बचे लाखों टन लौह अयस्क को ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए यह एक अच्छी पहल है. इससे निश्चित ही दल्लीराजहरा से बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन पर आंशिक रोक लग सकेगी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है. दल्लीराजहरा और नंदिनी नगर का अस्तित्व बचाने के लिए यहां बेकार पड़ी संयंत्र की हजारों एकड़ जमीनों का सदुपयोग करना जरूरी है. यहां अन्य औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के साथ ही शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थानों को पुनर्जीवित एवं उन्नत करना जरूरी है.

जहां तक भिलाई का सवाल है, यहां के तमाम संगठनों द्वारा संयंत्र की रिक्त पड़ी हजारों एकड़ जमीन व इतनी ही संख्या में रिक्त पड़े कार्मचारी आवासों के सदुपयोग की मांग की जा रही है. रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए नए औद्योगिक एवं व्यवसायिक संस्थानों की स्थापना हेतु भी आवाज उठाई जा रही है.

» ऑनलाइन आर्डर कर रहे प्रदेश के युवा
» एक मां की शिकायत पर खुला मामला
» दिवास्वप्न दिखाती है नशे की यह पुड़िया
» दुनिया के कई देशों में है प्रतिबंधित

मेक्सिको से आ रहे हैं ड्रग्स के पार्सल

प्रदेश के युवा अब नशे की खुराक ऑनलाइन आर्डर कर रहे हैं. मोबाइल पर आर्डर हो रहा है और सुदूर मेक्सिको से इस खतरनाक ड्रग का पार्सल घर पहुंच रहा है. इस नशे के खिलाफ केवल एक ही बात जाती है और वह है इसकी कीमत. हर किसी की इतनी औकात नहीं कि वह यह नशा कर सके. एक ऐसे ही मामले का खुलासा छत्तीसगढ़ की एक मां द्वारा पुलिस से की गई शिकायत के बाद हुआ है.

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की अनुसूया (परवर्तित नाम) ने पुलिस को एक शिकायत पत्र दिया. इसमें उन्होंने आशंका जताई थी कि उनका बेटा नशे का पार्सल मंगवाता है. पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिए और उनके पते पर आने वाले सभी पार्सलों की निगरानी शुरू कर दी. इसमें एक पार्सल मेक्सिको से आया था. खोलने पर उसमें से एक नशीला पदार्थ निकला. इसे अंतरराष्ट्रीय ड्रग मार्केट में मैजिक मशरूम साइक्लोबिन के नाम से जाना जाता है.

मैजिक मशरूम साइक्लोबिन दुनिया के कई देशों में बैन है. हालांकि कुछ देशों में इसका उपयोग डिप्रेशन की दवा के रूप में किया जाता है. इसका नशा करने पर लोग एक रूमानी दुनिया की सैर करने लगते हैं. उन्हें अपने चारों तरफ, सबकुछ बेहंद रंगीन और खुशगवार लगता है. पार्सल में यही प्रतिबंधित दवा मैजिक मशरूम साइक्लोबिन पाया गया. यह पार्सल मेक्सिको से आया था. इसे ऑनलाइन आर्डर किया गया था. इसके 67 मिलीग्राम की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10 हजार रुपए के करीब है. युवक के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे पुनर्वास केन्द्र में भेज दिया गया है.

कैसे काम करता है मैजिक मशरूम

मैजिक मशरूम में मनोदशा को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करने वाला कम्पाउंड सिलोसायबिन (Compound Psilocybin) पाया जाता है. मशरूम में यह नैचुरल तौर पर होता है. सिलोसायबिन मस्तिष्क के खास हिस्से को एक्टिव करता है, जिसका मानसिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है. यह पदार्थ डिप्रेशन पैदा करने वाले ब्रेन सर्किट को फिर से ठीक कर देता है. डिप्रेशन की स्थिति में ब्रेन के विशेष हिस्से में रक्त का प्रभाव कम हो जाता है.

60 मरीजों पर हुआ क्लीनिकल ट्रायल

पिछले साल साइलोसाइबिन के असर को समझने के लिए 60 मरीजों पर क्लीनिकल ट्रायल्स किए गए. साइलोसाइबिन लेने के बाद इन सभी मरीजों के दिमाग की वायरिंग ज्यादा सक्रिय हो गई. यदि अधिक रिसर्चर्स एक उचित अनुभवजन्य स्टडी कर सकते हैं. यदि यह साबित हो जाए कि आहार में मैजिक मशरूम को शामिल करने से अवसाद ठीक हो सकता है, तो यह हजारों और लाखों लोगों के लिए फायदेमंद होगा. ये बहुत सारा पैसा भी बचाएगा.

● **आस्था डिंगरा, साइकोलॉजिस्ट**

इसलिए बढ़ी मैजिक मशरूम की डिमांड

जीवनशैली में बदलाव और काम के बढ़ते बोझ के साथ डिप्रेशन या अवसाद की समस्या लगातार बढ़ी है. आम भारतीय परिवारों में डिप्रेशन को कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती. लोगों को लगता है कि डिप्रेशन की बात सार्वजनिक हुई तो उन्हें पागल समझ लिया जाएगा. पिछले साल एक स्टडी में खुलासा हुआ कि महज एक मशरूम (Mushroom) खाने से डिप्रेशन ठीक हो सकता है. पर यह कोई आम मशरूम नहीं बल्कि मैजिक मशरूम होना चाहिए. यहीं से इसकी डिमांड बढ़ी और लोगों ने इसे ऑनलाइन आर्डर करना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे इसकी पहचान नशे की खुराक के रूप में होने लगी.

पारम्परिक दवा से ज्यादा कारगर

मैजिक मशरूम में मिलने वाला साइलोसाइबिन (Psilocybin) किसी भी सामान्य एंटीडिप्रेसेंट की तरह ही काम करता है. लेकिन इसकी तीव्रता और क्षमता ज्यादा होती है. मैजिक मशरूम में ऐसा हैल्यूसिनोजेनिक पदार्थ होता है, जो दिमाग को हाइपर कनेक्टेड ब्रेन (Hyper-Connected Brain) बना देता है. इसका साइकेडेलिक (Psychedelic) पदार्थ डिप्रेशन को रोकता है और नकारात्मक विचारों से दूर रखता है.

LEELA'S PUBLIC SCHOOL
World Class K-12 Schooling
Affiliated with CBSE, New Delhi
Affiliation no. 3330368
LEELA'S PUBLIC SCHOOL
ADMISSION OPEN
• MATHS
• BIO
• COMMERCE
• HUMANITIES
NURSERY TO CLASS XII
Motipur, Jamgaon Road, Tah. Patan, Dist. - Durg (C.G.),
info@leelasgroup.com
www.leelasgroup.com
8319870997, 8370077700

मोदी सरकार के नौ साल
पूछे नौ सवाल

छत्तीसगढ़ में भाजपा लगातार चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है. इसमें सबसे बड़ा मुद्दा शराबबंदी का है. पर इधर देश के कई राज्यों में केन्द्र सरकार के खिलाफ भी वादाखिलाफी के आरोप लग रहे हैं. विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के नौ साल के कार्यकाल को लेकर नौ सवाल पूछे हैं. इनमें से प्रमुख है भ्रष्टाचार का खात्मा, जाली नोटों की रोकथाम, आतंकवाद का सफाया और प्रतिवर्ष दो करोड़ युवाओं को नौकरी. विपक्ष का दावा है कि मोदी सरकार इनमें से एक भी मोर्चे पर सफलता दर्ज नहीं कर पाई है.

» राहुल गौतम

छत्तीसगढ़ में भाजपा लगातार चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है. इसमें सबसे बड़ा मुद्दा शराबबंदी का है. वहीं दूसरी ओर इधर देश के कई राज्यों में केन्द्र सरकार के खिलाफ भी वादाखिलाफी के आरोप लग रहे हैं. विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के नौ साल के कार्यकाल को लेकर नौ सुलगते हुए सवालों पर जवाब मांगा है. इनमें से प्रमुख है भ्रष्टाचार खत्म करना, जाली नोटों की रोकथाम, आतंकवाद का सफाया और प्रतिवर्ष दो करोड़ युवाओं को नौकरी. विपक्ष का दावा है कि मोदी सरकार इनमें से एक भी मोर्चे पर सफलता दर्ज नहीं

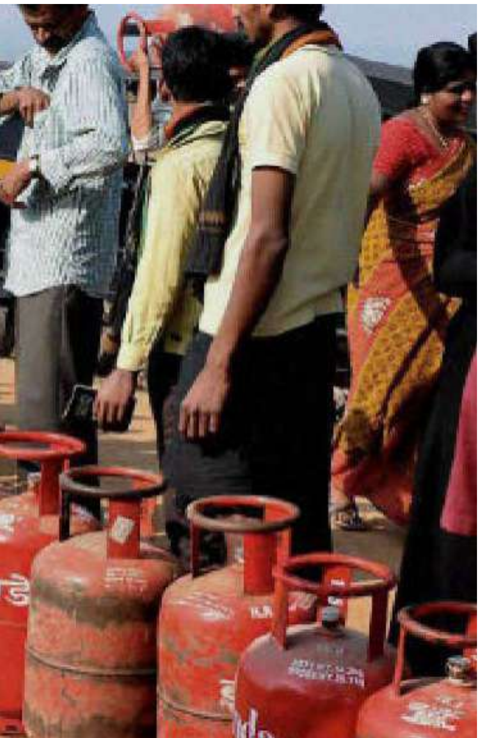

न आया काला धन, न बचा पाए खुद का छापा नोट

जिगरी को बचाने, लुटा दी देश की सार्वजनिक संपत्ति

कहां गया हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा

महिला पहलवानों को उठा ले गई पुलिस, बदला बयान

कर पाई है. मोदी सरकार का दावा था कि वह विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे. लोगों ने तो अपने खाते में रकम आने की उम्मीदें तक बांध ली थी. पर 9 साल बीतने के बाद भी विदेशी खातों में जमा एक रुपया भी भारत नहीं आ पाया है. बल्कि सरकार ने इस दिशा में प्रयास करना भी छोड़ दिया है.

मोदी सरकार ने आतंकवाद को खत्म करने का भी दावा किया था. आरंभिक वर्षों में घटनाएं कुछ कम जरूर हुईं पर यह पूरी तरह से खत्म नहीं हुई. आतंकवादी घटनाएं और देश के भीतर नक्सल घटनाओं पर रोक नहीं लगाई जा सकी है. हालांकि गृहमंत्री अमित शाह कुछ ही दिन पूर्व छत्तीसगढ़ में दावा करके लौटे हैं कि नक्सलवाद का जल्द ही खात्मा कर दिया जाएगा. इस दिशा में एक मात्न बात केन्द्र के खाते में जाती है, वह है पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक.

मोदी सरकार ने देश में सौ स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी. पर इनमें से एक भी शहर आज तक अस्तित्व में नहीं आया है. कुछ शहरों में अधोसंरचना विकास मद में काम जरूर हुआ है, पर इसमें स्मार्ट सिटी बसाने जैसी कोई बात नहीं है. केन्द्र का सबसे बड़ा वायदा हर साल शिक्षित बेरोजगारों के लिए दो करोड़ नौकरियां पैदा करने का था. इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होता रहा है. जब सेना में 'अग्निवीरों' की भर्ती शुरू हुई तो उल्टे केन्द्र पर सेना में ठेका मजदूर प्रथा शुरू करने के आरोप लगे. खेती किसानी में नई अड़चनें आईं जिसे लेकर किसानों को लंबा आंदोलन करना पड़ा. चुनावी घोषणा पत्न में हर वर्ष दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था. उनके अनुसार अभी तक 18 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी मिल जाना था. संसद में सरकारी नुमाइंदों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वर्तमान में देश में बेरोजगारों की संख्या उससे भी अधिक है. अशिक्षित और कोरोना के बाद उद्योगों में बेकार हुए लोगों की तादाद इससे कई गुना ज्यादा है. रोजगार के अवसर दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं. रोजगार देने के मुद्दे पर सवाल किये जाते हैं लेकिन मोदी भक्तों को रास नहीं आता. वे प्रश्न पूछने वालों को कांग्रेसी अथवा पाकिस्तानी घोषित कर देते हैं. प्रधानमंत्नी ने यह भी कहा था कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे. उन्होंने कहा कि 2022 तक सभी के पास अपना खुद का पक्का मकान होगा पर अभी 2023 चल रहा है. पीएम ने वादा किया था कि अब महिलाओं पर कोई अत्याचार नहीं होगा. सबका साथ सबका विकास होगा और अच्छे दिन आएंगे. क्या प्रधानमंत्नी और प्रचंड बहुमत से दूसरी बार सत्ता में आई उनकी सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा किया है. कांग्रेस का कहना है कि भले ही अच्छे दिन नहीं आए है लेकिन यह जो झूठे दिन और झूठे सपने दिखाए हैं, उसके सिर्फ अब मात्न एक साल ही बचे हैं. यह जो झूठ, लूट, नफरत और हिंसा समाज का जाति, धर्म के नाम पर बंटवारा किया जा रहा है, इसके अब एक साल ही शेष हैं.

देश में कांग्रेस के भ्रष्टाचार और कुशासन से त्नस्त जनता को दूर कर चौतरफा सब्जबाग दिखाकर दो बार केंद्र की सत्ता में काबिज भाजपा सरकार अपने नौ साल पूरे होने का जश्न मना रही है. लेकिन अवाम पूछ रही है कि मोदी सरकार आखिर किस बात का जश्न मना रही है और उसे इस तरह का उत्सव मनाने का क्या नैतिक अधिकार है ? कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष ने भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जिस तरह से इस सरकार ने वादाखिलाफी की है, उसके चलते देशवासी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. क्योंकि कांग्रेस के जिस शासनकाल को कोसते हुए चौतरफा वादे कर मोदी सरकार सत्ता में आई, उसने अपना एक भी वादा अब तक पूरा नहीं किया है. कांग्रेस ने सरकार के नौ साल पूरे होने पर नौ सवाल दागते हुए कहा है कि इस दौरान सरकार का मोदी मैजिक पूरी तरह से धाराशायी हो गया है और देश में बेरोजगारी, महंगाई, दोस्तीकरण के नाम पर निजीकरण, लोकतांत्निक संस्थाओं का पतन और महिला उत्पीड़न बेहिसाब बढ़ने के साथ अराजकता और नफरत का बाजार तेजी से फैला है.

सरकार से उसके अधिनायकवाद पर सवाल पूछने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरह विपक्ष और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं को अपनी जेबी जांच एजेंसियों का चाबुक दिखाने और देशद्रोही जैसे न जाने कितने ही तमगों से नवाजने वाली केंद्र सरकार ईमानदारी से बताए कि क्या वह अपने वादों से संबंधित एक भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में है. कांग्रेस के यह नौ सवाल कोई काल्पनिक या राजनीति से प्रेरित नहीं बल्कि 2014 के बाद पीएम मोदी के भाषणों से निकल कर आए हैं. सौ टके का एक सवाल यह है कि महंगाई, बेकारी और भ्रष्टाचार बढ़ाने और कुछ विकास नहीं करने जैसे जिन आरोपों को लेकर तत्कालीन मनमोहन सरकार को गुनाहगार करार देकर सत्ता हथियाने वाली मोदी सरकार खुद यदि इसी तरह की विसंगतियों को बढ़ावा दे रही है तो फिर दोनों में फर्क क्या है? क्या यह उस जनता के साथ छलावा नहीं है, जिसे पूर्ववर्ती सरकार की एंटी इन्कमबेंसी से बरगला कर मोदी सरकार सत्तारूढ़ हुई. विपक्ष के मुताबिक मोदी सरकार ने अपने घोषणापत्न और वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया है. प्रधानमंत्नी मोदी ने चुनाव पूर्व वादे किए थे कि

महंगाई पर सरकार लाजवाब

तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां लुटा कहां...
विपक्ष के सवालों पर मोदी सरकार का रवैया कुछ इसी तरह होता है. वह सवाल का कोई जवाब न देकर हिंदू, मुस्लिम, धर्म के नाम पर पाखंड और पिछले साठ साल में कुछ नहीं हुआ की बातें कहने लगती है. कांग्रेस का सवाल है कि अर्थ व्यवस्था को पलीता लगाने वाली बेरोजगारी की तरह क्या महंगाई कम हुई. सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं होता कि नौ साल में कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला और 2013 में कांग्रेस शासनकाल में 450 रुपए में मिलने वाला रसोई गैस सिलेंडर 1150 रुपए में क्यों मिल रहा है. क्या इस देश की कंपनियां बंद नहीं हो रही हैं. क्या देश की सार्वजनिक संपत्ति को मोदी अपने दोस्त को नहीं बेच रहे हैं. भाजपा अडानी की संपत्ति को ही देश की अर्थव्यवस्था समझ रही है. अपने दोस्त के विकास को ही देश का विकास समझ रही है. क्या इस देश में किसानों की खुदकुशी का आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है? क्या पीएम बताएंगे कि देश के किसान 1 साल से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन क्यों कर रहे थे और क्या सरकार उन्हें समझाने में फेल्योर साबित नहीं हुई. यदि देश में खुशहाली आई है तो किसान क्यों आंदोलन और आत्महत्या कर रहे हैं? यदि किसानों की आमदनी इतनी बढ़ गई है तो भाजपा नेता अपने बच्चों को किसान क्यों नहीं बनवाते हैं? गृहमंत्री अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी क्यों बनाते हैं, किसान बना देते. खुशहाली है तो जवान क्यों नाखुश हैं और महिलाएं क्यों सुरक्षित नहीं हैं? जब राजधानी में ही सरेआम नाबालिग बच्ची की क्रूर हत्या कर दी जाती है तब फिर अन्य शहरों और दूरदराज के गाँवों का क्या हाल होगा. दिल्ली में देश के लिए मेडल लाने वाली ओलम्पियन महिला पहलवानों को बलपूर्वक इसलिए उठा दिया जाता है क्योंकि उनका यौन उत्पीड़न करने वाले अपने सांसद और बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल नहीं भेजना है. लखीमपुर खीरी के अजय मिश्रा की तरह निर्लज्ज सुरक्षा कवच यानी रामराज वाली मोदी सरकार का यह कैसा इंसाफ है कि एक तरफ तो देश का गौरव बढ़ाने वाली महिला पहलवान बेटियों पर दिल्ली पुलिस द्वारा खदेड़कर उनके आंदोलन को खत्म करवाया जाता है और विपक्षी नेताओं पर फर्जी केसों की बिना पर ईडी के छापे मारे जाते हैं. वहीं दूसरी ओर ब्रजभूषण जैसे यौन पिपासुओं के लिए सरकार ढाल बनी हुई है. सच्चाई तो यह है कि आज देश में जिस तरह बेटियाँ महफूज नहीं हैं, छोटे व्यापारी परेशान हैं उसी तरह देश का प्रथम उत्पादक अन्नदाता कभी अनाज, गन्ना तो कभी टमाटर और प्याज की कीमत नहीं मिलने पर विरोध में सड़कों पर फेंककर कर घुट-घुटकर जी रहा है.

सौ दिन में विदेश से काला धन वापस लेकर आएंगे और आतंकवाद खत्म करेंगे. इन नौ सालों में सरकार ने देश के लिए क्या किया है, ऐसे ज्वलंत सवालों को पूछना लाजिमी है. लोकतंत्र में सवाल और विपक्ष दोनों जरुरी है. क्या विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस सरकार से आपातकाल, महंगाई और भ्रष्टाचार पर लोहिया, जेपी, अटल, बिहारी वाजपेयी और मोदी ने सवाले नहीं पूछे थे. तब तो सरकार ने इन्हें राष्ट्रद्रोही या ईडी का आरोपी नहीं बताया था. कांग्रेस ने देश और जनता की ओर से जो पहला सवाल यह है कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री ने जो तमाम दावे किए थे, उनमें से एक भी वादे क्या इन नौ साल में पूरे हुए हैं? क्या सौ दिन में काला धन वापस आया? जो नोट वो खुद लेकर आए थे, उसे ही बंद करवा दिया. नोटबंदी से देश की अर्थ व्यवस्था का जिस बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, व्यापार और उद्योग कैसे चौपट हुए, यह अब किसी से छिपा नहीं है. प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे. क्या यह वादा पूरा हुआ. मोदी सरकार को भ्रष्टाचारी सिर्फ कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के नेता ही दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें वे ज्यों-ज्यों आम चुनाव करीब आता है, चुन चुनकर जांच एजेंसियो के दायरे में ला रहे हैं और जेल में डाल रहे हैं. भ्रष्टाचारी जब तक भाजपा में नहीं है, तब तक तो उस पर कार्रवाई होती है, जैसे ही वह भाजपा में शामिल होता है, वाशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाता है. उस पर कार्रवाई

अडानी पर इतनी मेहरबानी क्यों

पीएम मोदी और उनकी सरकार पप्पू दुष्प्रचारित किए जाने वाले राहुल गांधी के इस सवाल का भी जवाब नहीं देते कि आखिर अडानी की शेल कंपनी में बीस हजार करोड़ रुपए किसका है? पीएम आखिर क्यों खदान और स्टेशन से लेकर सार्वजनिक संपत्ति तक सब अपने जिगरी दोस्त अडानी के नाम किए जा रहे हैं. राहुल गांधी के इस आक्रामक सवाल से मोदी इस कदर घबराए कि पहले तो आश्चर्यजनक तरीके से सत्तापक्ष से कई दिनों तक बहिष्कार कराया, जब इतने से भी बात नहीं बनी तो उनकी सांसदी ही खत्म करवाकर जगहँसाई की भी परवाह नहीं की. गोदी मीडिया मोदी को विश्व नेता प्रचारित करने में लगा हुआ है. लेकिन होशोहवास में उनके द्वारा किए गए वादों पर उनकी तरह कोई सवाल नहीं करता है. नौ साल में नौ प्रेस कान्फ्रेस होना था लेकिन गुजरात के क्रिकेट स्टेडियम से लेकर विदेशों और ओडिशा में हालिया रेल हादसे में इवेंट के अवसर की तलाश में शोमैन मोदी अपना इंटरव्यू किसी निष्पक्ष जर्नलिस्ट को नहीं पसंदीदा एक्टर को देते हैं. एक्टर भी सवाल देश समाज की बजाए व्यक्तिगत खाने पीने के करता है. पीएम बताते हैं कि आम कैसे खाते हैं, कितने घंटे सोते हैं, क्या पहनते हैं. अरे साहब यह बताइये कि हम खाएं कैसे, जिएँ कैसे, रोजगार कहाँ मिलेगा. आप कैसे खाते हैं क्या पीते हैं, उससे भला आम आदमी का क्या लेना देना. उसे तो बस इतना मालूम है कि सिलेंडर 12 सौ रुपए में खरीदना पड़ रहा है और पेट्रोल सौ से ऊपर पहुंच गया है और गंभीर बीमारी में अस्पताल पहुँच गए तो फिर घर जमीन और जिंदगी की जमापूंजी इलाज में निकल जाती है. मोदी के हैट्रिक का दावा करने वाली सरकार के मंत्री जरा बताएं कि महंगाई दुगुनी कैसे हो गई, आम आदमी किस तरह परिवार चलाए. आज इन्फ्लुएशन रेट का डाटा दिखाने वाले भाजपा सरकार के मंत्री और बड़बोले प्रवक्ता बताएं कि देश ने 2014 में का प्रधानमंत्री चुना है कि वास्कोडिगामा चुना है जो नेहरु को पीछे ढकेलने की सनक में विश्व के तीर्थाटन का रिकार्ड बनाकर भारतीय मूल के लोगों के प्रायोजित इवेंट में संबंधित देशों के प्रमुखों को आमंत्रित कर खुद के कसीदे पढ़वा कर गोदी मीडिया से अपना डंका बजवा रहे हैं. उनकी पूरी सरकार त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव. यानी प्रधानमंत्री सिर्फ पीएम ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और स्पीकर व तमाम मंत्री भी हैं. जो मन करता है वह बन जाते हैं. शिकस्त खाने वाले हिमाचल के चुनाव हों या फिर कर्नाटक के कहीं भी भाजपा सरकार महंगाई, बेरोजगारी और देशव्यापी लकवाग्रस्त कानून व्यवस्था का सवाल नहीं उठाती, उसके चुनावी मुद्दे बस हिंदू मुस्लिम, लव जिहाद, बजरंग दल को बजरंगबली बताने वाले होते हैं. कश्मीर मणिपुर सुलग रहे हैं, आम आदमी गरीबी व बेहिसाब मूल्यवृद्धि से परेशान है लेकिन केंद्रीय मंत्री व प्रवक्ता कहते हैं कि क्या महंगाई कम करना और रोजगार देना प्रधानमंत्री का काम है? अरे भाई क्या रेल मंत्री बनकर नई रेल की झंडी दिखाना और बिजली मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री की जगह खुद बिजली खंभे और हाईवे या फ्लाईओवर का उद्घाटन करना प्रधानमंत्री का काम है?

नहीं होती है और ईडी सीबीआई उसका पता भूल जाती है. भाजपा कह रही है भारत दुनिया की सबसे बड़ी पांचवीं अर्थ व्यवस्था बन गई है. यदि भारत पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था बन गई है, तो इस नाते देश में समृद्धि और खुशहाली आ जानी चाहिए थी. इसके विपरीत आज करोड़ों भारतीय जीविकोपार्जन के लिए बेइंतिहा जद्दोजहद कर रहे हैं.

मेक इन इंडिया बनाम मेड इन फारेन

कांग्रेस का यह भी सवाल है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है पर किसका? देश की कंपनियों का या फिर विदेशों की कंपनियों का. मेक इन इंडिया का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि भारत के अंदर बन रहा है, मतलब होता है कि भारत के लोग बना रहे हैं, भारत के लोगों के लिए बना रहे हैं. बताइये कि देश के लोग जितनी भी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें से कितना सामान भारत की कंपनियां बना रही हैं. सभी अपना मोबाईल निकालकर देख लीजिए, कम्प्यूटर, लैपटाप, टैबलेट लीजिए क्या वह मेक इन इंडिया है. क्या मोबाईल का कैमरा भारत में बना है. हकीकत यह है कि पहले जो चीजें भारत के लोगों द्वारा भारत के लिए बनाई जाती थीं, यह स्थिति पूरी तरह से बदल गई है. कांग्रेस के मुताबिक

मेक इन इंडिया का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि भारत के अंदर बन रहा है, मतलब होता है कि भारत के लोग बना रहे हैं, भारत के लोगों के लिए बना रहे हैं. बताइये कि देश के लोग जितनी भी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें से कितना सामान भारत की कंपनियां बना रही हैं.

सरकार दावा करती है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त दे रहे हैं, मतलब जो 80 करोड़ लोग हैं, वह 5 किलो अनाज लेने की स्थिति में नहीं है. यह कैसी आर्थिक मजबूती है. जब कांग्रेस महिलाओं को बस में फ्री पास देने की बात करती है, 10 लाख का इंश्योरेंस देने की बात करती तो मोदी सरकार कहती है कि यह रेवड़ी पॉलिटिक्स हो रही है. लेकिन क्या पुराने संसद भवन के रहते 20 हजार करोड़ की लागत से नई पार्लियामेंट बनवाना पीएम के लिए 8 हजार करोड़ का आलीशान प्लेन खरीदना क्या यह देश के पैसे की बर्बादी नहीं है. इन पैसों से हमारे आपके बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल में उपकरण खरीदे जा सकते थे, सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल बनवाया जा सकता था. विपक्ष पूछ रहा है कि यह कैसा मेक इन इंडिया है, कैसा नया भारत है.

परिवारवाद और सामाजिक सद्भाव पर चुप्पी क्यों?

कांग्रेस का सवाल है कि मोदी सरकार में गरीब और गरीब हो रहा है उसकी आमदनी कम हो रही है और पूँजी सिर्फ एक दो उद्योगपतियों की बढ़ रही है. पिछले सात साल में देश के 80 प्रतिशत लोगों की आमदनी कम हो गई है तो फिर सिर्फ अडानी जैसे एक दो लोगों की आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी कैसे बढ़ रही है. कारण यह है कि सरकार किसानों के खाद पर तो जीएसटी लाद देती है लेकिन अपने दोस्त अडानी को जिसे एयरपोर्ट दिया है, उसकी जीएसटी को माफ कर दिया जाता है. बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर देते हैं, पर कर्ज नहीं चुका पाने के चलते किसान आत्महत्या कर रहे हैं. राहुल के सवाल शेल कंपनी में 20 हजार करोड़ रुपए कैसे आए का कोई जवाब सरकार नहीं देती. देश को सांप्रदायिकता के नाम पर एक बार फिर विभाजन की ओर ले जाया जा रहा है. आम चुनावों के दौर में भाजपा और सैकड़ों आरएसएस सहित अनुषांगिक के राजनीतिक और सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमों की बाढ़ आ गई है. वोटबैंक को पुख्ता करने देश को धर्म व जातियों में बांटा जा रहा है. " विश्व महानायक " को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर सैकड़ों साल के सांप्रदायिक सद्भाव के पैरोकार 25 करोड़ से अधिक मुस्लिम और ईसाई तथा करोड़ों दलितों के बिना क्या भारत सांस ले पाएगा. सरकार यह क्यों नहीं समझती कि हिंदुस्तान को बनाने में देश के सभी लोगों का खून शामिल है. अगर इस देश में अशफाक उल्ला खान हैं तो रामप्रसाद बिस्मिल भी हैं. महात्मा गांधी हैं तो मौलाना अबुलकलाम आजाद भी हैं. सभी ने अपना खून पसीना बहाया है. आखिर क्यों छद्म राष्ट्रवाद व देशप्रेम का ऐसा खेल खेला जा रहा है कि अब उनके ही कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक हवाई मार्ग से हेलीकाप्टर जानबूझकर नहीं भेजने और फर्जी पुलवामा नरसंहार होने देने का खुलासा कर रहे हैं. मोदी सरकार के मीडिया मुँहजोर कांग्रेस के इस सवाल के जवाब पर भी बगलें झाँकने या कुतर्क पर उतारू हो जाते हैं कि क्या भाजपा में परिवारवाद नहीं चल रहा है. कांग्रेस को परिवारवाद बताने वाले यह नहीं बता पाते कि जब अनुराग ठाकुर को सांसद व मंत्री बनाया गया तो परिवारवाद नही दिखता, रक्षा मंत्री शाह के बेटे को बीसीसीआई का सचिव बनाते हैं तो परिवारवाद नहीं दिखता. कांग्रेस ने पीएम के सामाजिक न्याय पर भी सवाल पूछा है कि जब चुनाव आता है तो मोदी ओबीसी हो जाते हैं. जब आप ओबीसी हैं तो जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं. 2011की जनगणना की रिपोर्ट अब तक प्रकाशित करने की जहमत नहीं उठाई गई है. विपक्ष का कहना है कि सामाजिक न्याय का मतलब तो यही हुआ न कि हर क्षेत्र में रहने वाले जितने लोग हैं, इतने लोगों के अनुपात के आधार पर उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना. इमरजेंसी और भ्रष्टाचार के नाम पर ईडी का हंटर दिखा कांग्रेस मुक्त भारत की मुहिम चलाने और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़कर सत्ता में बार-बार काबिज होने की कवायद से सत्ता जरूर हाँकी जा सकती है लेकिन देश को नहीं चलाया जा सकता. और जब देश लड़खड़ाएगा, अभिव्यक्ति को कुचला जाएगा, समाज सिसकेगा और प्रजातांत्रिक संस्थाओं पर बेड़िया डाली जाएंगी तो जनता जनार्दन गण और तंत्र को बचाने चुनाव का भी इंतजार नहीं करेगी. सरकार को यह समझना चाहिए कि निंदक नियरे राखिये... की तरह विपक्ष की मजबूती और व्यवस्था के सुलगते सवालों से ही लोकतंत्र मजबूत होगा. क्योंकि सत्यमेव जयते और सत्यम शिवम सुंदरम ही भारत देश और इसके संविधान की आत्मा है. समावेशी समाज का इंद्रधनुष इसकी देह है.

सुश्री सरोज पाण्डेय
राज्यसभा सांसद
अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला मोर्चा
राष्ट्रीय महासचिव, बीजेपी
पूर्व विधायक, वैशालीनगर विधानसभा
पूर्व महापौर, न.पा.नि. दुर्ग
राजनीतिक परिचय
छात्र संघ
महिला महाविद्यालय भिलाई में छात्राओं ने लगातार दो बार छात्रसंघ अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी और यही से सरोज पाण्डेय ने अपनी राजनैतिक कैरियर की शुरूआत की। ये वर्ष 1989 से 1991 तक इस पद की जिम्मेदारी एक प्रखर छात्र संघ नेता के रूप में निभायी।
नगर पालिका निगम में 10 साल तक महापौर
सुश्री सरोज पाण्डेय ने दुर्ग शहर से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत नव निर्वाचित होकर लगातार दो बार महापौर पद पर दुर्ग निगम के छत्तीसगढ़ मॉडल निगम को बेहतर बनाया। उस समय की दुर्ग निगम की योजनाओं को प्रदेश के सभी निगमों ने अपनाया। सुश्री सरोज पाण्डेय देश की एकलौती महापौर रही, जो सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीतकर महापौर बनी थी।
पुन: महापौर
सर्वश्रेष्ठ महापौर का पुरुस्कार 10 वर्षों का रिकार्ड
विधायक
विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-66, वैशाली नगर
(दिनांक 08.12.2008 से 31.05.2009 तक)
लोकसभा
लोकसभा क्रमांक-07 दुर्ग छत्तीसगढ़, 2009-2014
राज्यसभा सांसद - 2017 से अब तक
वर्ल्ड रिकार्ड बनाया...
सुश्री सरोज पाण्डेय ने एक ही अवधि (समय) में महापौर, विधायक व सांसद के निर्वाचित प्रतिनिधि के दायित्वों का निर्वहन हेतु लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड 2010 में अपना नाम रजिस्टर्ड कराया। सुवा नृत्य में 12 हजार प्रतिभागियों ने एक साथ नृत्य का वर्ल्ड रिकार्ड भी दर्ज करवाया।
संगठन दायित्व
प्रवक्ता भा.ज.पा. छत्तीसगढ़ (2004 से 2008)
राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य युवा मोर्चा
महामंत्री भा.ज.पा. छत्तीसगढ़
राष्ट्रीय मंत्री भा.ज.पा. (प्रथम 2008 से 2009)
पुनः राष्ट्रीय मंत्री भा.ज.पा. (2009 से 2012)
राष्ट्रीय अध्यक्ष भा.ज.पा. महिला मोर्चा (2012 से 2014)
राष्ट्रीय महामंत्री भा.ज.पा. (2014 से 2019)
विगत 30 वर्षों से छत्तीसगढ़ एवं राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय
सुश्री सरोज पाण्डेय जी
के जन्मदिन के इस मौके पर रामगोपाल शर्मा ने मुलाकात कर उन्हें बधाई दी और उनके स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना की
राकेश पाण्डेय जी
वरिष्ठ भाजपा नेता
राम गोपाल शर्मा
वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला उपाध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी, भिलाई

ओडिशा के बालासोर रेल सेक्शन में रेल हादसे की सीबीआई जांच आरंभ हो चुकी है. सी.बी.आई ने कुछ संदिग्ध रेल कर्मियों को हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ जारी है. आम तौर पर रेल हादसों की जांच तकनीकी कमेटी करती है, पर यहां पहले ही मान लिया गया है कि यह सेबोटाज (तोड़फोड़) का मामला था. रेलवे ने खामोशी की चादर ओढ़ ली है, अब पूरा मामला केन्द्र के पाले में है. आखिर क्या छिपाना चाहती है सरकार?

बालासोर रेल हादसा

क्या छिपाना चाहती है सरकार

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

दरअसल, रेलवे की हालत, जितनी दिखाई देती है, उससे भी ज्यादा खराब है. सरकार का पूरा जोर नई ट्रेनें चलाकर लोगों को यह फील देने की है कि रेलवे तरक्की कर रहा है. जबकि हकीकत यह है कि ट्रैक और कोच के मेंटेनेंस के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है.

2022 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने संसद में भारतीय रेलवे में ट्रेनों के पटरी से उतरने की घटनाओं की समीक्षा रिपोर्ट पेश की थी. रिपोर्ट के मुताबिक़, अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2021 के बीच देश में कुल 2017 रेल हादसे हुए. इनमें से 75 फीसदी मामले ट्रेनों के बेपटरी होने के थे. इनमें से 217 हादसे ऐसे थे जिसमें जान-माल का नुकसान हुआ. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ट्रेनों के बेपटरी होने की घटनाएं पटरियों के रखरखाव से जुड़ी हुई है.

सीएजी की रिपोर्ट ने रेलवे ट्रैक के मेनटेनेंस कामों के लिए आवंटित होने वाले फंड्स में कटौती का भी उल्लेख किया था. साल 2018-19 में ट्रैक की मरम्मत और नए ट्रैक बिछाने के लिए 9 हज़ार 6 सौ 7 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, लेकिन 2019-20 में इसे घटाकर 7 हज़ार 4 सौ 17 करोड़ रुपये कर दिया गया. आवंटित राशि का पूरा इस्तेमाल भी नहीं किया गया.

रखरखाव के प्रति लापरवाही

दक्षिण पूर्व रेलवे, जहां हादसा हुआ वहां एंटी कोलिजन सिस्टम के लिए आवंटित बजट में से एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पूर्व रेलवे को एंटी ट्रेन कोलिजन सिस्टम के लिए 468.9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, ये पैसा साल 2020-21 में कम आवाजाही वाले 1563 रूट किलोमीटर के लिए था. लेकिन मार्च 2022 तक इसमें से एक भी रूपया खर्च नहीं किया गया था. इसी जोन के दूसरे सेक्शन के लिए भी ट्रेनों को टक्कर से बचाने के लिए 1563 रूट किलोमीटर के लिए 312 करोड़

रुपए सैंक्शन किए गए थे. मार्च 2022 तक इसमें से भी एक रुपए खर्च नहीं किए गए. इसी तरह से 2021-22 में 162.9 करोड़ रुपए दक्षिण पूर्व रेलवे को मिले, लेकिन एक भी पैसा इसमें से भी खर्च नहीं किया गया. इस क्षेत्र में सुरक्षा उपायों के लिए अभी तक कोई टेंडर नहीं निकाला गया है.

क्या है आपत्ति

बालासोर के बहानागा बाजार रेलवे स्टेशन के करीब हुए इस हादसे को एक अलग रूप देने की कोशिश की जा रही है. आम तौर पर ऐसे हादसों की जांच रेलवे के सेफ्टी अफसर और तकनीकी टीम करती है. इसलिए जब इस रेल हादसे की जांच सीधे सीबीआई को सौंपी गई तो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई. कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सीबीआई केवल क्रिमिनल केसेज़ की जांच करती है, रेल दुर्घटना की जांच उसे क्यों सौंपी गई? जबकि रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की जांच अभी चल ही रही थी. रेलवे के दुर्घटना के कारणों की

सीएजी की रिपोर्ट में गिनाई गई थी गंभीर खामियां

कर्मचारी कम, वर्कलोड ज्यादा, इसलिए हादसे

सिग्नल सिस्टम के फाल्ट की अनदेखी हुई

2017 से 2021 तक हुए 2017 रेल हादसे

समुचित तरीके से जांच पूरी कर पाने से पहले ही, 'अपराधी कौन' की अटकलबाजियों के खेल शुरू हो चुके थे. आरोप हैं कि सीबीआई को 'अपराधियों' की खोज करने के काम पर लगा दिया गया है और बलि के लिए बकरों की खोज शुरू हो गयी है. शासन की ओर से रेलवे और सीबीआई को साफ-साफ इसका इशारा दिया जा चुका है कि उन्हें बलि के बकरे खोजने हैं और उन व्यवस्थागत खामियों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, जो ऐसी बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं.

क्या कवच रोक सकता था हादसा?

कवच एक ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है. जिसे भारतीय रेलवे के रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गनाइजेशन ने डेवलप किया है. इस पर काम 2012 में शुरू हुआ था. तब इस प्रोजेक्ट का नाम "ट्रेन कोलीजन एवायडेंस सिस्टम" था. ये सिस्टम कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज का एक सेट है, जिन्हें ट्रेन और ट्रैक पर इंस्टॉल किया जाता है. सिग्नल आने से पहले ही लोकोपायलट को मालूम चल जाता है कि वो ग्रीन है, रेड है या डबल यलो. जैसे ही कोई लोको पायलट किसी सिग्नल को जंप करता है कवच एक्टिव हो जाता है और ट्रेन के ब्रेक का कंट्रोल हासिल कर लेता है. जैसे ही सिस्टम को पता चलता है कि ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही है वो पहली ट्रेन के मूवमेंट को एक निश्चित दूरी पर रोक देता है. 4 मार्च 2022 को खुद रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक लोकोमोटिव इंजन में बैठकर इसका परीक्षण किया था जो सफल रही थी.

फरवरी में मिली थी रेल मंत्रालय को चिट्ठी

ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नल सिस्टम एक उन्नत और सुरक्षित सिस्टम है. इसीलिए अगर बालासोर हादसे में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को लेकर जांच चल रही है, तो यह चिंता का विषय है. इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को लेकर तीन महीने पहले ही चेतावनी दी गई थी. कर्नाटक के हुबली स्थित दक्षिण-पश्चिम रेलवे ज़ोन के मुख्य परिचालन प्रबंधक ने 9 फरवरी को इंटरलॉकिंग सिस्टम की ख़ामियों को लेकर सरकार को पत्र लिखा था. पत्र में कहा गया था कि कर्नाटक के यशवंतपुर जंक्शन से दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन तक चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस. 8 फरवरी को ट्रेन का सिग्नल फ़ेल हो गया था, मगर लोको-पायलट की सतर्कता ने हादसे को टाल दिया. उन्होंने कहा

कि सिस्टम में गंभीर ख़ामियां हैं. पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द इन ख़ामियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक क़दम उठाए जाने चाहिए. अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी खामी के सामने आने के बाद भी इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया?

रिपोर्ट में छिपे हैं कई राज

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने, भारतीय रेलवे में बेपटरी होने के प्रकरणों पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रेलवे की अनेक व्यवस्थागत खामियों को उजागर किया था. अप्रैल 2017 से मार्च 2021 के बीच सामने आये प्रकरणों की जांच के बाद पकड़ में आयी कुछ समस्याओं का विवरण इसमें दिया गया है. सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी समस्याओं के 275 मामले सामने आए थे, इनमें ऐसे प्रकरण जिनमें 'प्वाइंटों की गलत सेटिंग तथा शंटिंग ऑपरेशनों की अन्य गलतियां' पायी गयी थीं, वे 84 फीसद यानी 231 थे. यह महज संयोग है कि 231 बार तो ऐसी गड़बडियों से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन 232वीं बार में बड़ी दुर्घटना हो गयी.

कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा रेलवे

1 दिसंबर 2022 तक, भारतीय रेलवे में क़रीब सवा तीन लाख अराजपत्रित पद ख़ाली पड़े हुए थे. यानी रेलवे में कामगारों की भारी कमी थी. यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य सभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी थी. इसमें उत्तरी जोन में 38 हज़ार 754, पश्चिमी जोन में 30 हज़ार 476, पूर्वी जोन में 30 हज़ार 141 तथा मध्य रेल जोन में 28 हज़ार 650 पद ख़ाली थे. इनमें से ज़्यादातर वेकेंसियां ऑपरेशन और मेनटेनेंस से जुड़ी हुई हैं. इसीलिए कहा जा रहा है कि भले बालासोर हादसे की वजह क्रिमिनल एक्ट में खोजी जाएं, लेकिन रेलवे के पूरे सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है. इस साल के जून में रेलवे बोर्ड ने भी दुर्घटनाओं को रिव्यू करते हुए कहा था कि खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए. साथ ही सभी ज़ोन्स के जनरल मैनेजर्स को निर्देश दिया था कि वर्कफ़ोर्स और काम के घंटों का ख़याल रखें. किसी भी सूरत में कोई कर्मचारी 12 घंटों से ज़्यादा काम नहीं करेगा.

पल्ला झाड़ता रेल मंत्रालय

बालासोर रेल हादसे को बार-बार इस दिशा में घुमाया जा रहा है कि ये हादसा कवच या किसी और तकनीक के चलते रोकना मुश्किल था. लेकिन ये आंकड़ें आपको बता रहे हैं कि पांच साल में रेलवे में सेफ्टी पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का वादा करने वाली सरकार ने पैसा कितना जारी किया. और जो पैसा मिल भी गया, उसमें से भी कितना कम खर्च हो पाया. यहां टेंडर ही नहीं निकल पा रहा है. ये बात सरकार और रेल अधिकारी - दोनों के एटीट्यूड पर सवाल खड़े करती है.

अगर सरकार को पिछले साल से मालूम है कि पटरियों का मेनटेनेंस न होने की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो सरकार ने क्या किया? रेलवे का एक क़द्दावर अधिकारी उसे पत्र लिखता है, कि सिग्नल सिस्टम में फ़ॉल्ट है. सरकार ने इस जानकारी का क्या किया? कामगारों की हालत ख़राब है.. सरकार ख़ाली पद क्यों नहीं भर रही है?

शोशेबाजी में सरकार

एक तरफ रख-रखाव की अनदेखी हो रही है, कर्मचारी 16-16 घंटे काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार बुलेट ट्रेन और वंदे भारत की महत्वाकांक्षी लक्ष्य के पीछे भाग रही है. 13 मई तक, ऐसी 17 रेलगाडियां चलने भी लगी थीं और 75 और गाड़ियां 2023 के अगस्त तक शुरू किए जाने का प्रस्ताव है, इनमें से हरेक गाड़ी की लागत, 115 करोड़ रुपये है. यह उस महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना के ऊपर से है, जिससे 1,08,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से, मुंबई से अहमदाबाद को जोड़ा जाएगा. सीएजी की रिपोर्ट में ध्यान दिलाया गया है कि रेलवे को पांच वर्ष की अवधि में अपने सुरक्षा बजट में, 20 हजार करोड़ रुपये अपने आंतरिक संसाधनों से लगाने थे और 80,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के फंडों से मिलने वाली बजट सहायता में से लगाने थे. रिपोर्ट बताती है कि रेलवे के आंतरिक संसाधनों से '20 हजार करोड़ रुपये के कुल हिस्से में से 15,775 करोड़ रुपये (79.88 फीसद) की कमी रही.' सीएजी के अनुसार इसने तो, 'रेलवे में पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संसाधन मुहैया कराने के लिए आरआरएसके के गठन के मूल लक्ष्य को ही विफल कर दिया.'

बालासोर रेल हादसा

ये हादसा हुआ ओडिशा के बालासोर जिले के बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास. ये जगह कोलकाता से करीब 280 किलोमीटर और भुवनेश्वर से करीब 170 किलोमीटर दूर है. यह दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का हिस्सा है, यहां चार रेल ट्रैक हैं, किनारे-किनारे दो लूप लाइन और बीच दोनों मेन लाइन. शाम के 6 बजकर 55 मिनट पर बहनागा स्टेशन से थोड़ा पहले दो मालगाड़ी लूप लाइन पर खड़ी थीं ताकि मेन लाइन पर यशवंतपुर एक्सप्रेस और कोरोमंडल एक्सप्रेस को पास दिया जा सके. यशवंतपुर एक्सप्रेस, बेंगलुरु से कोलकाता की ओर जा रही थी, कोरोमंडल को ग्रीन सिग्नल था. यानी फुल स्पीड में निकल जाना था. सिग्नल की कुछ दिक्कत हुई और कोरोमंडल को लूप लाइन में जाने के लिए सिग्नल मिला, जिसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर गई और वहां पर खड़ी मालगाड़ी से 128 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टकरा गई और कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी के डिब्बों पर चढ़ गया. कोरोमंडल के डिब्बे चारों तरफ तितर-बितर से होकर फैल गए, और इसी दूसरी मेन लाइन से गुजर रही यशवंतपुर एक्सप्रेस के आखिरी दो डिब्बे भी इसकी चपेट में आ गए. इस हादसे में 275 लोगों की मौत की पुष्टि रेलवे ने 72 घंटे बाद कर दी. 900 से ज्यादा घायल बताए गए.

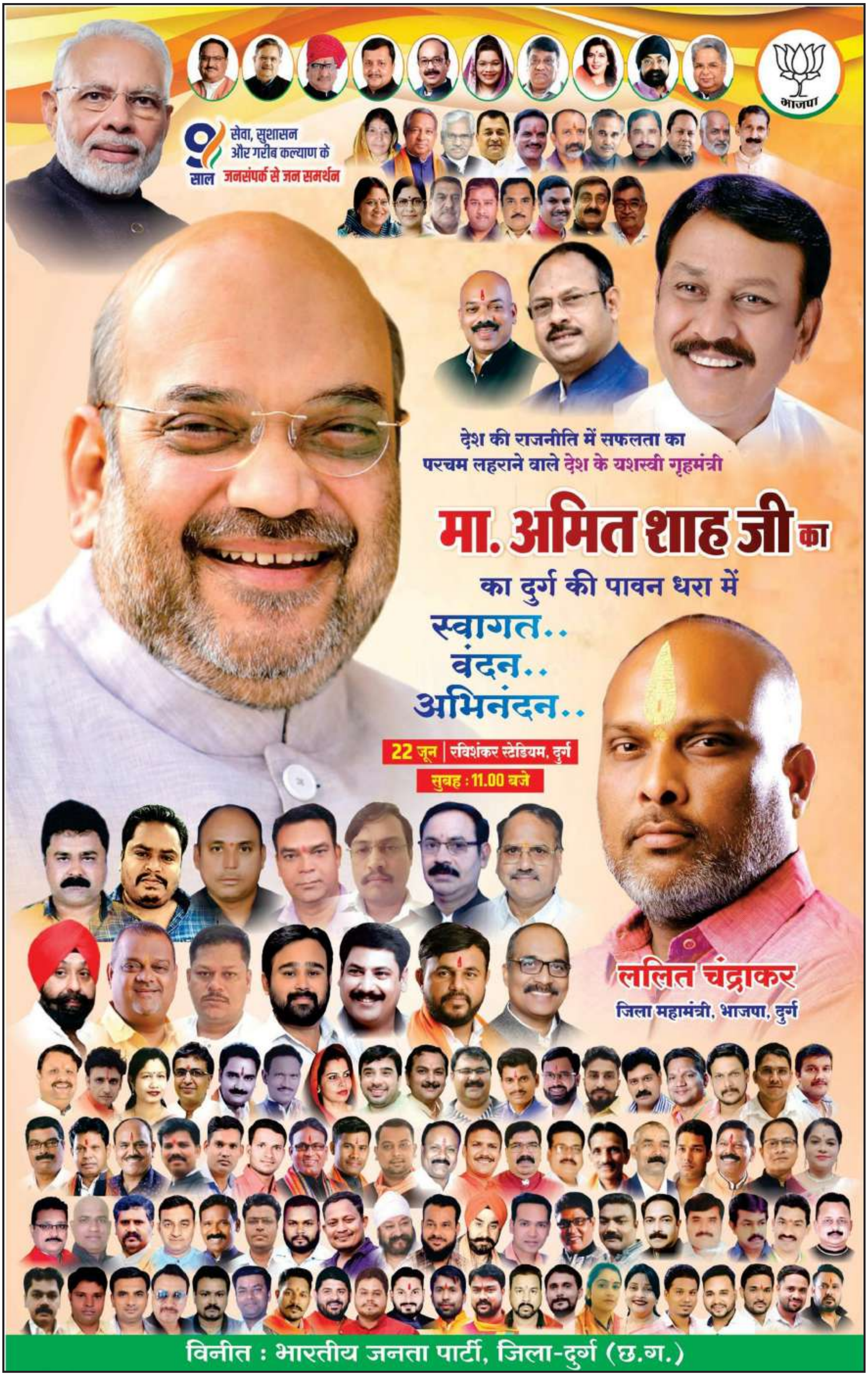

भाजपा
9 साल
सेवा, सुशासन
और गरीब कल्याण के
जनसंपर्क से जन समर्थन
देश की राजनीति में सफलता का
परचम लहराने वाले देश के यशस्वी गृहमंत्री
मा. अमित शाह जी का
का दुर्ग की पावन धरा में
स्वागत..
वंदन..
अभिनंदन..
22 जून | रविशंकर स्टेडियम, दुर्ग
सुबह : 11.00 बजे
ललित चंद्राकर
जिला महामंत्री, भाजपा, दुर्ग
विनीत : भारतीय जनता पार्टी, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

मेडिकल कालेज खुला तो दल्ली-राजहरा को मिलेगा नवजीवन

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

खनिज नगरी को मिलेगी नई पहचान, कई शहरों को होगा लाभ

आसपास के सैकड़ों गांवों के आदिवासियों को मिलेगा लाभ

खेल अकादमी खुलने से मिलेगा स्थानीय प्रतिभा को मौका

व्यवसायी हर प्रकार के सहयोग के लिए तैयार

दल्ली-राजहरा के प्रतिष्ठित व्यवसायियों एवं उद्यमियों का मानना है कि यदि यहां मेडिकल कालेज और स्पोर्ट्स काम्पलेक्स की स्थापना कर दी जाए तो शहर नए स्वरूप में एक बार फिर निखर सकता है. यहां की खदानों ने सेल की फ्लैगशिप इकाई भिलाई इस्पात संयंत्र को छह दशकों तक लौह अयस्क की आपूर्ति की है. पर समय के साथ ही यहां का भंडार चुकने लगा और शहर धीरे-धीरे मरने लगा. अब जबकि रावघाट की खदानों से अयस्क मिलने के मार्ग प्रशस्त हो गया है तो यहां के नागरिक इस शहर को पुनर्जीवित करने की कोशिश में जुट गए हैं.

इस शहर का एक वैभवशाली इतिहास रहा है. दल्ली-राजहरा की खदानों ने न केवल भिलाई इस्पात संयंत्र की चरण-दर-चरण बढ़ती क्षमता की मांग को पूरा किया बल्कि रेलवे को भी माल भाड़ा के रूप में एक बड़ी राशि पिछले छह दशकों में दी है. इस शहर को यूं ही मरने नहीं दिया जा सकता. भीखमचंद जैन, कमल सारडा, शांतिलाल जैन सहित शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायियों का कहना है कि यदि सरकार पहलकदमी करती है तो वे प्रत्येक स्तर पर अपनी क्षमता के अनुरूप सहयोग करने को तैयार हैं. मेडिकल कालेज, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, तारामंडल (प्लैनेटोरियम) जैसे प्रोजेक्ट इस शहर में नए प्राणों का संचार कर सकते हैं.

छत्तीसगढ़ प्रदेश कबड्डी संघ के प्रथम अध्यक्ष तथा अंचल के प्रतिष्ठित उद्योगपति एवं व्यवसायी भीखमचंद जैन का मानना है कि दल्ली राजहरा में मेडिकल कालेज के खुल जाने से एक तरफ जहां अंचल के लोगों को स्तरीय इलाज अपने घर के पास मिल जाएगा वहीं इससे अंचल का व्यापार भी बढ़ेगा. लोगों की आवाजाही बढ़ेगी और शहर एक बार फिर से गुलजार हो जाएगा. यह एक आदिवासी

प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से है उम्मीद

शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री रचनात्कमता के लिए जाने जाते हैं. उन्हें पूरी उम्मीद है कि दल्ली-राजहरा को उसका खोया वैभव लौटाने तथा आदिवासियों की भलाई के लिए वे अवश्य इस अंचल की मांगों पर विचार करेंगे.

बहुल क्षेत्र है जिन्हें इसका सबसे बड़ा लाभ मिलेगा.

उन्होंने कहा कि फिलहाल यहां के लोगों को अच्छे इलाज के लिए जगदलपुर, राजनांदगांव, रायपुर या भिलाई के अस्पतालों तक जाना होता है. इससे कई बार समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण लोगों की स्थिति गंभीर हो जाती है. कई बार तो अस्पताल पहुंचते-पहुंचते ही रोगी दम तोड़ देता है. यहां से जगदलपुर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है. वहीं चिकित्सा का सबसे बड़ा केन्द्र रायपुर भी लगभग 122 किलोमीटर दूर है. भिलाई की दूरी यहां से 90 किलोमीटर है जबकि राजनांदगांव 67 किलोमीटर दूर है. सबसे निकट का केन्द्र धमतरी है जो यहां से लगभग 70 किलोमीटर दूर है.

दल्लीराजहरा एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है. इसलिए दल्ली-राजहरा में मेडिकल कालेज अस्पताल का लाभ डौण्डीलोहारा, चारामा, अंतागढ़, बालोद, भानुप्रतापपुर जैसे शहरों और उनके आसपास फैले हजारों वनग्रामों को इसका लाभ मिलेगा. कुछ समय पहले वरिष्ठ साहित्यकार शिरोमणि माथुर के पुत्र की असामयिक मौत केवल इसलिए हो गई कि उसे समय पर सही उपचार नहीं मिल पाया.

भीखमचंद जैन बताते हैं कि मेडिकल कालेज के खुलने से दल्ली-राजहरा भी उच्च शिक्षा के नक्शे पर आ जाएगा. उनका परिवार

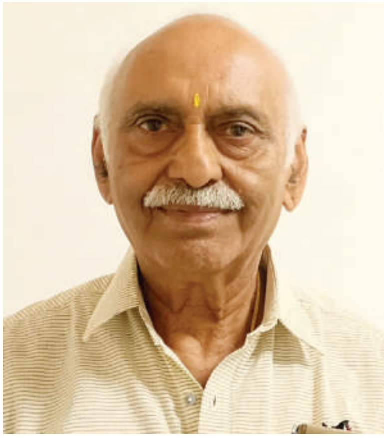

भीखमचंद जैन, समाज सेवी

हमेशा अंचल की बेहतरी के लिए काम करता रहा है. यहां के प्रसिद्ध नेमीचंद महाविद्यालय की स्थापना उनके पिता के नाम पर ही 1978 में की गई थी. पांच दशक से भी अधिक समय से यह महाविद्यालय आर्ट्स, साइंस एंड कामर्स के क्षेत्र में अंचल के आदिवासी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा की जरूरतों को पूरा कर रहा है.

चंडीगढ़ की तर्ज पर खुले स्पोर्ट्स काम्पलेक्स

शहर के नागरिकों का मानना है कि दल्ली-राजहरा में स्पोर्ट्स काम्पलेक्स या खेल अकादमी की स्थापना की जानी चाहिए. यह एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है. इसके आसपास के छोटे शहरों और असंख्य गांवों में भी आदिवासी खेल प्रतिभाएं बड़ी संख्या में रहते हैं जिन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाने के कारण उनकी प्रतिभा कुंठित होती है. यदि इन्हें प्रशिक्षण की सुविधा मिले तो ये भी देश विदेश में अपना परचम फहरा सकते हैं. कांकेर की बेटी नैना सिंह धाकड़ ने माउंट एवरेस्ट सहित हिमालय की कई चोटियों पर तिरंगा लहराकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया था.

सभी प्रकार से सहयोग करने को तैयार

भीखमचंद जैन, कमल सारडा, शांतिलाल जैन आदि ने कहा कि दल्ली-राजहरा की लौह नगरी ने उन्हें काफी कुछ दिया है. अब उनकी बारी है कि वे इस शहर को कुछ लौटाएं. इसलिए यदि सरकार यहां के विकास की पहल करती है तो वे भी मुक्त हस्त से इसमें सहयोग करने को तैयार हैं. यदि शहर में मेडिकल कालेज अस्पताल खुल जाता है तो इसके साथ ही नर्सिंग कालेज, फार्मेसी कालेज जैसी संस्थाओं को भी यहां आने का मौका मिलेगा. यदि स्पोर्ट्स काम्पलेक्स की सौगात मिल जाती है तो यह इस अंचल के लिए एक और बड़ी सौगात होगी.

प्रवीरचंद्र भंजदेव को बस्तर में राजा के साथ-साथ भगवान का दर्जा प्राप्त है. बचपन में अंग्रेज गार्जियन ने उनपर इतने जुल्म ढाए कि उनकी बड़ी बहन कमला कुमारी मानसिक विकृति का शिकार हो गई. पर प्रवीरचंद्र इस प्रताड़ना के चक्रव्यूह से और तपकर निकले. उन्होंने लंदन से अपनी शिक्षा पूरी की और फिर बस्तर के होकर रह गए. उन्होंने जितने आंदोलन चलाए उनका सुफल आगे चलकर बस्तर को मिला. आज जो नगरनार का इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ है, उसकी कल्पना भी प्रवीरचन्द्र ने 1966 के आसपास ही कर ली थी. प्रवीरचंद्र ने ही बस्तर दशहरा को वह ऊंचाई दी कि आज वह विश्वप्रसिद्ध हो चुका है और देश विदेश से लाखों सैलानी उसे देखने के लिए जगदलपुर और आसपास के शहरों में डेरा डालते हैं.

बचपन की प्रताड़ना से तपकर निकला संन्यासी राजा प्रवीरचंद्र

» हेमंत कश्यप

प्रवीरचंद्र की की माता स्व. प्रफुल्लकुमारी देवी बस्तर की महारानी थी. उनके पिता राजा रुद्रप्रताप देव का निधन सन 1921 में हुआ तो उन्हें राजगद्दी पर बिठाया गया. प्रफुल्लकुमारी अपने माता-पिता की इकलौती संतान थीं. उनका विवाह मयूरभंज महाराजा के भतीजे प्रफुल्लचंद्र भंजदेव के साथ 1927 में हुआ था. इनके दो पुत्र और दो पुत्रियां थीं. उन दिनों राजमहल पर अंग्रेजी हुकूमत का साया था. अंग्रजों की मनमानी के चलते उनके पिता प्रफुल्लचंद भंजदेव का अपने बच्चों पर कोई अधिकार नहीं था.

जीवन भर आदिवासियों के लिए करते रहे संघर्ष

विदेश प्रवास के दौरान जुड़े स्वतंत्रता आंदोलन से

छह दशक पहले उठाई थी बस्तर स्टील प्लांट की मांग

दंतेश्वरी के साथ पूजे जाते हैं राजा प्रवीरचन्द्र

प्रवीरचंद्र का जन्म 25 जून 1929 को शिलांग में हुआ था. 25 मार्च 1966 को राजमहल के भीतर हुए गोलीकांड में बस्तर का यह सबसे लोकप्रिय महाराजा कुछ आदिवासियों के साथ मारे गए. पर बस्तर ने आज भी अपने राजा को याद रखा है. महाराजा प्रवीरचन्द्र को आज भी बस्तर के आदिवासी देवतुल्य मानते हैं. प्रत्येक घर में मां दंतेश्वरी के साथ प्रवीरचन्द्र भंजदेव की तस्वीर भी नजर आती है. बस्तर राजमहल के सम्मुख उनकी प्रतिमा भी राज परिवार द्वारा स्थापित कराई गई है. बस्तर दशहरे में भी लोग मां दंतेश्वरी के साथ ही राजमाता और राजा प्रवीरचंद्र की तस्वीर लेकर ही निकलते हैं.

क्रूर अंग्रेज गार्जियन गिब्सन

प्रवीरचंद्र राजघराने में अवश्य पैदा हुए थे किंतु बचपन से क्लेश ही भोगते रहे. कर्नल गिब्सन नामक एक अंग्रेज उनका गार्जियन था. वह प्रवीरचन्द्र का खानपान, शिक्षा-दीक्षा आदि विलायती तरीके से करता था. उन्हें भारतीयता और भारतीय खानपान से दूर रखा गया. एक बार

आदिवासियों के लिए लगातार संघर्ष

प्रवीरचंद्र के 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद जुलाई 1947 में ब्रिटिश शासन ने उन्हें रियासत का पूर्ण अधिकार सौंप दिया. सन 1948 को छत्तीसगढ़ की अन्य रियासतों के साथ बस्तर भी मध्यप्रदेश में विलीन हो गया. वर्ष 1955 में प्रवीरचंद्र ने बस्तर जिला आदिवासी किसान- मजदूर सेवा संघ की स्थापना की. जनवरी 1956 में संघ का महाधिवेशन किया गया. इसका उद्देश्य था जिला स्तर पर आदिवासी किसान, मजदूरों का आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक विकास करना. इसी दौरान उन्हें क्षयरोग (टीबी) ने घेर लिया. उन्हें पागल घोषित कर स्विजरलैंड भेज दिया गया. सेनेटोरियम ने उन्हें मानसिक रुप से पूरी तरह स्वस्थ घोषित कर दिया और दो-तीन माह के अंदर ही वे मातृभूमि लौट आए.

उन्हें पैलेस के सेक्रेटरी गौरीदत्त जोशी के घर भारतीय व्यंजनों का स्वाद मिला. उन्होंने अपने नियमित भोजन में भारतीय भोजन की मांग की किंतु गिब्सन ने इंकार कर दिया. इस पर प्रवीर चन्द्र क्रोधित हुए और गिब्सन के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया. गिब्सन ने उनके खिलाफ पोलिटिकल एजेंट के पास शिकायत दर्ज की. नतीजा यह निकला कि प्रवीरचन्द्र को एक मेडिकल कांफ्रेंस ने पागल घोषित कर दिया. प्रताड़ना का शिकार होकर उनकी बड़ी बहन ने अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया.

नगरनार में साकार हुआ भंजदेव का सपना

प्रवीरचन्द्र भंजदेव चाहते थे कि बस्तर का लोहा बस्तर में ही गले, इसलिए उन्होंने विश्व प्रसिद्ध लौह अयस्क के परिपूर्ण बैलाडीला की चौदह पहाड़ियों को हैदराबाद के निजामों को सौपने की साजिश का विरोध किया. उन्होंने बस्तर में इस्पात उद्योग की मांग की पर केंद्र सरकार ने बस्तर में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र को विशाखापट्टनम के सेलम में खड़ा करवा दिया. प्रवीरचंद्र भंजदेव की मांग को उस समय मान ली गई होती तो आज बस्तर की तस्वीर कुछ और होती. बस्तर महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव की शहादत के संतावन वर्षों बाद स्पात संयंत्र नगरगार में शुरू होने जा रहा है. निश्चित ही स्पात संयंत्र और इसके सहायक उद्योगों में बस्तरवासियों को रोजगार सुलभ होगा.

संघर्षों से तपकर निकला खरा सोना

अंग्रेज गार्जियन की निर्दयता, पैलेस का बंदी जैसा माहौल, खान-पान, बोल-चाल से लेकर रहन सहन तक प्रवीरचंद्र पर हजार पहरे थे. उन्हें मारपीट तक सहनी पड़ती थी. कोशिश थी कि उन्हें निकम्मा या पागल घोषित कर दिया जाए. पिता प्रफुल्लचंद भंजदेव का अपने बच्चों पर कोई अधिकार नहीं था. वह उनके मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे. पर तमाम बंदिशें उनकी प्रतिभा को रोक नहीं सकी. उन्होंने एमए की परीक्षा उन्होंने इंग्लैंड में पास की. अर्थशास्त्र, भाषा विज्ञान, नृविज्ञान और दर्शन उनके विषय रहे. वह संस्कृत के जाने-माने विद्वान थे.

एक तरफ जहां उनके हृदय में देशभक्ति हिल्लोरें ले रही थी वहीं दूसरी तरफ वे गणतंत्र परिषद से भी जुड़ गए. राज्य परिषद के सम्मानित सदस्य भी बने. लंदन की इंडिया लीग में स्व. कृष्णा मेमन के साथ काम किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया. लेखनी तथा वाणी के प्रभाव द्वारा उन्होंने इंग्लैंड प्रवास के दौरान राष्ट्र को अपनी सेवाएं दीं. उनका आध्यात्म की तरफ झुकाव था और अन्याय सहने के खिलाफ थे. इसलिए उन्हें भी पिता की भांति शासन की टेढ़ी नजर का शिकार होना पड़ा.

लोहंडीगुड़ा गोली कांड

कोर्ट आप वार्ड्स के कारण प्रवीरचंद्र भंजदेव के सामने अर्थ संकट उत्पन्न हो गया था. इससे वे विचलित हो उठे थे. सन 1957 में बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे. वे मध्यप्रदेश विधानसभा के सदस्य भी चुने गए किंतु अपरिहार्य कारणवश सन 1959 में उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया. 11 फरवरी को दिल्ली से लौटते समय धनपूंजी में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. उनकी गिरफ्तारी के परिणाम स्वरुप ही लोहंडीगुड़ा में गोली कांड हुआ था. जिसमें एक दर्जन से ज्यादा आदिवासियों की मौत हुई थी.

विवाह और दशहरा संकट

4 जुलाई 1961 को उनका विवाह पाटन (राजस्थान) की राजकन्या वेदमती देवी के साथ दिल्ली में संपन्न हुआ. इसी साल दशहरे को लेकर विवाद खड़ा हो गया. उनकी गिरफ्तारी के दूसरे दिन ही उन्हें महाराजा के पद से हटा कर छोटे भाई

विजयचंद्र को महाराजा घोषित कर दिया गया. लेकिन आदिवासियों ने विरोधियों की मंशा को पूरा नहीं होने दिया. जिस प्रवीरचंद्र भंजदेव ने राजा होकर भी कभी रथ की सवारी नहीं की थी अब "जनता का राजा" बनकर रथारूढ़ हुए. उनके लाखों आदिवासी समर्थकों ने दशहरा का पूरा खर्च उठाया और श्रेष्ठ व्यवस्था की. सन 1961 से 1965 तक उन्होंने सबसे अधिक शानदार ढंग से दशहरा मनाया था. वर्ष 1962 का दशहरा पर्व बस्तर के इतिहास में सबसे अभूतपूर्व था. जब छः अक्टूबर को महारानी वेदवती देवी का बस्तर आगमन हुआ था महाराजा सपत्नीक रथारूढ़ हुए थे. लगभग पांच लाख आदिवासी बस्तर के कोने-कोने से इस महोत्सव में उपस्थित हुए थे. यही वह काल था, जब दशहरा राजा का न होकर आदिवासियों का हो गया था.

राजमहल का वह हादसा

बचपन की प्रताड़ना से लेकर राजनीतिक कोपभाजन तक को हंसते हंसते सह जाने वाले देवपुरुष प्रवीरचंद्र के लिए 16 नवंबर 1963 की दीवाली एक जीवन पर्यंत सालने वाला दर्द बन गई. परम्परा के अनुसार वे प्रजा को दान दे रहे थे कि तभी दुर्घटनावश मोतीलाल नामक एक रिक्शा चालक का हाथ कट गया. इस अभियोग में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 500 रूपये की जमानत पर छोड़ा गया. 22 सितंबर 1964 को इसी मामले में उन्हें 100 रूपये का जुर्माना और 18 माह की सजा सुनाई गई. जबलपुर हाईकोर्ट में अपील करने पर उन्हें बरी कर दिया गया.

बस्तर के लिए अनशन

प्रवीरचंद्र की पहल पर आदिवासियों के शिष्ट मंडल ने प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री से मिलकर बस्तर की समस्याओं पर ज्ञापन सौंपा. 12 जनवरी 1965 को उन्होंने दिल्ली में अनशन भी किया. बस्तर की आदिवासी महिलाओं का हुजूम जगदलपुर राजमहल में एकत्र होने लगा. आदिवासी महिलाओं का जुलूस देख जगदलपुर के बाशिंदे चकित थे. ऐसा विशाल जुलूस इससे पहले यहां कभी देखने में नहीं मिला था. 6 नवंबर 1965 को आदिवासी महिलाओं ने जिलाधीश कार्यालय में धरना दिया. इसके बावजूद महिलाओं के साथ अभद्रता की गई. कई जुलूसों में इन्हें प्रताड़ित भी किया गया. इन्हीं सब बातों को लेकर 12 दिसंबर 1965 को प्रवीरचंद्र भंजदेव ने विजय भवन में अनशन प्रारंभ किया. 16 दिसंबर 1965 को आयुक्त वीरभद्र सिंह ने अनशन समाप्त करवाया. आठ फरवरी 1966 को जबरन लेवी वसूली के खिलाफ वे फिर अनशन पर बैठे गए.

विलक्षण प्रतिभा के धनी

महाराजा प्रवीरचंद्र देव धार्मिक थे और उन्हें धर्म ग्रंथों का अच्छा ज्ञान था. किसी भी विषय पर वे अधिकारपूर्वक बोल सकते थे. उन्होंने योग विद्या पर कई किताबें लिखीं. उन्होंने योग तत्व, भगवा तत्व, योग संबंध का निरूपण, लोहंडीगुड़ा तरंगिनी, आई प्रवीर द आदिवासी गार्ड जैसे चर्चित ग्रंथों की रचना की. उन्होंने 1950 में मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का चतुर्दश वार्षिक अधिवेशन राजमहल परिसर में कराया था.

छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थानों में से एक ताला न सिर्फ ऐतिहासिक वरन् धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है. इसे शैव उपासकों की महत्वपूर्ण स्थली के रूप में भी जाना जाता है. सन् 1873-74 में तत्कालीन कमिश्नर फिशर जे. डी. बेलगर ने भारतीय पुरातत्व के प्रथम महानिदेशक एलेक्जेन्डर कनिंघम के सहयोगी को ताला गांव की सूचना दी थी.

» डॉ. डी.पी. देशमुख

एक विदेशी महिला जोलियम विलियम्स ने अपने सर्वेक्षण में इसे गुप्तकाल का मंदिर बताया. पुरातत्ववेत्ताओं ने ताला गांव के काल का निर्धारण 6वी से 7वी शताब्दी के आस पास निर्धारित किया है. लगभग ढाई दशक पहले यहां उत्खनन में रूद्रशिव की अद्भुत प्रतिमा मिली. जीव-जंतुओं के सुन्दर संयोजन से बनी यह पाषाण प्रतिमा अद्वितीय है.

ऐतिहासिक शहर मल्हार से मात्र 18 कि.मी. की दूरी पर बसा ताला स्थापत्य व मूर्तिकला का अत्यंत समृद्ध स्थल रहा होगा, ऐसा प्रतीत होता है. मूर्तियों की शैली और प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है कि यह स्थान शैव उपासकों की धर्मस्थली रही होगी. वर्तमान में भी "ॐ नम: शिवाय" और "ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगंधिम पुष्टीवर्धनम् मामृतात्" की ध्वनि ताला की फिजाओं में गुंजती रहती है. शिवजी के अनेकों विधानों को शिवभक्त समन्न करते आ रहे हैं. निषाद समाज द्वारा राम-जानकी मंदिर एवं स्वामी पूर्णानन्द महाराज की कुटिया एवं गौशाला शोभायमान है.

ताला का प्रसिद्ध शैव मंदिर देवरानी-जेठानी कलात्मकता का बेजोड़ नमूना है. देवरानी-जेठानी मंदिर विशिष्ट तल विन्यास में विलक्षण

चमत्कृत करती हैं ताला की मूर्तियां

प्रतिमा निरूपण तथा मौलिक अलंकरण की दृष्टि से भारतीय कला में विशिष्ट स्थान रखता है. मंदिर के तल विन्यास में आरंभिक चन्द्रशिला और सीढ़ियों के बाद अर्द्धमण्डप, अंतराल और गर्भगृह तीन मुख्य भाग हैं. शिव के यक्षगण एवं भारवाहक गणों की सुन्दर आकृतियाँ दर्शनीय है जो जेठानी मंदिर की सीढ़ियों पर भग्न अवस्था में है. उसके उत्तरी पार्श्व में दोनो किनारों में विशालकाय हाथी बैठी हुई मुद्रा में है. दक्षिण की ओर मुख्यप्रवेश द्वार के अलावा पूर्व और पश्चिम दिशा में भी द्वार है. कमनीय अंकन लिये मुख्य प्रवेश द्वार में पत्थरों के कलात्मक स्तंभ है.

रूद्र शिव की अनूठी प्रतिमा

सन् 1987-88 में देवरानी मंदिर परिसर में उत्खनन के दौरान एक अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है. जो भारतीय शिल्प कला में अद्वितीय है, शिव के रूद्र अथवा अघोर रूप से सामन्जस्य होने के कारण इसका रूद्र शिव के रूप में उच्चारण किया गया. ताला की एक मात्र परिपूर्ण प्रतिमा को स्मारक स्थल पर रखा गया. यह प्रतिमा 2.54 मीटर ऊंची तथा 1 मीटर चौड़ी है. जीव-जन्तु की मुखाक्रति से इसके अंग-प्रत्यंग निर्मित है.

प्रतिमा समपाद स्थानक मुद्रा में प्रदर्शित है, इसका रूपाकंन कृकलास (गिरगिट), मछली, केकड़ा, मयूर, कच्छप, सिंह आदि जीव-जन्तु तथा मानव मुख की मौलिक प्रकल्पनायुक्त रूपाकृति अत्यंत ओजस्वी है. इसके शिरोभाग पर मंडलाकार चक्रों में लिपटे हुए दो नाग क्षेत्रिजीय क्रम में पगड़ी के सदृश्य दृष्टव्य है. नीचे की ओर मुख किये हुए गिरगिट के पृष्ठ भाग से नासिका,अग्रपाद से नासिका रंध्र, सिर से नासाग्र तथा पिछले पैरों से भौहें निर्मित है. बड़े आकार के मेंढ़क के विस्तारित मुख से नेत्र गोलक बने हैं. छोटे आकार के प्रोष्ठीमत्स्य से मुछे तथा निचला ओष्ठ निर्मित है. बैठे हुए मयूर से कान रूपांकित है.

कंधा मकर मुख में निर्मित है, भुजाएं हाथी के सूंड के सदृश्य है तथा हाथों की उंगलियां सर्पमुखों से निर्मित है. वक्ष के दोनों स्तन तथा उदर भाग पर मानव मुख दृष्टव्य है. कच्छप के पृष्ठ से कटिभाग, मुख से शिश्न और उसके जुड़े हुए दोनों पैरों से अंडकोष निर्मित है. अंडकोष पर घंटी के सदृश्य जोंक लटके हुए हैं. दोनों जांघों पर हाथ जोड़े विद्याधर तथा कटिपार्श्व में दोनों ओर 1-1 गंधर्व की मुखाकृति है. दोनों घुटनों पर सिंहमुख अंकित है. स्थूल पैर हाथी के अगले पैर के सदृश्यहै, प्रमुख प्रतिमा के दोनों कंधों के ऊपर दो महानागपार्श्वरक्षकके सदृश्य फन फैलाए हुए स्थित है. पैरों के समीप उभयपार्श्व में गर्दन उठाकर फनफाड़े हुए नाग अनुचर दृष्टव्य है. प्रतिमा के दाएं हाथ में स्थूल दंड का खंडित भागबच रहा है. उनके हार वक्ष-बंध, कंकण तथा कटिबंध नाग तथा अधिष्ठान भाग भग्नहै. सामान्य रूप से इस प्रतिमा में शैवमत, तंत्र तथा योग के गुह्यसिद्धांतों का प्रभाव और समन्वय दिखलाई पड़ता है. उत्खनन से प्राप्त अन्य मूर्तियों में चतुर्भुज कार्तिकेय की मयूरासन प्रतिमा है जो शौर्य और उत्साह से प्रकाशित .है द्विमुखी गणेश की प्रतिमा अपने दांत को बाएं हाथ में लिए हुए चंद्रमा की ओर प्रक्षेपण के लिए उद्यत मुद्रा में है. अर्धनारीश्वर, उमा-महेश्वर, नाग पुरुष, यक्ष, मूर्तियों में अनेक पौराणिक कथानक झलकते हैं. शाल भंजिका की भग्न मूर्ति में शरीर सौष्ठव और कलात्मक सौंदर्य का संतुलित प्रयोग है. ताला न सिर्फ ऐतिहासिक पुरातात्विक दृष्टिकोण से वरन् धार्मिकशैव संप्रदाय की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थल के रूप में अपनी पहचान रखता है.

सिरपुर एक प्रेम कथा

मानव सभ्यता के विकास की कहानी पीढ़ियों के एकांतरण के जैविक सिद्धांत की पुष्टि करती है. दुनिया में चर्चित प्रेम कहानियों में कालीदास रचित दुष्यंत-शकुन्तला और अत्यंत चर्चित हीर-रांझा, लैला-मजनू, रोमियो-जूलियट, सलीम अनारकली, शाहजहॉं-मुमताज के किस्से तो सबने सुने होंगे, किन्तु आज छत्तीसगढ़ में स्थित एक अनूठे प्रेम की निशानी जिसका जिक्र न तो भारतीय सिनेमा में हुआ है और न ही किसी कलमकार ने उसे अपनी लेखनी से विश्व पटल पर लाने का कार्य किया है.

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

छत्तीसगढ़ के महासमुन्द जिले में महानदी के तट पर स्थित ऐसे रमणीक स्थल को सर्वप्रथम सेन्ट्रल प्रोविन्स एंड बरार के राजस्व आयुक्त ने 14 नवंबर 1906 के राजपत्र में पुरातात्विक महत्व के क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया और पता लगा कि वहाँ भी मोहन जोदड़ो एवं हड़प्पा, मेसोपोटामिया की तरह एक प्राचीन मानव सभ्यता के अवशेष लंबित हैं. उसके बाद से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई से मानव सभ्यता के अनेक रहस्य उजागर होने के साथ ही अब भी तीन चौथाई रहस्य अनसुलझे ही हैं. अब तक उजागर रहस्यों में सिरपुर क्षेत्र में छठवीं शताब्दी की एक अनूठी प्रेम कहानी का सबूत सामने आया है और वह प्रेम की निशानी है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर.

लक्ष्मण मंदिर सिरपुर को अनूठा कहने का कारण है कि यह अन्य प्रेम कहानियों की तरह प्रेमियों के व्दारा अपनी प्रेयसी के लिए किये गये प्रेम के प्रदर्शन की कहानी न होकर इकलौती गाथा है जिसमें प्रेयसी ने अपने प्रेमी की याद में इसका निर्माण कराया था. कहते हैं तत्कालीन दक्षिण कौशल के राजा सोमवंश के राजा हर्षगुप्त का विवाह मगध नरेश सूर्यवर्मा की पुत्री राजकुमारी वसाटादेवी से हुआ था और उनके दो पुत्र रामेश्वर एवं लक्ष्मणेश्वर थे. हर्षगुप्त शैव मत के थे जबकि वसाटा वैष्णव मत की. दोनों में अगाध प्रेम था और हर्षवर्धन की मृत्यु ने वसाटा के मन में असहनीय वेदना भर दी थी जिसके निवारण के लिए दोनों के प्रेम से उत्पन्न पुत्रों के नाम पर उसने हर्षवर्धन की याद को चिरस्थायी बनाने के लिए क्रमशः राम और लक्ष्मण मंदिरों का निर्माण कराया था, जो 12 शताब्दी के भूकंप और 14 वीं, 15वीं शताब्दी में महानदी के विनाशकारी बाढ़ में जमींदोज हो गये थे किन्तु वसाटा देवी के अक्षुण्ण प्रेम की यह निशानी लक्ष्मण मंदिर पुरात्त्व विभाग की 20वीं सदी के अंत में की गई खुदाई में 1500 सालों के बाद भी पूरी तरह सही सलामत प्राप्त हुई है. इस मंदिर का निर्माण सन् 525 से 540 के मध्य हुआ है. नागर शैली में, दुनिया के इकलौते लाल ईंटों से बने लक्ष्मण मंदिर को एक हिन्दू मंदिर के साथ ही नारी के मौन प्रेम की अद्भुत निशानी के रुप में भी जाना जाता है. यदि प्रेम को प्रदर्शित करने वाले 500 साल पुराने ताजमहल को, जिसे कि विदेशों से लाये संगमरमर के पत्थ्रों को तराशकर श्वेत शीतल प्रेम की निशानी माना जा सकता है तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर प्रेम की तपन को दर्शाने वाले लाल ईंटों से बना एवं 1500 सालों से टिका मजबूत और गहरे प्रेम का प्रतीक है. इतिहास में इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती बल्कि यह सबसे पुराने प्रेम की निशानी के तौर पर एक वास्तविकता है.

लाल ईंटों से बना यह मंदिर अद्भुत इसलिए भी है कि ईंटों पर नक्काशी का दूसरा नमूना दुनिया में कोई और नहीं है, जहां पत्थरों पर भी ऐसी नक्काशी देखने को मिलती हो. लक्ष्मण मंदिर में एक गर्भगृह, अंतराल और मंडप भी हैं साथ ही मंदिर का तोरण और उसमें शेष शैय्या पर लेटे हुए भगवान विष्णु और उनके नाभि से ब्रम्हाजी के उद्भव को बेहद करीने से उकेरा गया है साथ ही भगवान विष्णु के चरणों में माता लक्ष्मी विराजमान है. मंदिर के भीतर भगवान विष्णु के दशावतारों को चित्रित किया गया है. गर्भगृह में पाँच फन वाले शेषनाग पर विराजमान लक्ष्मण की प्रतिमा स्थापित है.

रेलवे के बिलासपुर संभाग मुख्यालय ने बस्तर को कभी भी उसका हक नहीं दिया. किसी तरह ओड़ीशा होकर दुर्ग-जगदलपुर तक एक इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाई गई तो उसे भी घाटा दिखाकर बंद कर दिया गया. जबकि इसी रूट पर 11 कंपनियों की 65 बसें प्रतिदिन दुगने-तिगुने किराए पर सवारी ढो रही है. दरअसल, इस ट्रेन की टाइमिंग यात्रियों को सूट नहीं करती थी जिसे ठीक करने की जरूरत थी. इस ट्रेन को पुन: चलाने के लिए पूर्व मंत्री केदार कश्यप तथा पूर्व विधायक संतोष बाफना ने नए सिरे से प्रयास शुरू कर दिये हैं.

बसों से आधा किराया फिर भी दुर्ग-जगदलपुर इंटरसिटी फेल

गलत टाइमिंग के कारण नहीं मिले यात्री

रेल संभाग मुख्यालय ने नहीं ली दिलचस्पी

इस रूट पर चलती हैं 65 लक्जरी बसें

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

रेलवे का बिलासपुर जोन सबसे कमाऊ जोन माना जाता है. पर छत्तीसगढ के सबसे पिछड़े क्षेत्र बस्तर के साथ वह न्याय नहीं कर पा रहा है. जगदलपुर-दुर्ग इंटरसिटी एक्सप्रेस के पहिए पिछले चार साल से बंद हैं पर रेल संभाग को इसकी सुध लेने की फुर्सत नहीं है. इसके कारण बस्तरवासियों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है.

दुर्ग से जगदलपुर के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस 10 अक्टूबर 2012 को शुरु हुई थी. पहले इस ट्रेन का जगदलपुर से छूटने का समय शाम चार बजे था. जिसे एकाएक बदल कर दोपहर साढ़े बारह बजे कर दिया गया. यह ट्रेन दोपहर 12.30 बजे जगदलपुर से छूटकर सुबह चार बजे दुर्ग पहुंचती थी. ये दोनों ही टाइम रेल यात्रियों के लिए असुविधाजनक थी.

लगभग 16 घंटे की इस यात्रा के लिए यात्री चाहते थे कि इस ट्रेन का टाइम जगदलपुर और दुर्ग दोनों ही स्टेशनों से संध्या 7 बजे रखी जाए. इसका यह लाभ होता कि लोग रात का यह सफर सोकर निकाल लेते और सुबह आठ-नौ बजे तक रायपुर पहुंच जाते. दुर्ग-पुरी इंटरसिटी की सफलता के पीछे भी यही फार्मूला काम करता है.

वैसे भी इंटरसिटी एक्सप्रेस कभी नियमित रूप से नहीं चली. कभी रायगड़ा में ट्रेक की मरम्मत तो कभी ओडिशा में नक्सली उत्पात के नाम पर इसके पहिये थमते रहे. हद तो तब हो गई, जब रायगड़ा रूट की तरफ एक रेल पुल के क्षतिग्रस्त होने पर कई महीनों के लिए इस ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया. कोरोना काल में फरवरी 2019 में इस ट्रेन को बंद कर दिया गया जो आज तक बंद पड़ी है. पूरे चार साल से यह ट्रेन जगदलपुर नहीं आ रही है.

दिल्ली गया प्रतिनिधिमंडल

पूर्व मंत्री केदार कश्यप तथा पूर्व विधायक संतोष बाफना दिल्ली प्रवास पर हैं. वे जगदलपुर - दुर्ग इंटरसिटी एक्सप्रेस को नई समय सारणी के साथ शुरू करने केंद्रीय रेल मंत्री से व्यापक चर्चा करेंगे. आशा है रेल मंत्री बस्तर की परिवहन समस्या और यहां के रहवासियों की भावना को समझेंगे.

दिया फायदे का फार्मूला

जगदलपुर से प्रतिदिन शाम पांच बजे से रात बारह बजे के बीच रायपुर के लिए 65 बसें छूटती हैं. इंटरसिटी एक्सप्रेस संध्या 7 बजे छूटेगी तो इनमें से कम से कम दस बसों के चार सौ यात्री इंटरसिटी एक्सप्रेस से यात्रा करना पसंद करेंगे. बस्तरवासियों का यह भी कहना है कि रेलवे दो-तीन महीना इस ट्रेन को संध्या 7 बजे चलाकर देखे, फिर भी यात्री न मिले तो इस ट्रेन का परिचालन बंद कर दे. ऐसा ही प्रयोग जगदलपुर से विशाखापट्टनम नाइट एक्सप्रेस के साथ किया गया जो सफल रहा. इस ट्रेन को अच्छा प्रतिसाद मिला और रेलवे ने इसे अब नियमित कर दिया है.

इसी रूट पर लाभ में चल रही बसें

बिलासपुर रेलवे जोन ने इस ट्रेन से मात्र 15 फ़ीसदी आय को कारण बताकर इसका परिचालन अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया है. जबकि हकीकत यह है कि जगदलपुर से दुर्ग के मध्य 11 कंपनियों की 65 बसें चलती हैं. इन सभी बसों का किराया अलग-अलग है. जगदलपुर से रायपुर का किराया 600 लेकर 735 रुपये तक है जबकि इंटरसिटी एक्सप्रेस में रायपुर का प्रति स्लीपर किराया मात्र 340 रुपये था. वहीं दिव्यांग और सीनियर सिटीजनों को विशेष रियायत दी जाती थी जबकि बस वाले किसी को कोई रियायत नहीं देते. ऊपर से एक स्लीपर में दो लोगो को जगह देकर 1500 रुपये तक वसूलते हैं.

सार्वजनिक जीवन का अर्धशतक

विद्यारतन भसीन

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

पचास साल की राजनीतिक यात्रा के बाद वरिष्ठ नेता विद्यारतन भसीन ने अंतिम विदाई ले ली. भिलाई, विशेषकर वैशाली नगर विधानसभा के निवासियों ने सजल नेत्रों से अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई दी. श्री भसीन ने भारतीय जनसंघ से अपना सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया था. भाजपा के संगठन में विभिन्न पदों पर रहे श्री भसीन भिलाई के एकमात्र भाजपा समर्थित महापौर भी रहे. सम्प्रति वे वैशालीनगर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. वे इस सीट से दो बार विजयी हुए थे.

श्री भसीन की लोकप्रियता और सज्जनता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब भाजपा विरोधी लहर के चलते उसके अधिकांश प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा था, तब भी विद्यारतन भसीन हजारों मतों के अंतर से वैशाली नगर सीट पर विजयी हुए. इस चुनाव में भाजपा ने न केवल बहुमत की सत्ता गंवाई बल्कि उसके विधायकों की संख्या सिमट कर 15 पर आ गई.

अपने लंबे राजनीतिक सफर में बतौर महापौर और विधायक उन्होंने अपने कार्य एवं व्यवहार से जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में सफलता प्राप्त की. सहज व सरल व्यक्तित्व के धनी श्री भसीन को चुनाव प्रबंधन का भी विशेषज्ञ कहा जाता था. वे नगरीय चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव परिणामों की जानकारी निर्वाचन कार्यालय से लेकर उसका गहन अध्ययन करते थे. विभिन्न वर्गों की संख्या, उनके प्रमुख व्यवसाय एवं सामाजिक स्थिति के साथ ही बदलते राजनीतिक परिवेश पर उनकी पैनी नजर होती थी. श्री भसीन अपनी पार्टी के अलावा अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों के संगठन और उनकी गतिविधियों की भी पुख्ता जानकारी रखते थे. इसीके आधार पर वे अपने संगठन की मजबूती सुनिश्चित करते थे. चुनाव में कौन सा कार्यकर्ता या नेता किस क्षेत्र में और किस कार्य में अधिक अच्छा परिणाम दे सकता है, इसकी उन्हें खूब परख थी. मित एवं मृदुभाषी श्री भसीन न केवल आम जनता के बीच बल्कि अन्य दलों के नेताओं में भी काफी लोकप्रिय थे.

22-23 जून की दरम्यानी रात रामकृष्ण केयर अस्पताल, रायपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली. श्री भसीन को श्रद्धांजलि देने सभी प्रमुख दलों के नेता और कार्यकर्ता उनके निवास पर पहुंचे. कांग्रेस और भाजपा के प्रदेशाध्यक्षों ने उनके अंतिम संस्कार में उपस्थिति दी. यह पहला मौका था जब रामनगर मुक्तिधाम में किसी को गार्ड ऑफ ऑनर ने सलामी दी क्योंकि उनका निधन विधायक कार्यकाल के दौरान हुआ.

स्व. भसीन को श्रद्धांजलि देने वालों में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह, भाजपा के अध्यक्ष अरुण साव, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, सांसद विजय बघेल, सुनील सोनी, सरोज पांडे, कांग्रेस विधायक अरूण वोरा, देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक एवं मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, रमशीला साहू, जागेश्वर साहू, अजय चंद्राकर, विधायक शिवरतन शर्मा, पूर्व विधायक डॉ. दयाराम साहू, पूर्व महापौर नीता लोधी, चंद्रकांता मांडले, निर्मला यादव, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी संस्था की संचालिका आशा बहन, छत्तीसगढ़ चेंबर एंड कॉमर्स के महामंत्री अजय भसीन, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, जिला भाजपा अध्यक्ष बृजेश बिचपुरिया, जिला भाजपा प्रभारी संदीप शर्मा, वरिष्ठ नेता प्रभुनाथ मिश्रा, शंकर लाल देवांगन, प्रीतपाल बेलचंदन, भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल सहित हजारों की संख्या में नागरिक गण उपस्थित थे.

छत्तीसगढ़ आजतक की ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि.

भसीन के नाम पर सड़क

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि देने के साथ ही उनकी स्मृति को संजोने के लिए एमआर-9 रोड को उनके नाम पर कर दिया है. यह रोड जामुल बोगदा पुलिया से शुरू होकर कातुलबोर्ड तक जाती है. 2018 में इस सड़क का निर्माण लगभग 49,50,00,000 से पूरा किया गया. मुख्यमंत्री ने दिवंगत विधायक के पुत्र चन्दर भसीन एवं परिवार जनों से मुलाकात के दौरान इसकी घोषणा की.

66 YEARS OLD BUT GOLD

Symbol of Trust
at ®
Since 1957

भगवान श्री जगन्नाथजी की कृपा हम सब पर बनी रहे...

एटी ज्वेलर्स ने अपने विशिष्ट कलात्मकता व उत्कृष्ट गुणवत्ता से पूरे मध्यभारत में अपनी खास पहचान बनाई है और स्थापित किया है 66 वर्षों का अटूट विश्वास जो निरंतर और भी प्रगाढ़ होता जाएगा।

अनोपचंद तिलोकचंद
ज्वेलर्स

रायपुर	रायपुर	रायपुर	बिलासपुर	कोरबा	गोंदिया
सिटी कोतवाली चौक, सदर बाजार	अनूप प्लाजा, सदर बाजार	न्यू क्लॉथ मार्केट, गेट नं. 2, पंडरी	लिंक रोड, सी.एम.डी. चौक	पावर हाउस रोड	गाँधी प्रतिमा के पास
0771-2225363	88177-10111	0771-4047111	94255-02214	9340062090	07182-232262

ATUL PUBLICITY

पूरी बिजली आधा बिल
भरपूर आपूर्ति ने जीता दिल

घरेलू बिजली पर
400 यूनिट
तक बिजली बिल हाफ

45.16 लाख
उपभोक्ता लाभान्वित

3,767 करोड़
की छूट मिली

- 17 लाख बीपीएल परिवारों के बिजली बिल में 122 करोड़ रुपये की बचत
- अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को नि:शुल्क बिजली
- 6 लाख से अधिक किसानों को सिंचाई पंपों के लिए मुफ़्त बिजली
- राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों को 80 पैसे प्रति यूनिट की छूट

पिछले चार सालों में 51 हजार से अधिक
नए ट्रांसफार्मर स्थापित

C/PDCL

मोर बिजली एप
के माध्यम से घर बैठे बिजली बिल की
पूरी जानकारी और भुगतान

छत्तीसगढ़ सरकार
भरोसे की सरकार

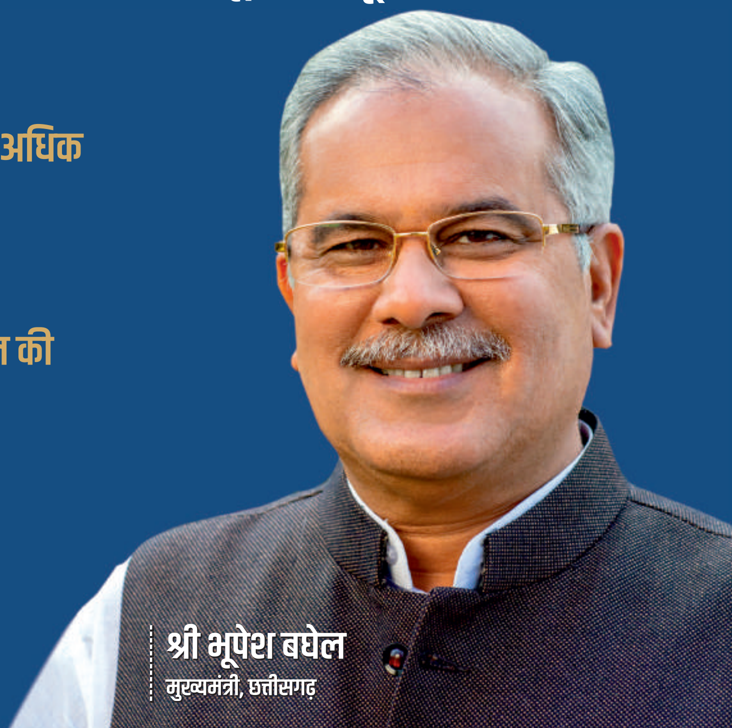

श्री भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

R.O. No. : 12464/3